RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 203
नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 मई, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

जोया मोरानी ने दूसरी बार किया प्लाज्मा डोनेट
विविध-12

नहीं ले सकते भाड़ा, करें भोजन का प्रबंध

प्रवासी मजदूरों के जख्मों पर सुप्रीम कोर्ट का मरहम

● अपने अंतरिम निर्देश में कहा-राज्य सरकार मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखें और तय करें कि उन्हें जल्द ट्रेन या बस मिले

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान लिये गये मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि देश के विभिन्न हिस्सों से अपने घर जाने के इच्छुक श्रमिकों से रेल या बस का कोई किराया नहीं लिया जायेगा। अदालत ने यह भी कहा कि श्रमिकों की यात्रा जिस राज्य से शुरू होगी उसके स्टेशन पर वही भोजन और पानी उपलब्ध कराएंगे और यात्रा के दौरान इनके भोजन-पानी की व्यवस्था रेलवे की जिम्मेदारी होगी।

शीर्ष अदालत ने विभिन्न स्थानों पर फंसे इन श्रमिकों के मामले में करीब ढाई घंटे की सुनवाई के बाद अंतरिम निर्देश दिये और कहा कि संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने यहां विभिन्न स्थानों पर फंसे कामगारों को भोजन उपलब्ध कराने के स्थान के बारे में उन्हें वहीं सूचित करेंगी जहां वह वे अपनी बारी के लिये ट्रेन या बस का इंतजार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के बाद अपने निर्देशों में कहा कि इन श्रमिकों की यात्रा जिस राज्य से शुरू होगी, वे अपने यहां के स्टेशन पर भोजन और पानी उपलब्ध करायेंगे और यात्रा के दौरान इन श्रमिकों को भोजन तथा पानी रेलवे मुहैया करायेगा। न्यायालय ने कहा कि बसों में यात्रा के दौरान भी इन कामगारों को खाना और पानी उपलब्ध कराना होगा। इस मामले में न्यायालय अब पांच जून को आगे विचार करेगा। पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था देखें और यह सुनिश्चित करें कि ये कामगार अपने गंतव्य के लिये जल्द से जल्द ट्रेनों या बसों में सवार हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी सभी संबंधित प्राधिकारियों के लिये प्रकाशित की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि इस समय उसकी चिंता इन प्रवासी मजदूरों की तकलीफों और परेशानियों को लेकर है जो जल्द से जल्द अपने अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंधित राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश आवश्यक कदम उठा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी कामगारों के यात्रा के पंजीकरण, उन्हें घर भेजने तथा उनके खाने-पीने के बंदोबस्त में अनेक कमियां पायी गयी हैं।

पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का भी संज्ञान लिया कि राज्य सरकारों को यह निर्देश दिये गये हैं कि सड़कों पर पैदल ही चल रहे कामगारों को बस या दूसरे वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। पीठ ने कहा कि सड़कों पर पैदल ही जा रहा कोई भी कामगार दिखाई पड़ने पर उसे तत्काल आवास शिविर में पहुंचाया जाये और उसके लिये भोजन तथा दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस समय इन कामगारों की दुर्दशा को देखते हुये तत्काल ही कुछ अंतरिम निर्देश देने की आवश्यकता है।

कोविड-19 महामारी की वजह से चार घंटे की नोटिस पर 25 मार्च से देश में लागू लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों भूखे प्यासे श्रमिक विभिन्न जगहों पर फंस गये। उनके पास ठहरने की भी सुविधा नहीं थी। इन श्रमिकों ने आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से पैदल ही अपने-अपने घर की ओर कूच कर दिया था जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गयी थी। न्यायालय ने कहा कि इन प्रवासी कामगारों की संख्या, इन्हें भेजने की योजना, इनके पंजीकरण के तरीके और दूसरी संबंधित जानकारियों का विवरण रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि रेलवे को राज्य सरकार के अनुरोध पर उसे ट्रेन उपलब्ध करानी होगी। न्यायालय ने इस मामले को पांच जून के लिये सूचीबद्ध करते हुये कहा कि केन्द्र और कुछ राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों ने नोटिस पर अपने जवाब दाखिल किये हैं। पीठ ने सॉलिसीटर जनरल द्वारा केन्द्र की ओर से दी गयी इस दलील का भी संज्ञान लिया कि एक से 27 मई के दौरान इन कामगारों को ले जाने के लिये कुल 3,700 विशेष ट्रेन चलायी गयी और सीमावर्ती राज्यों में अनेक कामगारों को सड़क मार्ग से पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि बुधवार तक करीब 91 लाख प्रवासी कामगारों को उनके पैतृक घरों तक पहुंचाया गया है।

मेहता ने पीठ से कहा कि ये कामगार जब अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं तो संबंधित राज्य सरकार उनके पृथकवास और स्क्रीनिंग करने जैसी आवश्यकताओं को देखती है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने अपने यहां राहत शिविर बनाये हैं जहां प्रवासी कामगारों को खाना और दूसरी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। उन्होंने यह (शेष पेज 9)

अमृतसर में बस के इंतजार में अपने गांव जाने के लिए बैठे प्रवासी श्रमिक

अदालत ने दिए ये आदेश

1. ट्रेन और बस से सफर कर रहे मजदूरों से किराया न लिया जाए। यह खर्च राज्य सरकारें उठाएं।
2. स्टेशनों पर खाना और पानी राज्य सरकारें मुहैया करवाएं और ट्रेनों में मजदूरों के लिए यह व्यवस्था रेलवे करे।
3. जो मजदूर घर जाने के लिए बसों और ट्रेनों के इंतजार में हैं, उन्हें खाना राज्य सरकारें ही मुहैया करवाएं।
4. मजदूरों को खाना कहां मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहां होगा। इसकी जानकारी प्रसारित की जाए।

चीन से सुलह में ट्रंप की पेशकश को भारत की ना

● शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्ष के बीच चल रही है बातचीत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

'**बढ़ते** सीमा विवाद' को लेकर भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को नई दिल्ली ने गुरुवार को एक तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए चीनी पक्ष के साथ बातचीत चल रही है। भारत के रुख साफ करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली और बीजिंग दोनों जगहों पर इस मुद्दे पर राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है।'

उन्होंने कहा कि भारत और चीन सैन्य तथा राजनयिक दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरिता को बरकरार रखने के लिए कई प्रोटोकाल पर दस्तखत किए है। इस मुद्दे पर कई समझौते हुए हैं। उन्होंने कहा 'हमारी सेना सीमा प्रबंधन पर बेहद जिम्मेदार रवैया रखती है और प्रोटोकॉल का पालन करती है। वह हमारे नेतृत्व द्वारा दिए दिशानिर्देशों का पूरा पालन करती है।' ट्रंप ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा था, "हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका उनके इस समय जोर पकड़ रहे सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। इस बात की ओर इशारा करते हुए कि एलएसी विवाद द्विपक्षीय है और इसमें किसी तीसरे पक्ष के दखल जरूरत नहीं, भारत ने यह भी कहा कि दोनों देशों (भारत और चीन) ने शांति कायम रखने के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यवस्था बना रखी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि स्थानीय सैन्य स्तर पर दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच भी बातचीत जारी है। वस्तुत: एक पखवाड़े में दोनों पक्षों के बीच सात दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक यह बेनतीजा ही रही है।

पूर्वी लद्दाख में पिछले 25 दिनों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच चार स्थानों पर झड़प हो चुकी है। चीनी गलवान घाटी के हॉट स्प्रिंग इलाके में घुसपैठ की थी और यहां पर उसके 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। चीनी सेना गलवान घाटी में एलएसी के समानांतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 250 किलोमीटर लंबी रोड पर पुल के निर्माण पर एतराज जता रही है। लेकिन भारत का कहना है कि यह सड़क उसकी सीमा में हैं और वह किसी भी प्रकार से एलएसी का उल्लंघन नहीं कर रहा है। चीन ने एलएसी के बराबर में अपनी सीमा में बंकरों का (शेष पेज 9)

अनुराग श्रीवास्तव

केंद्रीय कर्मचारी नहीं कर सकेंगे साथ में लंच, मटरगश्ती भी बंद

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

● सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, सेंट्रल एसी सिस्टम के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, करना होगा अलग-अलग द्वारों से प्रवेश

अगले कुछ महीनों तक न कोई सामूहिक लंच होगा, न तो कार्यालयों में केवल एक द्वार से प्रवेश की इजाजत होगी और न ही शास्त्री भवन, कृषि भवन, रेल भवन, उद्योग भवन, सेना भवन और निर्माण भवन आदि के कॉरीडोरों में मटरगश्ती की जा सकेगी। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल भी वर्जित होगा।

ये दिशा निर्देश कोविड 19 संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के खत्म होने या फिर और ढील के साथ जारी रहने पर तब प्रभावी होंगे जब सरकारी विभागों में शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ कामकाज शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरूवार को नए दिशा निर्देश जारी कर कहा कि यदि संभव हुआ तो केंद्रीकृत वातानुकूलित प्रणाली का इस्तेमाल कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

गाइडलाइन में कर्मचारियों को बिल्डिंग के विभिन्न द्वारों से अलग-अलग प्रवेश करने, सीढ़ियों का इस्तेमाल करने और लिफ्ट का प्रयोग करने की स्थिति में छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करने की सलाह दी गई है। लिफ्ट में एक साथ सिर्फ चार लोग मौजूद रहें और बातचीत न करते हुए अपने-अपने मुंह दीवार की ओर रखने का प्रयत्न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा (शेष पेज 9)

केंद्र पर आक्रामक सोनिया ने छेड़ी स्पीक अप इंडिया मुहिम

● प्रवासी मजदूरों-गरीबों की आवाज उठाने के लिए ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर एक साथ किया लांच

● राहुल, प्रियंका और चिदंबरम ने भी मैसेज पोस्ट कर मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने और उनकी मदद के लिए जन समर्थन जुटाने के मकसद से कांग्रेस ने

गुरूवार को सोशल मीडिया पर स्पीक अप इंडिया नाम से व्यापक मुहिम छेड़ दी है।

केंद्र सरकार पर लाखों असहाय श्रमिकों की त्रासदी के प्रति आंखें मूंद लेने का आरोप लगाती कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी की यह मुहिम अशक्त और निर्बल लोगों के लिए आवाज उठाने का मंच बनेगी। स्पीक अप इंडिया एक (शेष पेज 9)

कांग्रेस देश की चुनौतियों से लाभ लेने की कोशिश में: भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर देश के सामने मौजूद चुनौतियों से फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी दल ऐसे समय में राजनीतिक दोषारोपण में लिप्त है जो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन उससे अपेक्षित भी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मोदी सरकार (शेष पेज 9)

पुलवामा पार्ट 2 की नापाक साजिश ध्वस्त

दिलेर जवानों ने विस्फोटक से लदी कार के उड़ाए परखच्चे

मोहित कंधारी। जम्मू

● आतंकियों के निशाने पर थे दर्जनों वाहन, सैकड़ों सैनिक

पुलवामा-2 दोहराने की आतंकियों की साजिश को दिलेर जवानों ने नाकाम कर दिया है। खुफिया एजेंसियों की सहायता से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने पुलवामा में दो साल पहले सीआरपीएफ काफिले पर किए गए कार बम हमले की तरह ही रची गई सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश को अपनी जांबाजी से विस्फोट कर उड़ा दिया।

यहां पुलवामा जिले के राजपोरा के अयेंगुंड इलाके में सुनसान जगह पर कम से कम 40 से 45 किलोग्राम विस्फोटक से लदी कार खड़ी थी। कार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से लैस थी जिसका समय पर पता लगाकर आतंकियों के इरादे धुआं-धुआं कर दिए गए। पुलिस को इस घटना में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के साथ हिजबुल मुजाहिदीन के स्थानीय कमांडरों का हाथ होने का षक है, जो कष्मीर घाटी में सैन्य ऑपरेशन के दौरान रियाज नायको और जुनैद सेहराई सहित अपने अन्य शीर्ष कमांडरों की हालिया हत्याओं का बदला लेने की फिराक में है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विस्फोटक से लदी नकली पंजीकरण संख्या जेके 08बी-1426 वाली कार को गुरुवार सुबह बम डिस्पोजल दस्ते द्वारा विस्फोट कर ध्वस्त किया गया। इससे क्षेत्र में स्थानीय घरों के खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। कार में विस्फोट करने से पहले बुधवार देर रात ही निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को (शेष पेज 9)

दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1,024 मामले

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के एक दिन में सबसे अधिक 1,024 मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 16 हजार के पार पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या 316 हो गई है। इससे पहले बुधवार को एक दिन में सबसे अधिक 792 मामले सामने आए थे। ऐसा पहली बार है कि दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के एक हजार से अधिक मामले सामने आए है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बुलेटिन में कहा कि कोविड-19 से मृतकों की संख्या बढ़कर 316 हो गई है और मामलों की संख्या 16,281 हो गई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 15,257 थी जिनमें 303 लोगों की मौत के मामले भी शामिल थे। दूसरी ओर केंद्रीय (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	32,200	↑ 595
निफ्टी	9,490	↑ 175
सोना		/10g
चांदी		/kg

क्विक न्यूज

विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि बढ़ी

नई दिल्ली। रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेनें और एक जून से चलने जा रही 100 जोड़ी नई ट्रेनें शामिल है। रेलवे ने एक बयान में कहा, रेल मंत्रालय ने सभी विशेष ट्रेनों की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। बयान मे कहा गया है कि वर्तमान बुकिंग, रोडसाइड स्टेशनों के लिए सीटों का तत्काल कोटा आवंटन और अन्य नियम एवं शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।

संबित पात्रा को कोरोना की आशंका, अस्पताल में

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

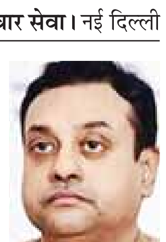

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर संबित पात्रा के जल्द ठीक होने की कामना की है। पेशे से डॉक्टर संबित पात्रा हिंदू राव हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा की पुरी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। टीवी डिबेट का चर्चित चेहरा संबित लंबे समय से भाजपा के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा के (शेष पेज 9)

सात राज्यों पर मंडरा रहीं टिड्डियां, मचा कोहराम

राजेश कुमार। नई दिल्ली

● लगभग 45 से 50 जिलों में किसानों को चिंता में डाला

● केंद्र ने जारी की एडवायजरी, छिड़काव के इंतजाम

पिछले साल पाकिस्तान से आए करोड़ों रेगिस्तानी टिड्डियों के दल ने छह राज्यों राजस्थान व गुजरात के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के लगभग 45 से 50 जिलों में कोहराम बचा दिया है। अनुमान है कि पिछले साल दिसंबर से अब तक छह राज्यों में 10-15 लाख एकड़ फसलें प्रभावित हुई हैं, जबकि सरकार का मानना है कि अब तक लगभग एक लाख एकड़ कपास, ग्रीष्मकालीन दलहन और सब्जियों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि ज्यादातर इलाकों में बुआई नहीं हुई है और रबी की फसलें कट चुकी हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार नुकसान के सर्वेक्षण के बाद टिड्डे के झुंड के हमलों को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की योजना बना रही है। हरियाणा ने गुरुवार को किसानों के लिए 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने भी किसानों को दिषा निर्देष जारी किए हैं। दिल्ली और इसके पड़ोसी क्षेत्र नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम ने भी इस संबंध में जरूरी सलाह जारी की है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ टिड्डी मुद्दे को उठाया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कृषि मंत्रालय के टिड्डी वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बड़ी समस्या उस समय खड़ी हो सकती है जब टिड्डियां अंडे देंगी और नए दल आसमान में छाएंगे। लोकस्ट वॉर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर केएल गुर्जर ने कहा कि एक वयस्क मादा टिड्डी अपने तीन महीने के जीवन चक्र में (शेष पेज 9)

मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खेतों के ऊपर से उड़ता टिड्डियों का झुंड

टिड्डी दल का कहां-कहां प्रभाव

टिड्डी हमले के कारण राजस्थान के 20 जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। श्रीगंगानगर में 4,000 हेक्टेयर और नागौर में 100 हेक्टेयर में फसल नष्ट हो गई है। यहां श्री गंगानगर, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और स्वाई माधोपुर में अधिकारियों द्वारा छिड़काव और अन्य उपाय किए जाने के बाद टिड्डी दल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर गए हैं। राजस्थान के कृषि विभाग के आयुक्त डॉ. ओम प्रकाश चौधरी के अनुसार, जयपुर में टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हरियाणा ने सात जिलों- सरसा, फ्तेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में अलर्ट जारी किया है। मप्र में जबलपुर में किसानों ने टिड्डों पर हमला करने से बचने के लिए पानी के टैंकरों और रसायनों के छिड़काव की व्यवस्था की है। इसके अलावा, सीहोर जिले में किसान बर्तन पीट रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में टिड्डियों को भी देखा गया है, जहां उन्होंने जंगली पौधों और पेड़ों पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में टिड्डियों के झुंड ने प्रवेश किया है। महाराष्ट्र के नागपुर और वर्धा जिलों में नारंगी और बागवानी फसलों को टिड्डी दल ने नुकसान पहुंचाया है। ये दल गुरुवार दोपहर पूर्वी महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में प्रवेष कर गए।

विपक्ष और किसानों के दबाव में सरकार का यू-टर्न

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

अब किसानों पर सख्ती नहीं केवल सलाह

योजना का स्वरूप बदला, एक दर्जन नए ब्लाक शामिल

अब पंचायतों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

मामला सात जिलों में धान की रोपाई पर रोक लगाने का

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के आठ ब्लाकों में धान की रोपाई पर रोक लगाए जाने के फैसले का चौतरफा विरोध होने के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब सरकार ने इन ब्लाकों के किसानों के साथ सख्ती का व्यवहार छोड़ते हुए केवल इन्हें वैकल्पिक खेती को अपनाने की सलाह दी है। यही नहीं सरकार ने पहले से लागू की गई योजना का विस्तार करते हुए इसमें 12 नए ब्लाकों को शामिल करके धान की रोपाई रोकने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। पिछले दो वर्षों से हरियाणा में धान की फसल सरकार के गले की फांस बनी हुई है। किसानों को धान की फसल से अलग करने के लिए सरकार की सभी योजनाएं विफल साबित हो रही हैं। इस साल सरकार द्वारा मई माह के दौरान 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना लागू की थी। इसे लेकर पूरे प्रदेश में सरकार का विरोध हो रहा है।

किसान संगठन जहां एकजुट हो रहे हैं वहीं विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा तथा रणदीप सुरजेवाला प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चौतरफा विरोध के चलते सरकार ने अब इस योजना को बदल दिया है। पहले जहां रतिया,सिवान, गुहला, पिपली, शाहबाद, बबैन, इस्माईलाबाद व सिरसा में धान की रोपाई पर रोक लगाई थी वहीं अब सरकार ने किसानों के प्रति सख्ती का मूढ़ त्यागते हुए केवल उन्हें वैकल्पिक फसलों को अपनाने की सलाह दी है। सरकार ने हरियाणा में फसल विविधकरण के लिए तय किए गए लक्ष्य को भी त्याग दिया है। अब इन ब्लाकों में अगर कोई किसान 50 प्रतिशत से अधिक हिस्से में धान की रोपाई करता है तो भी सरकार उसकी खरीद करेगी।

क्या थी पहले सरकार की योजना

हरियाणा के रतिया,सिवान, गुहला, पिपली, शाहबाद, बबैन, इस्माईलाबाद व सिरसा में पंचायती जमीन को पट्टे पर लेकर धान की रोपाई पर रोक लगाई थी। इसके 50 हार्स पावर की मोटर वाले किसानों के लिए धान की खेती पर रोक लगाई गई थी। फसल विविधिकरण अपनाने वाले किसानों को सात हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देने का फैसला।

अब क्या है योजना

सरकार ने पहले लागू की योजना में सख्त शब्दावली को हटाते हुए जहां केवल सलाह दी है वहीं अब नई योजना के तहत रतिया, फतेहाबाद, जाखल, सिवान, गुहला, पिपली, शाहबाद, बबैन, इस्माईलाबाद, थानेसर, पेहवा तथा सिरसा को उन ब्लाकों में शामिल किया है जहां जलस्तर 35 मीटर से अधिक है। इन ग्राम पंचायतों की कृषि योग्य भूमि पर धान की खेती नहीं की जाएगी। ऐसी पंचायतों को सरकार ने साढे सात हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने का ऐलान किया है।

हरियाणा : आधा दर्जन विधायकों ने अफसरों के खिलाफ खोला मोर्चा

स्पीकर के पास धड़ाधड़ आ रही सुनवाई न करने की शिकायतें

विधानसभा सचिवालय ने कई को जारी किए नोटिस

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के अधिकारियों द्वारा विधायकों की सुनवाई न किए जाने का मुद्दा और गहरा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और गृहमंत्री अनिल विज द्वारा विधायकों की पीठ थपथपाए जाने के बाद विधायकों ने अफसरों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा दिया है।

हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने जब वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विधायकों की बैठक ली तो लगभग सभी विधायकों ने अधिकारियों द्वारा अनेदखी किए जाने का मुद्दा उठाया। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों से मिले फीडबैक के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत कराया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस बीच विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय में अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायतें दी जा रही हैं। कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने रेवाड़ी की एसपी नाजनीन भसीन के तबादले की मांग करते हुए कहा है कि एसपी उनका फोन नहीं उठाती हैं। जिससे डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी बल मिल रहा है। असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने अपने क्षेत्र के एसडीएम अनुराग डालिया के विरुद्ध शिकायत दी है।

सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त और एडीसी के विरुद्ध फोन न उठाने, जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता न देने की शिकायत दी है। इसके अलावा अन्य कई विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारियों के विरुद्ध विधानसभा स्पीकर को शिकायत दी है। इनमें ज्यादातर शिकायतें एसपी, एसडीएम और एसडीओ स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध है।

सीएमओ ने जारी किए अधिकारियों को निर्देश

हरियाणा में पिछले कई दिनों से नौकरशाहों द्वारा जनप्रतिनिधियों की अनदेखी किए जाने का मुद्दा गर्माया हुआ है। विधायकों की नाराजगी का मुद्दा स्पीकर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाया था। जिसके बाद सीएम ने अपने प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को जिलों के अधिकारियों को हिदायतें जारी करने के आदेश दिए थे। खुल्लर ने भी हाथों-हाथ इस इस बारे में राजनीतिक और संसदीय मामले विभाग को निर्देश दिए। प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, डीसी-एसपी के अलावा एडीसी, एसडीएम, नगर निगमों के आयुक्तों और जिला परिषद के सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) को लिखित में आदेश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के अलावा सभी विधायकों को पूरा मान-सम्मान देना होगा। इन जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर जिले के अधिकारियों को अपने फोन में सेव करने होंगे ताकि वे तुरंत फोन उठा सकें। अगर किसी कारण से फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो मैसेज करके रिप्लाई करना होगा। बाद में फोन करना होगा। अगर सांसद या विधायक फोन नहीं उठाते तो उन्हें मैसेज करना होगा।

मास्क न पहनने पर 8 लोगों का उपायुक्त ने किया चालान

500 रुपये के हिसाब से जुर्माना वसूला

करनाल। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले लोगों को 500 रुपये का जुर्माना लगाने की अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई है।

उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने वीरवार को शहर के मुख्य बाजार में स्थित महर्षि वाल्मिकी चौक पर पहुंचकर स्वयं 8 लोगों का चालान किया और उनसे 500 रूपये के हिसाब से जुर्माना वसूल किया और उन्हें मास्क वितरित करके इसका प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर एसडीएम करनाल नरेन्द्र पाल मलिक व एसीयूटी आयुष सिन्हा और एसएचओ हरजिन्द्र सिंह उपस्थित रहे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं करेंगे तथा सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर थूकने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किए हैं।

मोदी पार्ट टू की उपलब्धियां घर-घर पहुंचाएगी भाजपा

सीएम व भाजपा प्रभारी की अध्यक्षता में हुई बैठक

चंडीगढ़। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर पार्टी द्वारा हरियाणा में डिजिटल प्लेटफार्म पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हरियाणा के बीस लाख घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और हरियाणा के सभी सांसदों, केन्द्रीय मंत्रियों, प्रदेश मंत्री और विधायकों समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।

बैठक में फैसला लिया कि भाजपा इस एक साल के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम से एक जागरुकता अभियान चलाएगी। एक साल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए भाजपा कार्यकर्ता 20 लाख परिवारों से संपर्क करेंगे। मोदी सरकार की एक साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम व्यक्तिगत संपर्क माध्यम वर्चुअल माध्यम और मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता से संपर्क किया जाएगा।

हरियाणा प्रदेश में इसके लिए व्यक्तिगत संपर्क की जिम्मेवारी प्रदेश महामंत्री और सांसद संजय भाटिया को, डिजिटल संपर्क की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को, वर्चुअल संपर्क की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री वेदपाल एडवोकेट और मीडिया के माध्यम से प्रेस कांफ्रेंस व संपर्क की जिम्मेदारी प्रदेश सह मीडिया प्रमुख रणदीप घनगस को दी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन की टीम ने चिकित्सकों को किया सम्मानित

पायनियर समाचार सेवा। करनाल

कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन में मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों, चिकित्सा सहायकों व अन्य लोगों का वीरवार को स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन सुभाष चन्द्र व उनकी टीम ने फूल बरसाकर अभिनंदन किया।

सुभाष चन्द्र ने इस अवसर पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सकों को पीपीई किट भी प्रदान की। इससे पूर्व सिविल सर्जन अश्वनी कुमार ने सुभाष चन्द्र को कोरोना के सम्बंध में अब तक उठाये गए कदमों की रिपोर्ट दी। सुभाष चन्द्र ने कहा कि पूरा देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है ऐसे कठिन समय में पुलिस, डॉक्टर व सफाई कर्मी कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन योद्धाओं की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह ये सब दिन-रात खुद परेशानी से जूझकर हम सब की जान बचाने में लगे हुए हैं, हम उनके उत्साह और जज्बे को सलाम करते है। हम यही कहना चाहते हैं कि पूरा देश और समाज इन योद्धाओं के साथ हमेशा खड़ा है। ये लोग ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इसके लिए हम सबको भी मिलकर खड़ा होना होगा तभी हम इसे हरा पाएंगे।

उन्होंने कहा कि डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी दिन-रात कार्य करके आम लोगों को कोरोना से बचाने का कार्य कर रहे हैं। इन्ही के प्रयासों से आज हम लोग कोरोना से बचे हुए हैं, इसलिए इन्हें सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुभाष चन्द्र ने कहा कि जो भी कोरोना से जंग में फ्रंटलाइन पर लड़ रहे हैं उन का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि करनाल में पिछले दिनों जो भी कोरोना के मरीज आये उनमें अधिकतर बाहर से आने वाले लोग थे।

कोरोना मरीज को भर्ती करने में आनाकानी करने वाले दो अस्पतालों को नोटिस

गुरुग्राम। एक तरफ तो सरकार और प्रशासन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार को लेकर खूब दावे कर रही है, लेकिन गुरुग्राम के निजी अस्पतालों पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ता।

कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती नहीं करने पर यहां के दो अस्पतालों को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गुरुग्राम के पार्क अस्पताल और पारस अस्पताल को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों अस्पतालों की तरफ से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करनें में आनाकानी की गई। इसकी शिकायत जिलाधीश एवं जिला उपायुक्त अमित खत्री तक पहुंची तो उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। गुरुवार को उन्होंने दोनों अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

गुरुग्राम से 1600 नागरिकों को ले पश्चिम बंगाल रवाना हुई पहली ट्रेन

रेलवे स्टेशन पर पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को खाने का सामान देतीं जीआरपी की महिला कर्मी व रेडक्रॉस कर्मी।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव महेश गुप्ता की भी अहम भूमिका

जीआरपी की महिला पुरुष कर्मी भी दे रहे भरपूर सहयोग

स्थानीय रेलवे स्टेशन से गुरुवार शाम 6 बजे 1600 प्रवासी नागरिकों को लेकर पश्चिम बंगाल के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल केन्यू कूच बिहार नामक क्षेत्र के लिए गई है। जाते समय ट्रेन में बैठे नागरिकों ने हाथ हिलाकर व हाथ जोड़कर आभार जताया और जय हरियाणा के नारे लगाते हुए विदा हुए।

यहां पर जीआरपी कर्मचारी व रेडक्रॉस की टीम अहम भूमिका निभा रही हैं। स्पेशल श्रमिक ट्रेन से हरियाणा के अलग-अलग जिलों से यहां लाए गए प्रवासी नागरिकों को सरकारी खर्च पर उनके गृह राज्य भिजवाया गया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1600 प्रवासी नागरिकों को बसों के माध्यम से रेलवे स्टेशन लाया गया। इनमें बिहार के विभिन्न जिलों के प्रवासी नागरिक शामिल थे।

रेलवे स्टेशन पर इन सबके स्वास्थ्य जांच की गई व हाथों को सैनेटाइज करवाकर भोजन व पानी दिया गया। प्रत्येक यात्री की थर्मल स्कैनिंग करके उन्हें मास्क उपलब्ध करवाए गए। इसके उपरांत प्रत्येक श्रमिक को टिकट नि:शुल्क देकर ट्रेन में बिठाया गया।

पूंडरी का सरकारी अस्पताल का परिसर बना वाहन पार्किग स्थल

पूंडरी। पूंडरी का सरकारी अस्पताल का परिसर मरीजों के लिए नहीं, लोगों की कार पार्किंग स्थल बना हुआ है। अस्पताल परिसर में घुसने के बाद नहीं लगता कि ये सामान्य अस्पताल है, बल्कि कोई वाहन पार्किंग नजर आती है। जिसमें हर समय 50 से 60 गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती है। ये वाहन किसी अस्पताल में आने वाले मरीजों या उनके परिजनों के नहीं होते है, बल्कि ये अस्पताल के आसपास रहने वाले व दुकानदारों के निजी वाहन होते हैं। बिना रोकटोक ये गाड़ियां यहां प्रतिदिन खड़ी की जाती हैं। इसके अलावा अस्पताल स्टाफ व बाहर से आने वाले मरीजों को अपने वाहन इधर-उधर खड़े करने पड़ते हैं। इन वाहनों को खड़ा करने से रोकने के लिए पिछले 15 वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। नोटिस तक लोगों को दिये गये, लेकिन कुछ समय के लिए खड़ा करना छोड़ते हैं, उसके बाद फिर यही सिलसिला शुरू हो जाता है। चिकित्सा अधिकारी पूंडरी डा. विकास भटनागर ने बताया कि इस बारे में जब अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से बात कि जाती है तो वे लाचारी दिखाते हुए बताते हैं कि वे क्या करें, इस बारे में 5 से 6 बार थाना प्रभारी व उच्चाधिकारियों को लिखकर अवगत करा चुके हैं।

हरियाणा में किसानों को नहीं भाई 'मेरा पानी-मेरी विरासत'

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को पारंपरिक फसलों से हटाकर वैकल्पिक फसलों के साथ जोडने् के लिए शुरू की गई 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना पहले ही चरण में दम तोड़ गई है। एक माह के भीतर महज तीन हजार किसानों ने ही वैकल्पिक फसलों के लिए पंजीकरण करवाया है। इस मुद्दे पर विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा जमकर राजनीति की जा रही है और किसानों द्वारा सरकार का खुलकर विरोध किया जा रहा है।

क्या है सरकार की योजना

हरियाणा में भूमिगत जलस्तर लगातार नीचे गिर रहा है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल 'जल ही जीवन है' नामक योजना शुरू करके किसानों को वैकल्पिक फसलों की पैदावार की तरफ मोड़ा था। सरकार को इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अब सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर 'मेरा पानी-मेरी विरासत' शुरू की है। जिसके तहत हरियाणा के आठ ब्लाकों को चिन्हित करके धान की रोपाई पर रोक लगाई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा छह मई को शुरू की गई इस योजना में किसानों को मक्का, अरहर, उड़द, ज्वार, बाजारा, तिल व कपास आदि की बिजाई के लिए प्रेरित किया था। किसानों को इसकी एवज में सात हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार ने एक लाख हैक्टेयर में वैकल्पिक फसलें पैदा करने का लक्ष्य रखा था।

किसानों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी

हरियाणा सरकार द्वारा पिछले साल निर्धारित किया गया लक्ष्य भी अधूरा रहा था और इस साल भी यह लक्ष्य अधूरा रह गया है। सरकार ने रतिया, गुल्हा, सिवान, बबैन, शाहबाद, इस्माइलाबाद, पिपली व सिरसा समेत आठ ब्लाकों का चयन करके इनमें धान की रोपाई पर रोक लगाई थी। योजना शुरू हुए एक माह होने जा रहा है और उपरोक्त आठ ब्लाकों में केवल 3110 किसानों ने ही वैकल्पिक फसलों के लिए पंजीकरण करवाया है। इनमें 788 किसानों ने मक्का, 56 किसानों ने बाजरा, 2117 किसानों ने कपास तथा 149 किसानों ने दालों की पैदावार के लिए पंजीकरण करवाया है। अन्य किसान पहले की तरह धान की पैदावार को तरजीह दे रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

कृषि मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक जे गणेशन पहुंचे नारनौल

नारनौल। जिला की मंडियों में चल रहे सरसों खरीद कार्य में कथित रूप से हुए घोटाले की गूंज किसी तरह सरकार के कानों तक पहुंची। हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक आईएएस जे गणेशन गुरुवार सुबह नांरनौल रेस्ट हाउस से मंडियों के दौरे पर जांच के लिए निकले। निकलने से पहले लोक निर्माण विश्राम गृह में उपायुक्त जगदीश शर्मा से सरसों घोटाला सम्बंधी सारा फीडबैक लिया। पत्रकारों ने भी मुख्य प्रशासक से सरसों घोटाले बाबत सवाल किया तो उन्होंने कहां कि वह इसी मामले की जांच के लिये आये हैं। कुछ किसान भी फर्जीवाड़े के प्रमाण लेकर पहुंचे। सभी को ध्यान से सुनकर अपने साथ सभी कागज ले गए। मीडिया और किसानों को कहा ठोस कारवाई होगी। स्मरण रहे पिछले करीब एक पखवाडे से नारनौल, नांगल चौधरी व निजामपुर में श्मशान भूमि, मेडिकल कालेज और लाजिस्टक हब भूमि की जमीनों के अलावा जिनके पास जमीन तक नहीं और ऐसे लोगों द्वारा फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर सरसों बेच देने के मामले सुर्खियां बने। नारनौल, निजामपुर, नांगल चौधरी, अटेली, बोचड़िया, करीरा व कनीना में शिकायतों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

करनाल में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले

करनाल। सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 6284 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए इनमें से 6060 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 182 की रिपोर्ट आना शेष है। उपायुक्त ने बताया कि जिले में वीरवार को कोरोना के 5नए पॉजिटिव केस आए हैं, इनमें ओल्ड चार चमन करनाल के 27 वर्षीय निजामुदीन खान, शांति नगर के 21 वर्षीय कुश कुमार, मीरा घाटी नजदीक शाम नगर के 28 वर्षीय भूपेश कुमार, नीलोखेड़ी खण्ड के गांव तखाना की 85 वर्षीय प्रभी देवी, और कुंजपुरा की 10 वर्षीय वंशिका का नाम शामिल है, जिनका कल्पना चावाला राजकीय मेडिकल कॉलेज में ईलाज शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि इन सभी व्यक्तियों के सम्बंधित एरिया को कन्टेनमेंट जोन तथा आस-पास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 42 पॉजिटिव केसों में से 22 व्यक्ति ठीक होकर अपने घर चले गये और 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 19 केस एक्टिव हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे बचाव के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन की अनुपालना अवश्य करें।सिविल सर्जन डॉ. अश्विनी आहुजा ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया कि जिला में अब तक विदेश से आए यात्रियों की संख्या 1074 है, जिनमें से 1012 व्यक्ति 28 दिन या इससे अधिक दिनों का सर्विलांस समय पूरा कर चुके हैं, 14 दिनों वाले कांटैक्टस व यात्रियों की संख्या 319 है तथा 15 से 28 दिनों के कांटैक्टस वाले यात्रियों की संख्या 151 है और 347 यात्री 28 दिनों का सर्विलांस पूरा कर चुके हैं।

कलायत व राजौंद के लिए बस सेवा शुरू : कमलजीत सिंह

कैथल। हरियाणा रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर कमलजीत सिंह ने बताया कि कैथल से कलायत व राजौंद के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है, जिसकी टिकट मौके पर ही दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह बसें करनाल चौक से चलेगी और कलायत व राजौंद भी बस स्टैंड के बाहर ही सवारियों को उतारेगी। कैथल से कलायत जाने के लिए सुबह 9 बजे तथा कलायत से कैथल के लिए सायं 3 बजे बस चलेगी। इसी प्रकार कैथल से राजौंद के लिए सुबह 11 बजे तथा राजौंद से कैथल के लिए सायं 4 बजे बस चलेगी।

जिले में कुल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज

नारनौल। सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि जिले में 3 पॉजिटिव और आये हैं। एक बॉयल से, दूसरा इसराना गांव का और तीसरा बाढड़ा से। इनमें एक सीआरपीएफ का जवान है जो जम्मू से आया है, एक गुड़गांव से आया है। बॉयल वाला किसी के संपर्क में आने से पॉजिटिव आया है। लोगों की स्क्रीनिंग के लिए गुरुवार को चार मोबाइल टीमों ने 314 लोगों की स्क्रीनिंग की है। इनमें से 173 मरीजों को सामान्य बीमारी मिली है। जिले में 28 मई तक 59792 नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 35174 मरीजों में सामान्य बीमारी पाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें से छह मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिला में कोरोना के 33 केस अभी भी एक्टिव है।

पुंडरीक तीर्थ पर रिटर्निंग दीवार का चेयरमैन ने किया शुभारंभ

पूंडरी। पूंडरी के पुंडरीक तीर्थ पर बनने वाली रिटर्निंग वॉल का हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन ने नारियल तोड़कर कर शुभारंभ किया। इस मौके पर नगरपालिका के सचिव अशोक कुमार व पार्षद व अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गोलन ने कहा कि किसी भी सूरत में विकास कार्यों की गति को रुकने नहीं दिया जाएगा और विकास के लिए धन की भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। गोलन ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हमें करोना के साथ ही जिंदगी व्यतीत करते हुए अपने कार्यों पर भी ध्यान देना होगा। इस मौके पर नगरपालिका सचिव अशोक कुमार, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मोनू खुराना, पार्षद कुलविंद्र चट्ठा, जितेंद्र राणा, पार्षद पवन सैनी, पार्षद रामकुमार, कीमत बंसल, मनदीप राज गोलन, नरेश मनचंदा, पालाराम कश्यप, नरेश मंचल, बलजीत सिंह, फतेह सिंह ठेकेदार, अनिल भट्ठ, अमित सैनी, एमई राजेश कुमार, हैड क्लर्क जोगिंद्र सिंह, जेई प्रदीप, योगेश उप्पल और निजी सचिव संजीव गामड़ी भी मौजूद थे।

गेहूं के अवशेष जलाने से वन विभाग को हो रहा है नुकसान

पूंडरी। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद किसानों द्वारा गेहूं कटाई के बाद गेहूं के बचे अवशेषों में आग लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकार द्वारा अवशेष न जलाने की सख्त हिदायत व सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा हुआ है। इसके बावजूद कुछ किसान आग लगाने से बाज नहीं आते हैं। जिसका खामयाजा आसपास के लोगों को ही नहीं पर्यावरण व वन विभाग द्वारा लगाए जाने वाले छोटे पौधों को भी भुगतना पड़ता है। सड़कों के साथ लगते खेतों में आग लगाने से गर्मी की वजह से घास-फूंस और वृक्षों के पते भी आग पकड़ लेते हैं और सड़क के साथ-साथ ये आग घास-फूंस, सूखे वृक्ष, छोटे पौधों को जलाते हुए कई किलोमीटर आगे तक निकल जाती है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान वन विभाग को होता है। कई बड़े वृक्षों भी आग की चपेट में आने से सूख जाते हैं या फिर जड़ों में आग लगने से गिर जाते हैं। इसी प्रकार का वाकया पूंडरी से ढांड मार्ग पर देखने को मिला। जिसमें किसी किसान द्वारा अपने खेतों में गेहूं के अवशेषों में आग लगाई गई और ये आग खेतों से होते हुए सड़क के साथ खड़े वृक्षों तक पहुंच गई और आग ने कई किलोमीटर तक वन विभाग द्वारा लगाए गये पौधों को झुलसा दिया। जिससे विभाग को हर वर्ष लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है और पर्यावरण भी दूषित होता है। ऋषिराज वन रेंज अधिकारी ने बताया कि जो किसान खेतों में आग लगाते हैं और उनके कारण वन विभाग के पौधे झुलस जाते हैं, ऐसे लोगों के चालान काटकर रिकवरी डाली जाती है और रिकवरी न भरने पर कुरुक्षेत्र की पर्यावरण कोर्ट में पेशी भुगतनी पड़ती है। आग लगाने वाले ऐसे 40 लोगों के पिछले वर्ष भी चालान काटे गये थे और अब भी चालान काटे जा रहे हैं और इनसे पौधे के लंबाई के हिसाब से रिकवरी डाली जाएगी।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 मई, 2020

दिल्ली-एनसीआर पर टिड्डी गैंग का खतरा

आपात बैठक में कीटनाशकों के स्प्रे, जागरूकता के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोविड-19 के बाद दिल्ली पर इस समय एक और नई समस्या आफत बनकर सामने आई है। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डियों के दल ने कई राज्यों पर धावा बोलने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। टिड्डियों के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई।

अधिकारियों संग बैठक करते कैबिनेट मंत्री गोपाल राय।

इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने सभी राजस्व आयुक्त, जिलाधिकारियों, तीनों एमसीडी और एनडीएमसी को एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा। साथ ही कृषि और हॉर्टिकल्चर विभाग को कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के साथ किसानों को इनके संभावित हमले से होने वाले नुकसान की आशंका के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया है।

गोपाल राय ने बताया कि टिड्डियों का दल पेड़ पौधे, नर्सरी आदि पर भी हमला कर सकती हैं। इसी को देखते हुए कृषि और हॉर्टिकल्चर समेत अन्य विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागों के अधिकारियों को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। वह सभी अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे। एग्रीकल्चर एक्सटेंश के असिसटेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत कुमार अरुण के मुताबिक पहले ये दल राजस्थान और पंजाब तक ही ज्यादातर सीमित रहता था, लेकिन इस बार इनकी पहुंच यूपी समेत दिल्ली एनसीआर तक हो गई है।

नोएडा व गाजियाबाद भी तैयार ढोल-नगाड़े और डीजे का सहारा

पीएनएस। गाजियाबाद/नोएडा

● प्रशासन ने किसानों से कहा- शोर मचाकर टिड्डियों को भगाएं

लॉकडाउन और महामारी से अभी पीछा छूटा भी नहीं है कि एक और नई आफत एनसीआर की ओर बढ़ रही है। इस नई मुसीबत से बचने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है।

गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने ग्रामीणों व किसानों को ढोल नगाड़े बजाने का कहा है। साथ उनको यह भी कहा गया है कि वे तेज आवाज में डीजे भी बजा सकते हैं। टिड्डियों के हमले से बचने के लिए डीएम ने पंचायत स्तर पर टीम भी बनाई है। वहीं कृषि विभाग ने भी एनसीआर में टिड्डी दलों के हमले को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। खेतों में इस समय धान की फसल बोने की तैयारी शुरू कर दी है। टिड्डी दल धान की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि विभाग ने कहा कि टिड्डी दल का हमला होते ही इसकी सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के अधिकारी, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचने चाहिए। टिड्डियों का हमला होते ही ग्रामीण एकत्रित होकर टीन के डिब्बे, तालियां, डीजे आदि बजाकर शोर मचाना चाहिए। ऐसा होने पर टिड्डी दल आसपास के खेतों में आक्रमण नहीं करता। प्रकोप दिखाई देने पर लाइट टाइप का प्रयोग कर कीटों को नष्ट कर दिया जाए।

मरी टिड्डियां ढाह सकती हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसीबत

नई दिल्ली। अगर टिड्डियों का हमला इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर होता है तो एयर ट्रैफिक पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस बारे में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) और पायलटों का कहना है आमतौर पर इतने छोटे कीटों से हवाईजहाजों और इनके इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यह बहुत बड़ी संख्या में एकत्र होकर एक बड़े पक्षी जैसा रूप बनाते हुए एक साथ जेट में घुस जाएं तो इंजन के खराब होने की आशंका होती है। लेकिन वह भी बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इनका साइज जेट के हिसाब से बहुत छोटा है। एक ही डर सबसे अधिक है कि अगर यह रनवे और इसके आसपास मर गईं तो इन्हें खाने के लिए आने वाले बड़े पक्षी हवाई यातायात को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। एयर ट्रैफिक अलर्ट मोड पर है। अगर यह एयरपोर्ट की ओर आ गईं और यहां यह बड़ी संख्या में मरती हैं तो फिर जब तक पूरी तरह से इनकी सफाई नहीं की जाती तब तक विमान उड़ान नहीं भर सकते हैं।

दो दिन में डॉक्टरों समेत 50 एम्स कर्मी पॉजिटिव

तीन रेजिडेंट डॉक्टर, आठ नर्स, पांच मेस कर्मचारी सहित अब तक 195 को कोरोना

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में अब तक 195 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक एमबीबीएस छात्र, तीन रेजिडेंट डॉक्टरों, आठ नर्सों और पांच मेस कर्मचारियों समेत 50 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। ये सभी पिछले दो दिनों में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं।

अन्य लोगों में प्रयोगशाला के कर्मी, टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की

कोशिश की जा रही है। बृहस्पतिवार सुबह तक 28 स्वास्थ्य कर्मी जांच में संक्रमित पाए गए हैं जबकि बुधवार सुबह तक करीब 23 लोग संक्रमित पाए गए। संक्रमित पाए गए स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और अधीनस्थ कर्मी अस्पताल के कोविड-19 और गैर कोविड-19 इलाकों के हैं। इंजीनियरिंग, प्रयोगशालाओं, कार्यालयों, कैंटीन, ऑपरेशन थिएटरों और वार्डों जैसे सभी तरह के विभागों के कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं।

एक फरवरी से लेकर अभी तक दो फैकल्टी, पांच रेजिडेंट डॉक्टर, 21 नर्सिंग कर्मी, आठ टेक्नीशियन, 32 सफाई कर्मचारी और 68 सुरक्षा गार्ड समेत 195 स्वास्थ्य देखभाल कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से कई स्वस्थ हो गए और ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं।

कोविड-19 से संक्रमित पाए गए एम्स के एक सैनिटेशन सुपरवाइजर की रविवार को मौत हो गई जबकि एक मेस कर्मचारी की गत सप्ताह मौत हो गई।

एनडीएमसी के कई कर्मी संक्रमित, मुख्यालय सील

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने एक वरिष्ठ कर्मचारी के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद मध्य दिल्ली में स्थित अपनी इमारत को बृहस्पतिवार को बंद कर दिया। एनडीएमसी के अब तक सात कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं।

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, संयुक्त निदेशक स्तर के एक कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। कल तीन और कर्मचारी संक्रमित पाए गए थे। तय नियम के तहत जिला प्रशासन संपर्क पता लगाने के कार्य में जुटी हैं। इमारत को बंद कर दिया गया है और उसे संक्रमण मुक्त करने का कार्य जारी है।

अधिकारी ने बताया कि इमारत के संक्रमण मुक्त होने और इसके दोबारा खुलने तक सभी कर्मचारी घर

● पालिका केंद्र और शहीद भगत सिंह प्लेस दो दिन के लिए बंद

से काम करेंगे। एनडीएमसी के तीन कर्मचारी बुधवार को संक्रमित मिले थे। इसके बाद एनडीएमसी ने लुटियंस दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय की एक मंजिल और गोल मार्केट में एक अन्य इमारत में स्थित अपने कार्यालय के एक हिस्से को बंद कर दिया था। इससे पहले भी नगर परिषद के तीन कर्मचारी संक्रमित मिले थे, जिनमें से एक सफाई कर्मी और इंजीनियर भी था।

पिछले सप्ताह परिषद के दवाखाने में काम करने वाले एक डॉक्टर भी संक्रमित मिले थे, जिसके बाद इस परिसर को बंद कर दिया गया।

दिल्ली जल बोर्ड की दूसरी मंजिल लॉक

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड के करोल बाग स्थित मुख्यालय में तीन कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय वरुणालय कॉम्प्लेक्स के दूसरे तल को बृहस्पतिवार से शनिवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों ने तत्काल पूरे मुख्यालय को संक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है।

एक लाख सैनिटरी नैपकिन बांटेगी दिल्ली सरकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली बाल संरक्षण आयोग ने मासिक धर्म स्वच्छता अभियान शुरू किया है। सप्ताह भर चलने वाले इस मुहिम में आयोग, पूर्वी और उत्तर पूर्व जिलों की विभिन्न क्लस्टर में रहने वाली महिलाओं और युवा लड़कियों को एक लाख से अधिक सैनिटरी नैपकिन वितरित करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस अभियान का उद्घाटन किया।

आयोग का मकसद इस अभियान के जरिए दिल्ली सरकार, सामाजिक संगठनों की मदद से मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाए और अधिक से अधिक घरों तक महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करे। इसमें केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुषों की भी भागीदारी होगी।

राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पारिवारिक स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता है। विभिन्न

● डीसीपीसीआर ने शुरू किया मासिक धर्म स्वच्छता अभियान

सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी और जेजे क्लस्टर में रहने वाली महिलाओं को साफ शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। इस मुहिम के माध्यम से सरकार का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि हम केवल सैनिटरी नैपकिन बांटे बल्कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में परिवारों के बीच जागरूकता पैदा भी करें।

पानी टैंकर के नाम पर 5 सौ करोड़ का घोटाला : लेखी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

तापमान बढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। इस मुद्दे पर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा है।

पार्टी नेता ने आम आदमी पार्टी के नेता पर टैंकर माफिया चलाने का आरोप मढ़ा है। उनका कहना है कि यह सब केजरीवाल के संरक्षण में हो रहा है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने बृहस्पतिवार संवाददाता सम्मेलन में विवेकानंद कैंप की फोटो दिखाते हुए कहा पानी के लिए पूरी दिल्ली का यही हाल है। लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि पानी के टैंकर आने पर उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रहता। टैंकर के पास भीड़ जमा हो जाती है। उन्होंने इंद्रपुरी क्षेत्र का एक वीडियो साझा किया जहां पर इस भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लेखी ने कहा कि राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है इंद्रपुरी जहां से आप विधायक हैं राघव चड्ढा जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। उनके ही क्षेत्र में पानी की कमी से लोग परेशान हैं।

तीसरे दिन भी दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर पर वाहनों का लंबा जाम

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

दिल्ली बॉर्डर सील किए जाने के बाद गुरूवार को तीसरे दिन भी दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को जाम झेलना पड़ा। सुबह से ही यूपी बॉर्डर पर दिल्ली जाने वाले वाहन की लंबी कतारें देखने को मिलीं।

पुलिस द्वारा आवश्यक व आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों और पास धारकों को ही दिल्ली में प्रवेश करने दिया गया। बता दें कि गाजियाबाद से दिल्ली में डयूटी करने जाने वालों के लिए सुबह नौ बजे तक गाजियाबाद की सीमा से निकलने और शाम पांच बजे के बाद गाजियाबाद की सीमा में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है। हालांकि पुलिस द्वारा बॉर्डर पर निर्धारित समय के बाद भी कुछ समय तक बॉर्डर पार करने की इजाजत दी गई। इस दौरान पुलिस द्वारा केंद्र सरकार और जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का उल्लंघन करने वाले दोपहिया व चार पहिया वाहन चालकों के चालान भी भरे गए। चालकों का कहना है कि पचेकिंग के कारण आफिस पहुंचने में अधिक समय लगता है।

रिहायशी इमारत में आग नहीं हुआ कोई जख्मी

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक रिहायशी इमारत में बृहस्पतिवार को आग लग गई। दमकल की आठ गाड़ियों ने आग को काबू किया। इस अगजनी में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है।

आशंका है कि शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजकर 27 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की आठ गाड़ियां भेजी गई। आग ने इमारत की दूसरी मंजिल और छत पर एक अस्थाई ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया।

जेपी एसोसिएट्स व इंफ्राटेक की होगी जांच

पायनियर समाचा सेवा। नोएडा

● यूपी सरकार ने दिया आदेश, अनियमितताओं के लगे है आरोप

जेपी समूह की प्रमुख फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स और दिवालियापन की प्रक्रिया में चल रही जेपी इंफ्राटेक की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने का आदेश दिया गया है। यह जांच एजेंसी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करती है।

मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने जयप्रकाश एसोसिएट्स और जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ एसएफआईओ जांच का आदेश दिया है। पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी में चूक और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवास परियोजनाओं को पूरा करने में बेतहाशा देरी के कारण कम्पनी समूह संकट का सामना कर रहा है। समूह ने अपने कर्ज को कम करने के लिए पहले सीमेंट और बिजली संयंत्र बेच दिए थे।

लेकिन इसके बावजूद भी हालात नियंत्रित नहीं हुए। स्थिति तब बेकाबू हो गई जब कंपनी समूह का हिस्सा जेपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 30,000 फ्लैट का काम पूरा नहीं कर पाई। कंपनी के खिलाफ निवेशक, फ्लैट खरीदार और बैंक एनसीएलटी चले गए थे। जेपी इंफ्र टेक जयप्रकाश एसोसिएट्स की सहायक कंपनी है। इसके खिलाफ अगस्त 2017 में दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई।

लेनदारों की समिति सीओसी में 13 बैंक और लगभग 21,000 होमबॉयर्स शामिल हैं। 6 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्र टेक की 90 दिनों के भीतर दिवालिया प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दिसंबर में सीओसी ने एनबीसीसी के संकल्प योजना को मंजूरी दी थी।

रियल एस्टेट सेक्टर को 4 लाख श्रमिकों की जरूरत

गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद में एक लाख फ्लैट निर्माणाधीन हैं, एक साल की देरी से मिलेंगे घर

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में काम कर रहे दूसरे राज्यों के प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस लौट रहे हैं।

वहीं, उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक वापस आ रहे हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काम कर रहे थे। अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है की दूसरे राज्यों से वापस लौटकर आ रहे कामगारों को काम उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही सरकार ने यह भी पाबंदी लगा दी है कि दूसरी राज्य सरकारें यूपी से अनुमति लिए बिना यहां के श्रमिकों को काम नहीं देंगी। ऐसे में नौकरी के अवसरों और दावेदारों के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। दूसरी

ओर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र और गाजियाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर मजदूरों के अभाव में काम शुरू नहीं कर पा रहा है। बिल्डरों का अनुमान है कि अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही काम को पूरी रफ्तार से शुरू करने के लिए करीब 4 लाख मजदूरों की आवश्यकता है।

ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की संस्था नरेडको ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि उसके सदस्य बिल्डर ढाई लाख मजदूरों को काम देने के लिए तैयार हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको की यूपी इकाई ने कहा है कि वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए 2.5 लाख श्रमिकों को नियुक्त कर सकती है।

अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने में मिलेगी मदद

22 मई को यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब तक 18.24 प्रवासी श्रमिक अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। नरेडको ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। जिसमें सरकार से एनसीआर में काम शुरू करने के लिए रियल एस्टेट क्षेत्र के पुनरुद्धार और हालिया स्थिति को मजबूत करने का आग्रह किया है। रुपये की तरलता की कमी है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डिवेलपर्स एसोसिएशन की एनसीआर इकाई के अध्यक्ष पंकज बजाज ने कहा, धीरे-धीरे राज्य में लौटने वाले अधिकांश श्रमिक पूर्वी यूपी में चले गए हैं। एनसीआर में मजदूरों की मांग में गिरावट आई।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाषः 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादकः चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादकः उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 मई, 2020

जब तक जीवित थे कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, मौत के बाद पॉजिटिव

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

बुजुर्ग की मौत के मामले में निजी अस्पताल पर उठे सवाल

कैंसर से पीड़ित थे बुजुर्ग, अस्पताल ने पीपीई किट समेत कई खर्च वसूले

कैंसर पीड़ित एक बुजुर्ग जब तक जीवित थे, तब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई। यह बात परिजनों के गले नहीं उतरी और उन्होंने अस्पताल में हंगामा काटा। इसके बावजूद घंटों तक परिजनों को शव नहीं दिया गया। कोरोना पॉजिटिव केस बताकर इससे संबंधित नियम शर्तों का हवाला देकर कई हजार रुपये अलग से खर्च करा दिए। पीड़ित परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जानकारी के अनुसार यहां के बसई गांव निवासी एक बुजुर्ग को कैंसर की वजह से यहां सुशांत लोक फेज-1 स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया था। बुजुर्ग के बेटे बालकिशन के मुताबिक उनके पिता पिछले दो साल से कैंसर से पीड़ित थे। 12 मई 2020 को उनकी सेहत खराब होने के कारण अस्पताल लेकर गए। वहां पर ऐहतियात बरतते हुए उनका कोरोना टेस्ट कराया। आईसीयू में उन्हें भर्ती किया। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। रिपोर्ट के बाद डॉक्टर्स ने उनके पिता की तबियत और अधिक खराब होने की बात कहकर वेंटिलेटर पर रखने की बात कही। वेंटिलेटर पर ले जाने से पहले भी उनकी कोरोना जांच की गई, जो कि नेगेटिव आई। 26 मई की शाम को बुजुर्ग की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने परिजनों को इस बाबत बता दिया। डॉक्टर्स ने बुजुर्ग की मौत के बाद फिर से कोरोना जांच कराई। इस बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मतलब जब वे जीवित थे तो रिपोर्ट नेगेटिव रही और मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई। इस पर अस्पताल ने शव देने से इंकार कर दिया। परिजनों ने इस बाबत अस्पताल में बवाल काटा। क्योंकि उनका बुजुर्ग मौत से पहले कोरोना नेगेटिव था और मौत होते ही उसे पॉजिटिव करार दे दिया गया।

मौत के बाद पॉजिटिव होने की हो जांच

बुजुर्ग के बेटे बालकिशन ने अपने पिता के देहांत के बाद पॉजिटिव होने को लेकर अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले की दो बार की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। घर के किसी सदस्य को उन तक जाने नहीं दिया। अब अस्पताल यह बताए कि उनके पिता कैसे कोरोना पॉजिटिव हुए। यह अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए विधायकों, कई नेताओं तक यह बात पहुंचाई है।

मदनपुरी श्मशान घाट में हुआ दाह संस्कार

हर बार कोरोना पॉजिटिव के जांच के नाम पर 4500 रुपये भी वसूले गए। हंगामा काटने के बाद अस्पताल ने कुछ शर्तों के साथ शव देने को तैयारी की।

अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस के 2000 रुपये और एम्बुलेंस के साथ मदनपुरी श्मशान घाट में शव लेकर गए तीन कर्मचारियों के पीपीई किट के नाम पर 6000 रुपये ले लिए गए। तब जाकर बुजुर्ग का दाह संस्कार हुआ।

...ऐसे तो फिर पूरा गुरुग्राम ही बन जाएगा कोरोना का हॉट स्पॉट

छोटे अस्पतालों नर्सिंग होम में कोरोना मरीजों को भर्ती करने पर आईएमए हटी पीछे

जिलाधीश से अपने आदेशों को रिव्यू करने की दी सलाह

अभी जो अस्पताल अधिग्रहित हैं, उन्हीं में भेजें कोरोना पॉजिटिव मरीज

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

अगर जिला प्रशासन के आदेशों को निजी अस्पताल और नर्सिंग होम मानते हुए कार्य करते हैं तो पूरा गुरुग्राम कोरोना का हॉट स्पॉट बन जाएगा। फिर स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो जाएगी। सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो जाएंगी। यहां तक कि निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में झगड़े-फसाद भी बढ़ जाएंगे।

गुरुग्राम जिला के सभी निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करने के आदेश बतौर जिलाधीश जिला उपायुक्त अमित खत्री की ओर से बीती 25 मई 2020 को दिए गए थे। इस बाबत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) गुरुग्राम के अध्यक्ष डा. महावीर जैन का कहना है यह काम इतना आसान नहीं है।

विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि कोरोना महामारी फैली है। महामारी के बीच गुरुग्राम के अस्पतालों, नर्सिंग होम में कोरोना संक्रमित मरीजों को दाखिल करने के जो आदेश दिए गए हैं, वे किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं हैं। अगर ऐसा सभी अस्पताल, नर्सिंग होम करते हैं तो फिर जिला में स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। किसी भी एक अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती होता है तो उस अस्पताल की सारी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो जाएंगी। आम आदमी वहां नहीं आएगा।

अस्पताल संचालकों का परिवार भी इससे सफर करेगा। दूसरी बड़ी बात यह कि छोटे अस्पतालों, नर्सिंग होम में बेड साइड ऑक्सीजन, आईसीयू सुविधा नहीं है। ऐसे माहौल में किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती करना रिस्की रहेगा। सभी प्रभावित होंगे। सभी अस्पतालों में कोरोना पॉजिटिव भर्ती हो गए तो फिर यहां हालात बिगड़ जाएंगे। गुरुग्राम कोरोना का हॉट स्पॉट बन जाएगा। अच्छा करने के फेर में स्थिति और खराब हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन के आदेशों का हवाला देकर कोरोना संक्रमित लोग यहां दाखिल होने की जबरदस्ती करेंगे। अस्पताल मना करेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे।

अधिगृहित अस्पतालों को दें तवज्जो

आईएमए अध्यक्ष डा. महावीर जैन का कहना है कि प्रशासन ने पूर्व में जो छह अस्पतालों में 600 बेड तैयार किए हैं, पहले उनको उपयोग होना चाहिए। अभी कोरोना की इतनी स्थिति खराब नहीं हुई है कि छोटे अस्पताल और नर्सिंग होम को इनमें शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने जिला उपायुक्त अमित खत्री को सुझाव दिया है कि वे अपनी अध्यक्षता में एक कॉर्डिनेशन कमेटी गठित करें, जिसमें आईएमए को, सीएमओ को व अस्पतालों के प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल करके इस पर प्लानिंग करें। जैसे-जैसे पूर्व में अधिग्रहित अस्पतालों में बेड भरते जाएंगे, दूसरे अस्पतालों को इस सूची में शामिल किया जाए। जब स्थिति बहुत ही अधिक विस्फोटक होगी तो हर छोटा अस्पताल, नर्सिंग होम कोरोना पॉजिटिव केस भर्ती करेगा। कभी पीछे नहीं हटेगा।

कारपोरेट अस्पतालों में 4000 से अधिक बेड

आईएमए के सचिव डा. राजेश कटारिया कहते हैं कि जिला में तीन बड़े मेडिकल कॉलेजों के अलावा बड़े कारपोरेट अस्पतालों में 4000 से अधिक बेड हैं। उन्हें प्रमुखता से लिया जाए। छोटे अस्पतालों में सामान्य बीमारियों का उपचार, मेटरनिटी सेवाएं दी जा रही हैं। अगर यहां पर कोरोना के केस भर्ती किए तो फिर इन सेवाओं को देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन अपने आदेशों को रिव्यू करे, ताकि हर नागरिक को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें।

20 से 25 दिन बाद भी नहीं हो रहा फसल का भुगतान

सोहना में किसानों से खरीदा गया गेहूं।

सोहना। क्षेत्र के किसानों ने सरसों और गेहूं की फसल सरकारी खाते में बेच तो दी, लेकिन 20 से 25 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों को उनका भुगतान नहीं दिया गया। किसान दूसरे और तीसरे दिन जाकर अपने बैंक खातों की जांच करा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते राज्य में कहीं-कहीं मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद रिकार्ड तोड़ हुई है। जैसा कि पहली बार सोहना ब्लॉक में सरसों की आवक ने रिकार्ड बनाया था। सरकार की तरफ से सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने के साथ फसल का भुगतान सीधे बैंक खातों में भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन 20 से 25 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल रहा है।

गांव लाखूवास निवासी किसान लालसिंह का कहना है कि उसने और उसके दो भतीजों ने 5 मई को सोहना में गेहूं की फसल बेची थी। आज 23 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें उनकी फसल की कीमत नहीं मिली है। गांव खाईका निवासी किसान हंसराज का कहना है कि एक तरफ सरकार ने किसानों की फसल का भुगता सीधे बैंक खाते में 24 से 48 घंटे में देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक फसल का एक पैसा नहीं मिला।

क्या कहना है कि अधिकारी का

हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि किसानों का भुगतान बैंकों में देने का कार्य शुरू है। 14 मई तक जो फसल खरीदी गई थी। उसका पैसा किसानों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। यदि किसी किसान का भुगतान रुका हुआ तो जांच करके भेज दिया जाएगा।

मेयर ने दिखाए तेवर...लापरवाह अधिकारियों के तबादले की तैयारी

गुरुग्राम। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने एक बार फिर से तेवर दिखाए हैं। अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर असंतुष्ट मेयर ने साफ कहा है कि जो अधिकारी काम नहीं करते, उनके तबादले निश्चित हैं। अब अधिकारी यह तय कर लें कि वे यहां से जाना चाहते हैं या काम करना। गुरुवार को यहां नगर निगम कार्यालय में सफाई विंग की बैठक में उन्होंने यह बात कही।

मेयर मधु आजाद ने वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों तथा सफाई निरीक्षकों से रोजाना सफाई कर्मचारियों की हाजरी की रिपोर्ट मांगी। मेयर ने हजरियों में गड़बड़ी के मामले में नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने इकॉग्रीन तथा अन्य सफाई एजेंसियों पर लगने वाली पैनल्टी के बारे में समीक्षा की। मेयर ने ट्रेक्टर और जेसीबी पर जीपीएस नहीं लगाने वाले ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश अधिकारियों को दिए। मेयर ने संयुक्त आयुक्तों से कहा कि वे हर सप्ताह अपने जोन की रिपोर्ट भेजें।

गुरुग्राम में नगर निगम में अधिकारियों की बैठक लेतीं मेयर मधु आजाद।

मेयर ने रोड स्वीपिंग मशीन को धन का दुरुपयोग बताया तथा इन्हें हटाने बारे कहा। बैठक में मेयर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करवाएं। इसके तहत गलियों तथा मुख्य सड़कों की पर्याप्त सफाई हो। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सूरत में कूड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए। मेयर ने कहा कि प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरा उठाया जाना चाहिए तथा कचरा प्वाइंट्स की भी नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कचरा प्वाइंटों से कचरा उठान समयबद्ध तरीके से हो।

मेदांता मेडिसिटी की संक्रमित नर्स ने किया आत्महत्या का प्रयास

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में गुरुवार को केरल की रहने वाली एक स्टाफ नर्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि वह कोरोना पॉजिटिव थी। दो दिन पूर्व उसका कोरोना का टेस्ट हुआ था, जिसमें आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बारे में अभी पुलिस ने जांच की बात कही है, वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ भी बयान जारी नहीं किया गया है।

जानकारी के अनुसार केरल के कोल्लम की रहने वाली इस नर्स ने तीन महीने पहले ही यहां मेदांता मेडिसिटी में बतौर स्टाफ नर्स ड्यूटी ज्वाइन की थी। उसकी यहां आपातकालीन विभाग में ड्यूटी लगी थी। कोरोना के फैलने के खतरे के बीच यहां ऐहतियात के तौर पर उसका कोरोना जांच के लिए बुधवार को सेंपल लिया गया था। बताया जा रहा है कि सेंपल लिए जाने के बाद से ही वह तनाव में थी। गुरुवार को उसके सेंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव बताई गई। इससे वह और अधिक तनाव में आ गई। इसी तनाव में उसने हॉस्टल में अपने कमरे में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेदांता मेडिसिटी में ही भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर है। होश में आने के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव होने के अलावा भी पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। असल कारणों का तभी पता चल पाएगा, जब स्टाफ नर्स के बयान दर्ज होंगे।

बता दें कि मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में काफी नर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। पूर्व में एक स्टाफ नर्स द्वारा ऑडियो जारी करके कहा गया था कि यहां पर आईसोलेशन वार्ड में कोई सुविधा नहीं मिलती। इसलिए बहुत से नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं।

नूंह जिले में दीक्षा टीम तैयार कर रही है ई-कंटेंट

नूंह। कोरोना महामारी के कारण जहां स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं वहीं जिले में अध्यापकों की टीम ई-कंटेन्ट की पूरी तैयारी कर रही है। दीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर का वेब पोर्टल है जो गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। जिसमें सभी कक्षाओं के वीडियो के साथ सरल सामग्री उपलब्ध है ताकि विद्यार्थियों को घर बैठे ही हर विषय की गुणवत्तापूर्ण रोचक सामग्री प्राप्त हो और वो बिना रुके पढ़ाई जारी रख सकें। इसके लिए स्क्रेट गुरुग्राम द्वारा प्रत्येक जिले को अलग-अलग चार टॉपिक दिए हैं। जिसे अध्यापक गहन विचार-विमर्श के बाद अपनी योजना बना कर तैयार करता है और फिर उसे जिले की टीम के साथ, राज्य स्तर की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है उसके बाद वह पोर्टल पर उपलब्ध किया जाता है। दीक्षा के जिला समन्वयक, गेट्टी प्रवक्ता डॉ. संजय ने बताया कि हमारे सभी टॉपिक निरीक्षण के बाद अपलोड हो गए हैं।

सीएंडडी वेस्ट का सही निपटान न करने पर निर्माण भी हो सकता है सील

अनाधिकृत रूप से सीएंडडी डंपिंग को रोकने के लिए नगर निगम गुरुग्राम हुआ सख्त

गुरुग्राम। निर्माण एवं तोड़फोड़ कार्यों से उत्पन्न होने वाले मलबे अर्थात सीएंडडी वेस्ट की अनाधिकृत डंपिंग को रोकने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसके तहत जो निर्माणकर्ता उनके यहां उत्पन्न होने वाले मलबे का सही ढंग से निपटान नहीं करेंगे तो उनके निर्माणों को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह द्वारा सीएंडडी वेस्ट की अनाधिकृत डंपिंग को रोकने के लिए गठित टीमों द्वारा डीएलएफफेज-3 में एक निर्माण को सील करने की कारज़्वाई की। टीमों ने सेक्टर-14 तथा सिविल लाइन्स क्षेत्रों में भवन निर्माण करने वालों को नोटिस भेजकर उनके यहां उत्पन्न होने वाले मलबे के सही ढंग से निपटान करने बारे कहा गया है। सयुंक्त आयुक्त एवं सीएंडडी वेस्ट प्रबन्धन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी इंद्रजीत कुल्हड़िया के अनुसार नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गांव बसई में मलबा प्रबन्धन का कार्य किया जा रहा है। घर-घर से मलबा उठान के लिए एजेंसियों को अधिकृत किया हुआ है। ये एजेंसियां नगर निगम गुरुग्राम द्वारा निर्धारित दरों पर आपके घर से मलबा उठाएंगी। मलबा उठान के लिए मोबाईल नम्बर 8607058320 तथा 7005674475 पर संपर्क करें। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत रूप से सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के वाहनों को जब्त करके उनके खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

नौरंगपुर गांव में बिहार की महिला के साथ रेप, केस दर्ज

गुरुग्राम। बिहार मूल की रहने वाली महिला ने मेवात के फिरोजपुर झिरका के रहने वाले युवक पर रेप का आरोप लगाया है। दोनों ही यहां नौरंगपुर गांव में रहते हैं। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना दक्षिण ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसीपी (महिला अपराध) शकुंतला यादव ने गुरुवार को बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

बिहार मूल की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लॉकडाउन के दौरान वह नौरंगपुर स्थित अपने कमरे पर अकेली थी। इस दौरान पड़ोसी फिरोजपुर झिरका निवासी इरफान उसके कमरे में घुस आया। उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर चला गया। दूसरे दिन आरोपी दोबारा आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बुधवार देर रात महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एसीपी शकुंतला यादव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

तीन बसें हिमाचल प्रदेश और दो बसें मध्यप्रदेश को हुईं रवाना

लॉकडाउन में अब तक 335 बसों में लगभग 10,500 लोगों को भेजा घर

दूसरे प्रदेशों के श्रमिकों व अन्य को भेजा गया घर

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लॉकडाउन में पंजीकृत प्रवासी नागरिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक गुरुग्राम जिला से 335 बसों में लगभग 10 हजार 500 प्रवासी नागरिकों को उनके गृह राज्यों में भेजा जा चुका है। गुरुवार को जिला से 3 बसों को हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, सोलन तथा 2 बसों को मध्यप्रदेश के छत्तरपुर के लिए रवाना किया गया।

गुरुग्राम से हिमाचल व मध्यप्रदेश के लिए रोडवेज बसों जाते लोग।

गुरुग्राम जिला में 14 मई से लगातार अलग-अलग राज्यों के नागरिकों को उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। यह यात्रा पूर्ण रूप से नि:शुल्क है। यात्रियों से इसका किराया नहीं लिया जा रहा। बस में इन यात्रियों को बिठाते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल जिसमें मुंह और नाक पर मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए समझाया गया है। प्रवासी नागरिकों को फूड पैकेट देकर व भोजन आदि करवाकर भेजा जाता है। इस दौरान यात्रियों को फेस मास्क व अन्य जरूरत का सामान भी उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि बसों में जाने वाले प्रवासी नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है व उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। प्रवासी नागरिकों को कोरोना संक्रमण संबंधी बचाव उपायों की जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि वे गृह जिलों में जाकर भी एहतियात बरत सकें।

संक्षिप्त समाचार

अवैध खनन करने पर होगी कठोर कार्रवाई : चंद्रभान

नूंह। जिले के पिनगवां क्षेत्र से लगते गांव झिमरावट, खानपुरघाटी व ढाडोला सहित कई गांवों में चोरी छिपे हो रहे अवैध खनन पर अब पिनगवां पुलिस पैनी नजर रख रही है। एसएचओ चंद्रभान ने थाने का कार्यभार संभालते ही खनन माफियाओं के रास्तों को जेसीबी से कटवा दिया है, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके। साथ में ये भी कह दिया कि जो लोग चोरी छिपे अवैध खनन का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ सखती से निपटा जाएगा। थाना प्रभारी चंद्रभान ने बताया कि झिमरावट, खानपुरघाटी, बूबलहेडी, ढाडोलीकलां व शाहचौखा सहित कई अरावली पहाडी के निकटतम बसे कई गांवों में कुछ लोग चोरी छिपे अवैध खनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ अब सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वाले खनन माफिया या तो अपनी आदतों से बाज आ जाएं वरना फिर पुलिस उनके साथ सख्ती से निपटने को तैयार है। थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध खनन पूरी तरह रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को जो भी अवैध खनन करता या पत्थर ले जाता वाहन मिला उसे बख्शा नहीं जाएगा।

30 हजार उपभोक्ताओं को बिजली कटों से मिलेगी राहत

सोहना। सोहना सबडिविजन के 30 हजार उपभोक्ताओं को जल्द ही बिजली के कटों से राहत मिलेगी। इंडरी और रोजका मेव पॉवर हाउस की बिजली सप्लाई अन्य लाइन से जोड़ने की कवायद अंतिम चरण में चल रही है। सोहना बिजली निगम के एसडीओ रविन्द्र बैरवाल ने बताया कि अभी तक सोहना के 66 केवीए पॉवर हाउस में एक ही ट्रांसफार्मर पर लोड़ चल रहा था। जिसमें बुधवार को परिवर्तन करते हुए अन्य ट्रांसफार्मर पर डाला गया है। उसके बाद से बिजली की सप्लाई में लगने वाले कटों की संख्या कम हो गई है। एसडीओ ने बताया कि इंडरी में स्थापित 33 केवीए पॉवर हाउस पर सात दिन के बाद चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ इंडरी और रोजका मेव पॉवर हाउस पर बिजली सप्लाई सोहना से कट कर दी जाएगी। इंडरी और रोजका मेव पावॅर हाउस को केएमपी के साथ आ रही लाइन से जोड़ा जाएगा। दोनों पॉवर हाउस चालू होने से सोहना सबडिविजन में फीडरों की संख्या 35 से घटकर 18 से 20 रह जाएगी। जिससे सोहना के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के लगने वाले कटों से पूरी तरफ से छुटकारा मिल जाएगा।

जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलेंगे स्मार्ट मोबाइल

सोहना। जिला परियोजना संयोजक अधिकारी अपने निजी कोष से जिले के सभी खण्डों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरण करेगी। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थियों की पहचान की जा रही है। जिला परियोजना संयोजक अधिकारी रितु चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। विभिन्न टीवी चैंनलों पर बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रम आ रहे हैं। बच्चों और अध्यापक के बीच संवाद के बिना यह शिक्षा अधूरी है। अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ निर्देश देना, बच्चों द्वारा अध्यापक से कुछ पूछना, गृहकार्य दिखाना यह सब स्मार्ट फोन पर व्हाट्सएप द्वारा संभव है। इसके लिए जिला अधिकारी ने अपने निजी कोष से ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन चलाने के लिए देने का फैसला किया है। उन्होंने ने बताया कि सभी ब्लॉक में जरूरतमंद विद्यार्थियों की पहचान करने का जिम्मा सौंपा है। जो 29 मई तक सूची तैयार कर उन्हें सौंप देंगे।

पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जरूरी

नूंह। पशुओं के मुंहखुर, गलघोटूं जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण जरूरी है। यह आह्वान जिले के पशुपालकों से डाक्टर नरेंद्र यादव ने किया है। पशुपालन विभाग की जानकारी के अनुसार अब तक जिले में 153180 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में बचे हुए पशुओं के लिए अभी भी टीकाकरण अभियान जारी है, जिन पशुओं के टीके नहीं लग पाए वो अपने पशुओं के टीके लगवा सकते हैं। पूरे जिले में लगभग 85 प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है बाकी 15 प्रतिशत पशुओं के भी मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशु पालन एवं डेयरिंग विभाग नूंह पशु पालकों के लिए कोरोना वायरस (योद्धा) के रूप में सामने आया है। उप निदेशक, पशु पालन एवं डेयरिंग विभाग नूंह के दिशा निर्देश अनुसार जिले के सभी उप मण्डल अधिकारियों, पशु चिकित्सकों व सभी कर्मचारियों द्वारा इस लॉक डाउन के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए मापदण्डों के तहत सामाजिक दूरी व सैनेटाइजिंग को ध्यान में रखते हुए समस्त जिले में 23 अप्रैल से प्रारंभ किए गए हैं।

सरकारी, निजी अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था के आदेश

गुरुग्राम। गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने को हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने पॉजिटिव आने वाले मरीजों के लिए सरकारी तथा निजी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी मरीज को ईलाज की सुविधाओं की कमी ना रहे। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने राज्य स्तर तथा जिला स्तर के लिए अलग-अलग एपीटोमोलॉजिकल मॉडल तैयार करने पर बल दिया ताकि कोरोना के फैलाव के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर आगे की तैयारियां की जा सकें और भविष्य में फैलाव का अनुमान भी लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला के अस्पतालों में कम से कम एक हजार बिस्तरों की व्यवस्था कोरोना के मरीजों के लिए की जाए और इनमें से 500 बिस्तरों के साथ में ऑक्सीजन की सुविधा हो। कम से कम 100 बिस्तरों के साथ वेंटिलेटर भी उपलब्ध हो। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुग्राम तथा फरीदाबाद जिलों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचे, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने तक उस व्यक्ति से संपर्क करके उसके सभी परिजनों का सेंपल भी ले लिया जाए। राजेश खुल्लर ने कहा कि हरियाणा की किसी भी लैब में जब किसी व्यक्ति के सेंपल का टेस्ट हो, उस व्यक्ति के गृह जिला के स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए कि उक्त व्यक्ति ने सैंपल दिया है। यदि व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश का है तो वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचना तत्काल भेजी जाए। ऐसी ही व्यवस्था की अपेक्षा हम दूसरे प्रदेशों से भी करते हैं कि उनके यहां यदि कोई हमारे प्रदेश का व्यक्ति टेस्ट करवाता है तो उसकी सूचना हमारे संबंधित जिला के स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाए। रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो तुरंत संबंधित व्यक्ति को मैसेज करें। उन्होंने यह भी कहा कि सेंपल लेने के बाद यदि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उस व्यक्ति को इस बारे में तत्काल एसएमएस चला जाए।

नाले का कार्य अधूरा रहने से ग्रामीणों ने रोष जताया

पूंडरी। पूंडरी के पास स्थित गांव मोहना में कैथल से करनाल तक बनाई जा रही सड़क व नाले के कारण समस्या बनी हुई है। जिसके कारण ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि पिछले दो वर्षों से सड़क के निर्माण का कार्य चला हुआ है। सड़के के साथ-साथ गांव में जो पानी निकासी के लिए नाला बनाया जा रहा है, वह ठेकेदार द्वारा कई महीनों से अधूरा छोड़ दिया गया। जिसकी वजह से नाले का पानी सड़क पर भर जाता है और सड़क के साथ बने घरों में भी घुस जाता है। जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से बार-बार सड़क भी टूट जाती है और अधूरे पड़े नाले से दुर्घटनाएं भी घटती है। ग्रामीण घनश्याम दास, महीपाल, रामफल, भीम सिंह, पालाराम व ऋषिपाल ने बताया कि कई बार ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों व संबंधित ठेकेदार से मिलकर भी समस्याओं से अवगत कराकर नाले के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए कह चुके हैं।

कोविड-19 से शहर में दहशत का माहौल, रोजाना बढ़ रहे मरीज

एक परिवार के चार, कम्पनी से तीन कर्मचारियों समेत 25 पॉजिटिव

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में कोविड-19 के बृहस्पतिवार को 25 नए मामलों की पुष्टि की गई। जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों के अलावा डबुआ सब्जी मंडी कमेटी के कार्यालय में बैठने वाला एक व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही एक निजी कम्पनी में काम करने वाली एक महिला समेत तीन कर्मी पॉजिटिव है। इनमें से कुछ को होम आईसोलेट किया गया है तो कुछ को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वहीं रिपोर्ट लेने पहुंचे दो पॉजिटिव व्यक्तियों को आनन फानन में बीके अस्पताल से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। एक पॉजिटिव की मौत।

यहां से है पॉजिटिव

ईएसआई डॉक्टर समेत 5 के अलावा जवाहर कालोनी से एक ही परिवार के चार सदस्य पॉजिटिव पाये गए है। यह सभी कोविड-19 की चेन के जरिये पॉजिटिव हुए है। इनके घर में 65 वर्षीय एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला था। वह दिल्ली में हेल्थ केयर वर्कर है। वह एक मरीज के सम्पर्क में आने से पॉजिटिव हुआ था। उसके सम्पर्क में आने से परिवार के चार सदस्य और कोविड-19 से ग्रस्त हो गए। उसके सम्पर्क में आए चार सदस्यों में 40 वर्षीय व्यक्ति, 35 वर्षीय महिला, 12 और नौ वर्ष के बच्चे शामिल है। इसके अलावा सेक्टर-18 से 54 वर्षीय एक व्यक्ति, ऑटोपिन तिलक नगर से 40 वर्षीय व्यक्ति, सेक्टर-55 से 39 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। यह सभी होम आईसोलेट किए गए है। वहीं शिवदुर्गा विहार से 25 वर्षीय व्यक्ति, मेवला महाराजपुर से 34 वर्षीय व्यक्ति, डबुआ मंडी मार्केट कमेटी के दफ्तर से 40 वर्षीय व्यक्ति, बसेलवा कालोनी से 38 वर्षीय व्यक्ति, रामनगर कालोनी से 21 वर्षीय एक महिला पॉजिटिव पाई गई। इन सभी को ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। वहीं देर शाम आए आंकड़ों में मेडिकेयर नामक एक कम्पनी के तीन कर्मचारी पॉजिटिव मिले है। जिसमें सेक्टर-11 स्थित एक पीजी में रहने वाला 30 वर्षीय व्यक्ति और डबुआ कलोनी की 23 वर्षीय महिला को ईएसआई में दाखिल कराया गया है। जबकि कुंदन कालोनी, बल्लभगढ़ के रहने वाले एक 27 वर्षीय व्यक्ति को होम आईसोलेट किया गया है।

यह है आंकड़ा

डा. रामभगत ने बताया कि जिले में अब तक 10658 यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 3635 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 7016 लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 10382 होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 10397 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 9572 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 549 की रिपोर्ट आनी शेष है। अब तक 287 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 101 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा 30 पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार ठीक होने के बाद 138 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक आठ मरीजों की मौत हो चुकी है जिसमें कोरोना के साथ-साथ अन्य विभिन्न बीमारियां भी कारण रही।

लापरवाही : कोरोना पॉजिटिव खुद आकर ले रहे है रिपोर्ट

कविता। फरीदाबाद

कोविड-19 में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही कहीं जिले पर भारी न पड़ जाए। क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति खुद ही रिपोर्ट लेने बीके सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में वह कितने लोगों को पॉजिटिव करेंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहीं बीके सिविल अस्पताल प्रबंधन भी लापरवाही बरत रहा है। गत रविवार को दाखिल एक महिला की डिलीवरी के बाद रिपोर्ट आने पर उसे बीती रात पॉजिटिव घोषित किया गया। महिला भी सामान्य मरीजों के साथ भर्ती थी। पिछले 24 घंटे में बीके अस्पताल से तीन पॉजिटिव मिले हैं।

बीके पहुंचे सात पॉजिटिव

बीके अस्पताल में आईडीबीएससी लैब में जांच के दौरान फोन नम्बर, पता, मरीज का नाम सब लिखा जाता है। उसके बाद कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें सीएमओं दफ्तर के पास दी जाती है। पॉजिटिव मरीजों को फोन व पते के आधार पर सीधा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है।

लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार सीएमओ कार्यालय के नजदीक से पॉजिटिव मरीजों ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। बुधवार को करीब छह और बृहस्पतिवार की सुबह एक पॉजिटिव को यहीं से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। इससे साफ जाहिर है कि कोरोना के जिला नोडल अधिकारी लापरवाही बरत रहे है।

बीके से 24 घंटे में तीन पॉजिटिव, सामान्य मरीज व स्टाफ में दहशत

अस्पताल के अंदर भी लापवाही

बीके सिविल अस्पताल में पिछले 24 घंटे में दो महिलाओं समेत तीन पॉजिटिव मिले है। दोनो महिलाओं ने गर्भावस्था में जांच के लिए सैम्पल दिया था। दोनों की रिपोर्ट न आने से पहले डिलीवरी हो गई। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरतते हुए दोनों को विभिन्न कमरों में अन्य मरीजों के साथ भर्ती कर दिया। पहले मामले में छह लोगों को और दूसरे मामले में किसी भी कर्मचारी को क्वारेंटाइन नहीं किया। वहीं आईसोलेशन में दाखिल एक मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। जबकि यह मरीज अपातकालीन कक्ष में ईलाज को आया था। जिससे उसके सम्पर्क में दो स्टाफ और एक चिकित्सक आए। इन्होंने उसका इलाज और जांच के लिए भेजा था। इन्होंने क्वॅरेंटाइन न करने की शिकायत अभी अधिकारियों से की। लेकिन कुछ अधिकारियों ने तो उनके फोन तक उठाने बंद कर दिए।

आज चल सकती है दो स्पेशल ट्रेन

फरीदाबाद। बिहार के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन की तरफ से सरकार से दो स्पेशल ट्रेने चलाने की मंजूरी मांगी गई दी गई है। यह ट्रेने शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया और भागलपुर के लिए चलेगी। जिसमें एक ट्रेन की मंजूरी मिल गई है, दूसरी ट्रेन की मंजूरी जल्द मिल जाएगी।

जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन श्रमिकों को भेजने की तैयारियों में लगा हुआ है। लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

जिले में कंटेनमेंट जोन की सूची संशोधित, बने 59 जोन

फरीदाबाद। जिलाधीश यशपाल ने जिले में कंटेनमेंट जोन की सूची संशोधित की है, जिसके तहत नए क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल किए हैं। जिलाधीश ने बताया कि18 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि गांव पलवली, डबुआ कॉलोनी, सेक्टर-88 स्थित एफ ब्लॉक, चावला कॉलोनी स्थित डी ब्लॉक, एनआईटी-1 स्थित ब्लॉक-ए, बी, सी, एच और एनआईटी-2 स्थित ब्लॉक-जी, सेक्टर-28 में प्लाट नं. 682 पी से 889 पी, 835 पी से 905 पी, 817 पी से 834 पी, 851 पी से 876 पी और 781 पी से 816 पी, सेक्टर-28, प्लाट नं. 972 पी से 984 पी, बाढ़ मोहल्ला ओल्ड फरीदाबाद, जवाहर कॉलोनी में ब्लॉक बी और गली नं 6 में मकान नं. 1945 से 1954, मुजेसर कि गली नं. 2, मुजेसर मैन मार्किट रोड, गोयल कॉलोनी, कोहली मोहल्ला, मुजेसर, ग्रीन फील्ड कॉलोनी में प्लाट नं. 1079 से 1096, 796 से 802, 908 से 925, 926 से 930 और और 931 से 976 का ब्लॉक, प्लाट नं. 2719 से 2741, 2742 से 2753, 2802 से 2809 और प्लाट नं. 2887 से 2888 का ब्लॉक, प्लाट नं. 828 से 848, 849 से 866, 991 से 995, 1024 से 1027 और 986 से 990, 996 से 999, 1020 से 1023 का ब्लॉक, प्लाट नं. 746 से 770, 771 से 783 और 807 से 827 का ब्लॉक, प्लाट नं. 312 से 321, 322 से 353, 428 से 461, 407 से 424, 428 से 1041, 425 से 427 और नगर निगम द्वारा अधिकृत लेबर क्वार्टर, प्लाट नं. 2449 से 2446, 2467 से 2486, संजय कॉलोनी, सेक्टर 23 नगर निगम के मकान नं. 9470 गली नं. 294 से 295 नजदीक गौंछी ड्रेन, मकान नं. 9491 गली नं. 295, दूकान नं. 8810 नजदीक गली नं. 285, प्लाट नं. एफ-12, माइक्रोटेक इंडस्ट्रीज गौंछी ड्रेन, गली नं. 36 का एरिया, सेक्टर-23 में मकान नं. 1235 सेक्टर 23ए, पार्क एवं मार्किट के सामने, मकान नं. 1648, 1353, सेक्टर 23ए फाउंटेन पार्क के सामने, दूकान नं. 48 गली नं. 8 रोयल प्रॉपर्टी 22 मैन फीट रोड, दूकान नं 13 गली नं. 3, मोहर लेडीज टेलर 22 फीट रोड, सेक्टर 62 के प्लाट नं. 1136 से 1145, 1520 से 1563, 1886 से 1961 पी, 1962 से 1965, 2028 से 2031, 2032 से 2041, 2079 से 2087 पी, 2935 से 2937 पी, 2980 पी से 2982, सेक्टर-62, आदर्श कॉलोनी का एरिया, नजदीक मुल्ला होटल, दूकान नं. जे-1 (सुमित ट्रेडर्स-ओरिद्सा बी.एस. टेम्पो सर्विस), दूकान नं. आर-370 (वैष्णो देवी मंदिर के सामने बत्रा किरयाना स्टोर), दूकान नं. आर-303 (वाइन एवं कुनाल सोडा शॉप राम सिंह ऑटो सेंटर के सामने) और मकान नं. जे-59, वाल्मीकि गली सेंट्रल वाटर वर्क्स कमीशन, प्लाट नं. 288 से 701, सेक्टर 18, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कंटेनमेंट जोन-16 की सूची में गांव फतेहपुर चंदीला में अधिवक्ता सुखवीर सिंह, फिरे चंदीला, विजय चंदीला, और पंचायत भवन का एरिया, कंटेनमेंट जोन-17 की सूची में गाँव मोहला का एरिया, गांव सीही, बल्लभगढ़ की शिव शारदा कॉलोनी, मवई रोड से शिव मंदिर, शिव मंदिर से महिंद्रा बिल्डिंग मटेरियल शॉप, तिलपत, सेक्टर-91, सेक्टर-10 में प्लाट नं. 996 से 966, प्लाट नं. 739 से 759 सेक्टर-10, इंद्रा कॉलोनी सेक्टर-5, ऑटो पिन झुग्गी नाले के पास रेलवे रोड के बीच और सेक्टर डिवाइडिंग रोड, सेक्टर-22 और 24, सेक्टर-14 में प्लाट नं. 8 पी से 21 पी, 75 पी से 90 पी, 91 पी से 114 पी, 161 पी से 198 पी और प्लाट नं. 168 पी से 175, 183 से 191 पी, 215 पी से 218, 235 से 238 पी, 116 पी से 141 पी, सेक्टर-7 में प्लाट नंबर 687 पी से 699 पी, 834 पी से 853, 714 पी से 727 पी, सेक्टर डिवाइडिंग रोड सेक्टर 7-8, प्लाट नं. 780 पी से 803 पी, प्लाट नं. 2321 से 2334, 2269 से 2275, 2362 से 2371, 2399 से 2412, गांव मवई में साईं कॉलोनी, फायरिंग रेंज रोड, साईं मंदिर रोड, छाय्न्सा डिस्ट्रीबिउट्री का एरिया और अन्य कई इलाके शामिल किए गए हैं।

अखबार वितरकों को राशन बांटा

फरीदाबाद। फरीदाबाद में अमन गोयल का नाम युवा भाजपा नेता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में सभी जानते है। अमन गोयल ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए बृहस्पतिवार को अखवार वितरकों को राशन वितरित किया। अमन गोयल लॉकडाउन में जरूरतमंदो के साथ सदैव खड़े होकर उनके दु:ख दर्द को बाटते हुए उनकी हर संभव मदद करने के लिए अग्रणी रहते है। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप निरंतर अपने चरम पर है। अमन गोयल प्रतिदिन कहीं न कहीं अपने क्षेत्र की जनता के हित में यथा संभव मदद पंहुचा रहे है। बृहस्पतिवार को अमन गोयल ने तिगांव विधानसभा में विधायक राजेश नागर व सुरजीत अधाना जिला पार्षद के साथ घरों में जाकर समाचार पत्र वितरण करने वाले लोगों को राशन, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई, सैनिटाइजर, मास्क देते हुए सुरक्षित रहने की अपील की।

बच्चों की ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित

फरीदाबाद। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के निर्देशानुसार एवम उपायुक्त महोदय फरीदाबाद के मार्गदर्शन में लॉकडाउन में बच्चों का तनाव कम करने के लिए गत आठ से 15 मई तक प्रदेश स्तरीय बाल प्रतियोगितओं का आयोजन किया गया था। इस बारे में जिला बाल कल्याण अधिकारी एसएल खत्री ने बताया कि गत दस मई को कविता प्रतियोगिता के लिए 357 ऑनलाइन विडियो क्लिप, भाषण प्रतियोगिता के लिए 308 ऑनलाइन विडियो क्लिप, निबंध लेखन में 354 ऑनलाइन विडियो क्लिप, कहानी प्रतियोगिता के लिए 206 व नकल प्रतियोगिता के लिए 56 ऑनलाइन विडियो क्लीप ईमेल द्वारा प्राप्त हुई। जिनका गत 28 मई को तीनो ग्रुपों के सभी सब-ग्रुप का परिणाम निकाला गया। निर्णायक मंडल की भूमिका रविंद्र कुमार मनचंदा, विनोद कुमार एवं गीता सिंह ने निभाई। विजेता बच्चों की सूची संग्लन है। इन प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को उनकी श्रेणी में आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं की दो-दो मिनट की वीडियो क्लिप तथा फोटो ई- मेल balbhawanfbd-competition@gmail.com पर अभिभावकों द्वारा भेजी गयी।

ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम ने दिया वृद्ध को सहारा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

दामाद द्वारा मारपीट कर घर से निकाले गए एक वृद्ध को नवजन मोर्चा समिति ताऊ देवीलाल वृद्धाश्रम 2डी-ब्लॉक ब्लॉक ने सहारा देकर नेक काम किया है। आश्रम के संचालक किशन लाल बजाज को पैनल एडवोकेट रविन्द्र गुप्ता का फोन आया कि बीके अस्पताल के मेन गेट के पास एक वृद्ध लावारिस हालत में बैठा हुआ हैं। किशन लाल बजाज तुरंत अपनी धर्मपत्नी स्वर्णलता बजाज, सत्यपाल चौहान, सूरज आर्य और गौरव बजाज के साथ मौके पर पहुंचे और वृद्ध को अपने साथ लेकर आश्रम आए। पूछताछ करने पर वृद्ध ने अपना नाम जगधारी उम्र 83 वर्ष बताया। उसने बताया कि उसके दामाद ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया है। किशन लाल बजाज ने वृद्ध को आश्वासन दिया कि वह आश्रम को ही अपना घर समझे। जब तक चाहे वह यहां रह सकता है और उसके खाने पीने और पहनने का सारा इंतजाम नवजन मोर्चा समिति की देखरेख में किया जाएगा। किशल लाल बजाज ने बताया कि इसकी लिखित सूचना 3 नंबर पुलिस चौकी में दे दी जाएगी।

उपायुक्त ने किया बाजारों का औचक निरीक्षण

फरीदाबाद। उपायुक्त यशपाल ने वीरवार को विभिन्न सेक्टरों व बाजारों में खुली हुई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जिसमें कुछ स्थानों पर अनियमितता मिली तथा कुछ स्थानों पर सभी हिदायतों की अनुपालना पाई गई।

उपायुक्त ने इस दौरान सेक्टर-7 व सेक्टर-10 की मार्केट की दुकानों का निरीक्षण किया, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार सभी दुकानें ठीक प्रकार से खुली हुई पाई गई। इन सेक्टरों के अलावा फरीदाबाद क्षेत्र के सेक्टर-29 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर-19 व सेक्टर-15 की मार्केट में खुली हुई दुकानों में अनियमितता पाई गई, जिस पर उपायुक्त ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे दाएं व बाएं के नियमानुसार ही दुकानें खोलें। उन्होंने लोकल कमेटियों के सभी इंचार्ज को निर्देश दिए कि वह अलाट किए गए क्षेत्र की मार्केट में खुली सभी दुकानों व मार्केट में आने वाले सभी लोगों के लिए जारी निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि लोकल कमेटियों का गठन बाजारों में खुली दुकानों पर सभी एसओपी को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है।

पुलिस ने पहुंचाया बच्ची के जन्मदिन का केक

फरीदाबाद। कोविड-19 में घर में बच्चों का जन्मदिन परिजनों के लिए मनाना मुश्किल हो गया है। ऐसा ही ग्रीन फिल्ड कालोनी में एक दस वर्षीय बच्ची के साथ हुआ। बच्ची का जन्मदिन था और पिता घर पर नहीं थे। गृहणी मां के लिए बच्ची का जन्मदिन माानाना मुश्किल हो गया। ग्रीन फिल्ड पुलिस चौकी इंचार्ज सुनील को जब इसकी जानकारी मिली तो वे बच्ची के लिए केक लेकर उसके घर पहुंच गए और परिवार के साथ उसका जन्मदिन मनाया। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि चौकी इंचार्ज सुनील एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए उसके घर केक लेकर पहुंचे और बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस बच्ची के पिता लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे हुए हैं। बच्ची की जिद के बारे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए केक पहुंचाया। बच्ची परिजनों ने इसके लिए कोरोना योद्धा सुनील का आभार जताया है।

एनएसयूआई ने बांटा जरुरतमंदो को राशन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष विकास फागना ने बुधवार को राशन बांटा। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को घरो में ही जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाने की अपील की।

इस अवसर पर उन्होंने जरुरतमंदो को राशन बांटा, जिसमे तेल, चीनी, चावल, आटा, दाल आदि थे। इस अवसर पर विकास फागना ने कहाकि सभी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निवास पर नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू भारत में स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। आधुनिक भारत में उन्होंने हर हाथ को काम मिले, इसलिए जगह जगह भारी उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारी कम करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहाकि ने कहा कि महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आसीन रहे। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार थे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे।

देश के लिए पंचवर्षीय योजनाए बनाकर फैक्ट्रियां, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, किसानों के लिए योजनाए, छात्रों को हक़ व युवाओ के लिए रोजगार पैदा करके जिस देश मे सुई तक नही बनती थी, उस देश की अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया।

दीपक बनाए गए प्रवक्ता

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा एक जिम्मेदार और शहर की सबसे पुरानी संस्था है जो हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए प्रयासरत रही है।

उक्त विचार दीपक यादव ने एसोसिएशन के प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर अपनी बात रखते हुए कहा कि एसोसिएशन जो उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए वे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश डागर का धन्यवाद प्रकट करते हैं साथ ही वे यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे संस्था की सभी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे एसोसिएशन और अभिभावकों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित कर सकें ताकि स्कूलों और अभिभावकों के बीच आपसी सहयोग से शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। दीपक ने कहा कि स्कूल और अभिभावक दोनों मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। दीपक ने सरकार से स्कूल एवं अभिभावकों के सहयोग करने की अपील की।

छात्रों को प्रोमोट करने को भेजा ज्ञापन

फरीदाबाद। एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष विकास फागना ने बताया कि एनएसयूआई हरियाणा ने महामहिम राज्यपाल, हरियाणा को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मांग की है, कि बिना परीक्षाओं के छात्रों को प्रोमोट किया जाए। राज्यपाल को लॉकडाउन के समय एनएसयूआई हरियाणा द्वारा प्रदेश भर में किए गए जनहित व जरूरतमंदों की सहायता के कार्यो के बारे भी विस्तार पूर्वक बताया। विकास फागना ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा लेने के पुख्ता इंतजाम नही है ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प छात्रहित में नही है।

सपनों का पीछा करते हुए जीवन में कभी हार न माने: सोनल

आईएएस अधिकारी ने विद्यार्थियों के साथ सांझा किये जीवन के अनुभव

जेसी बोस द्वारा किया गया आनलाइन प्रेरक व्याख्यान का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

कोरोना संकट के बीच विद्यार्थियों में आत्म-प्रेरणा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद के डीन स्टूडेंट वेलफेयर विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक आनलाइन प्रेरक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड की कार्यकारी अधिकारी तथा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी सोनल गोयल मुख्य वक्ता रही।

व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने की। कुलपति ने मुख्य वक्ता का स्वागत किया और विद्यार्थियों के लिए प्रेरक व्याख्यान देने के लिए श्रीमती सोनल गोयल का आभार जताया। व्याख्यान सत्र का आयोजन डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉ. लखविंदर सिंह की देखरेख में लिया गया, जिसका संयोजन डिप्टी डीन डॉ. सोनिया द्वारा किया। कुलसचिव डॉ. एसके गर्ग भी उपस्थित थे।

भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनने की सोनल गोयल की सफलता की कहानी का उल्लेख करते हुए कुलपति प्रो दिनेश कुमार ने कहा कि वह हरियाणा के पानीपत जैसी जगह से आती हैं और सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। सोनल गोयल ने अपने व्याख्यान में विद्यार्थियों के साथ अपने जीवन और अनुभवों को साझा किया और उन्हें सपनों का पीछा करते हुए जीवन में कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2006 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास किया, लेकिन साक्षात्कार के दौर में नहीं पहुंच सकीं, लेकिन 2007 में उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इसे 13वीं अखिल भारतीय रैंक के साथ उत्तीर्ण किया। उन्होंने कहा कि आईएएस के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के प्रति स्पष्ट होना चाहिए कि वे आईएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी बनना उसके लिए समाज सेवा और समाज को सार्थक योगदान देने का एक अवसर था। उसने कहा कि आईएएस बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को अपने विचारों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और अपने सपनों को पूरी लगन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों को उपयोगी टिप्स भी दिए और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान वैकल्पिक करियर विकल्प चुनने का सुझाव भी दिया। सोनल ने बताया कि उनके पिता, जो पेशे से एक सीए थे, ने यह सुनिश्चित किया कि यदि वह सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती तो उनके पास एक अन्य कैरियर विकल्प तैयार होना चाहिए। इस प्रकार, सोनल ने 2004 में अपना सीएस पूरा किया और जल्द ही कानून की पढ़ाई शुरू कर दी और वह भी पूरी कर ली। इसके साथ ही, उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी।

सत्र को विश्व प्रकाश मिशन के अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी राकेश सेठी ने भी संबोधित किया। विश्व प्रकाश मिशन एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए सेठी ने कहा कि अपने जीवन में उन्होंने समाज की सेवा करने का सपना देखा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया। अब तक उनका ट्रस्ट से 100 से अधिक विद्यार्थी छात्रवृत्ति का लाभ उठा चुके है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में उच्च नैतिकता बनाए रखते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

संकट में उद्धव ठाकरे

सहयोगियों व भाजपा के निशाने पर

सच्चे नेतृत्व की परीक्षा संकट आने पर होती है और कोविड-19 वैश्विक महामारी को अनेक समाधानों की आवश्यकता है। लेकिन राजनीति में जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वालों पर दोषारोपण किया जा सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत गठबंधन सरकार संकट में है क्योंकि यह तेजी से वायरस संक्रमण पर अपनी पकड़ खोती जा रही है जो यहां पूरे देश में सर्वोच्च है और कुल मामलों का 30 प्रतिशत यहीं हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे शिवसेना नेता का कोई प्रशासनिक या जमीनी अनुभव नहीं है, राज्य भाजपा के नेता सशक्त हैं तथा उद्धव के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-रांकापा व कांग्रेस में वैचारिक मतभेद हैं। उनकी गठबंधन सरकार में मराठा क्षत्रप रांकापा सुप्रीमो शरद पवार ने प्रमुख मंत्रालयों पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस को भी कुछ मंत्रालय मिले हैं, पर वह तीसरे स्थान पर है तथा प्रशासन में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इन दबावों में सरकार किसी तरह अपना संख्याबल बनाए हुए है, जबकि भाजपा उसे उलटने के लिए मौके की तलाश में है। ठाकरे ने भले ही शिवसैनिक के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा किया हो, पर वे कागजी शेर के सिवा और कुछ नहीं हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होने के बाद वे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सारे संसाधन लगा रहे हैं, पर भाजपा रोज उनकी गलतियां बताती है। शिवसेना भले ही ऐतिहासिक रूप से बृहन्मुंबई नगर निगम-बीएमसी पर कब्जे में सफल रही हो, पर कोविड-19 से निपटने में वह पूर्ण विफल रही है। हर घंटे बीमारों की संख्या बढ़ने के साथ ही बीएमसी व शिवसेना असहाय अनुभव कर रहे हैं। इसका कारण शिवसेना की अनुभवहीनता है।

वह हमेशा 'रिमोट कंट्रोल' से सत्ता चलाती रही है, जबकि भाजपा गठबंधन की नेता रही है। शिवसेना ने पवार या कांग्रेस के प्रशासनिक अनुभव का लाभ भी नहीं उठाया है। सहयोगी इतने नाराज हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य में कोविड प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं कह सकती है क्योंकि वह निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। कुछ मंत्री व विधायक उद्धव के कामकाज तथा पुराने नौकरशाहों पर विश्वास से खुश नहीं हैं। सालों से मुंबई में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की लापरवाही हुई है तथा इस बीमारी के संकट से सरकारी अस्पताल चरमरा गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रवासियों के मामले में दूसरे राज्यों के समकक्षों से संवाद नहीं कर सके हैं। मुंबई से लौटने वाले अधिकांश प्रवासियों ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके भोजन व शरणस्थलों की चिन्ता नहीं की तथा उनके प्रति कोई संवेदना नहीं प्रदर्शित की। मामला इस तथ्य से और खराब हुआ है कि शिवसेना के धारावी जैसे पुराने गढ़ वायरस के शिकंजे में फंसे हैं, जबकि यहां रहने वाले मुंबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उद्धव ठाकरे उनका समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। वायरस के बहुआयामी हमले में वे स्वाभाविक रूप से सबसे संकटग्रस्त व्यक्ति लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे में अपने पिता जैसा प्रभामंडल नहीं है और बालासाहब को ऐसे किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा था।

ऐसे में भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी पार्टी के नेता को अतीत में अनुभव को देखते हुए जनता का कुछ विश्वास प्राप्त है और यह समय अपनी प्रासांगिकता बहाल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना नेता रहे नारायण राणे के साथ उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। राणे ने मुंबई में सेना बुलाने की मांग भी की है। फड़नवीस स्वयं को ऐसे भाजपा नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो केन्द्र-राज्य संबंधों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकता है तथा केन्द्रीय संसाधनों से वायरस संक्रमण पर आक्रामक तरीके से विराम लगा सकता है। वे केन्द्र से ज्यादा सहायता पाने के लिए 'राज्य व केन्द्र में एक पार्टी' का तर्क भी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल केवल यह है कि क्या राज्य में कोई आपरेशन लोटस शुरू होने वाला है।

सेना की गरिमा बनाए रखना जरूरी

सेना की गरिमा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन शायद अब वह सामाजिक व राजनीतिक दबावों का सामना कर रही है। इससे वह अपने संस्थान के प्रति महत्वपूर्ण दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव कर सकती है।

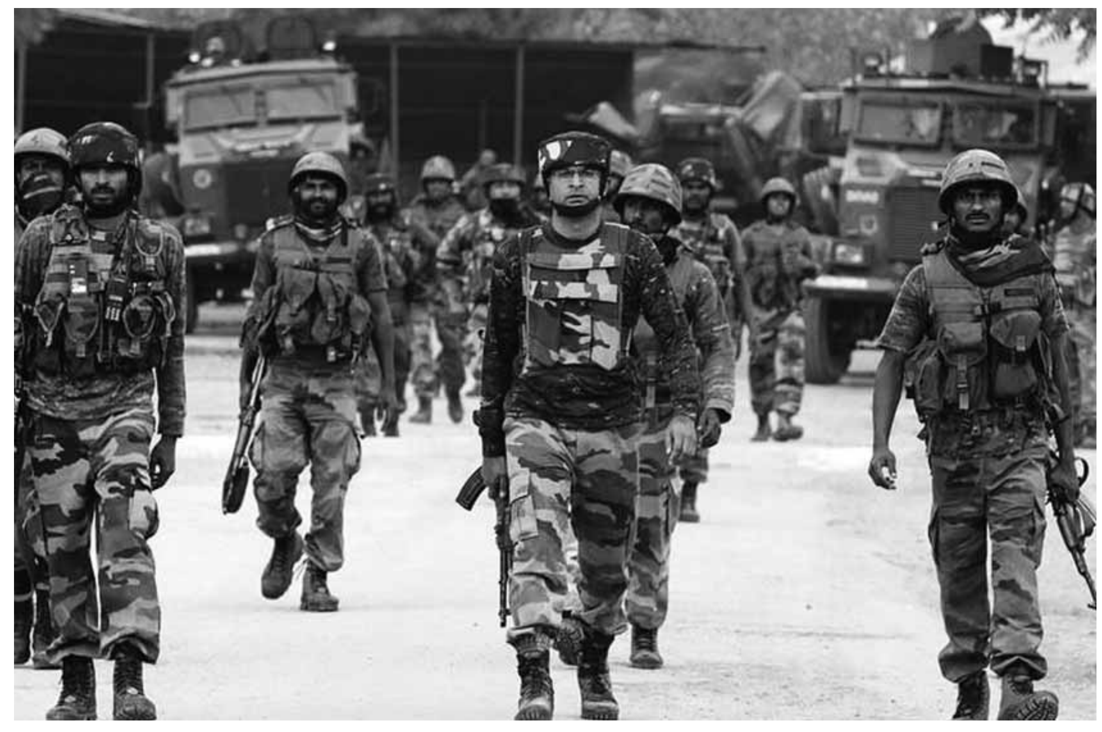

भूपिंदर सिंह
लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पूर्व उपराज्यपाल हैं

देश की 'रक्षक शक्ति', यानी सशस्त्र सेनाओं के प्रति पूरे समाज का विश्वास और उसकी शक्ति में आस्था की भावना महत्वपूर्ण है। यह बात खासकर भारत जैसे सहभागी लोकतंत्र के बारे में सही है जहां 'वर्दी' को अराजनीतिक, बहिर्मुखी, अहस्तक्षेपकारी व देशभक्त संस्था के रूप में 'संयम' व 'गरिमा' प्रदान की गई है। इसी कारण उसे संवैधानिक रूप से जनता की इच्छा के आधीन रखा गया है जिसका प्रतिनिधित्व सिविलियन सरकार करती है। संस्थान के भीतर कुछ लोगों या लोगों के समूह की गलतियों व विकृतियों के बावजूद 'संस्थान' अपनी चमक बनाए रखने में सफल रहा है और वह 'भारत के विचार' का शानदार उदाहरण है।

सशस्त्र बलों की अंतर्निहित संरचना सैनिकों व उनकी रेजीमेंटों को भारत की अनेक नस्लों व विविधताओं से बांधती है। उनको सैद्धान्तिक रूप से पश्चिमी भारत के गरम रेगिस्तानों में इन्फ्रेंट्री ब्रिगेड कहा जा सकता है। इनमें पूर्वोत्तर की नगा बटालियन, दक्षिण में 'थंबियों' की मद्रास बटालियन तथा जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फ्रेंट्री बटालियन शामिल हैं जिसमें कश्मीर घाटी और जम्मू मैदानों का समान प्रतिनिधित्व है। ये संयुक्त रूप से सीमापार से आने वाले किसी खतरे से भारतीय संप्रभुता की रक्षा करती हैं। इस संस्थान की संस्कृति, प्रशिक्षण व भावना ऐसे सामाजिक 'विभाजनों' को किनारे कर उनको लौह कैंटूनमेंटों में बांटती है जहां बैरकों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं दिखता है। इस प्रकार अनेकानेक जनमत सर्वेक्षणों में नागरिकों की नजर में 'भारतीय सैनिक' सर्वाधिक 'सम्मानित' पाया गया है।

लेकिन सशस्त्र बलों के लीक से हटने पर इस मूलभूत समन्वय को खतरा पैदा हो जाता है। आंतरिक मामलों में लगातार शामिल करने के कारण इस पर राजनीतिक झुकाव के आरोप लगते हैं। यह अपनी परंपरागत भूमिका, रुझान व परंपरा के विपरीत अन्य कामों में शामिल होते हैं। इससे संस्थागत दृढ़ता पर संकट आता है जो द्रविण आंदोलन, पूर्वोत्तर में विद्रोह तथा जम्मू कश्मीर के संकट से निपटने में सफल सिद्ध हुई है। सामाजिक दबावों, विकृतियों व दृष्टिकोणों को अनदेखा करने का सर्वोत्तम उदाहरण 26 वर्षीय सैनिक औरंगजेब है, जिसका पाक-समर्थित आंतकियों ने अपहरण कर लिया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी। उनके पिता ने यह भी सुनिश्चित किया कि औरंगजेब के भाई भी भारतीय सेना की 'वर्दी' पहनें। इस प्रकार उन्होंने अनजाने ही सैनिक छावनियों के बाहर कभी-कभी होने वाली विकृत, गलत व निरर्थक बातचीत को खारिज कर दिया।

सभी सरकारी संस्थानों की तरह सशस्त्र बलों के भी अपने सरोकार हैं जिनके मुख्यत: दो आयाम हैं। पहला, वार्षिक बजटीय आबंटन और दूसरा, इज्जत के गैर-वित्तीय व अगणनीय आयाम जो 'सैनिक' आत्मा को परिभाषित करते हैं। 'भारतीय सैनिक' को स्वाभाविक रूप से भावनात्मक संदर्भ में पेश करने वाली अवस्थापना का राजनीतिक दृष्टिकोण रक्षा बलों के प्रति वार्षिक बजटीय आबंटनों के माध्यम से अलग कहानी कहता है और सत्ता की पसंद उजागर करता है। यह सच है कि बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है। लेकिन सीमा की स्थितियों को देखते हुए सैनिक आवश्यकताओं के लिए यह जरूरी है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वेतन, पेंशन या काम व जीवन के बीच संतुलन अथवा अन्य भौतिक उपलब्धियों के मामले में सैनिकों की स्थिति अन्य सरकारी समकक्षों से बेहतर नहीं है। ओआरओपी की भावना का पूरी तरह सम्मान नहीं हुआ है। आधुनिकीकरण में भी आमतौर से विलम्ब होता है या राफेल की तरह जरूरतों में कमी की जाती है।

> **भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिक भावना की अपनी विशिष्ट परंपरा व पहचान है। यह नेहरूवादी अनदेखी और बाद वाली राजनीतिक अवस्थापनाओं की लचर व क्षेत्रीयतावादी भावनाओं तथा सैनिक छावनियों की सुरक्षा में सामाजिक अशांति झेलने में सफल रहे हैं।**

थियेटर कमांड, दो मोर्चों पर युद्धक क्षमता तथा संयुक्त कार्रवाई आदि ढांचागत परिवर्तनों को बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, पर अब तक केवल चीफ आफ डिफेंस स्टाफ-सीडीएस की नियुक्ति जैसा मामूली परिवर्तन ही हुआ है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण गेम-चेंजर है क्योंकि नीतिगत मामलों पर बहु-प्रतीक्षित सुरक्षा सलाह मिलेगी, अनेक संस्थागत सरोकारों का समाधान होगा तथा आंतरिक अशांति की स्थिति में बेलगाम तरीके से सशस्त्र बलों को बुलाने की समस्या पर विचार होगा। इससे सशस्त्र बलों को सरकारी सीमाओं व आवश्यकताओं से सुरक्षित रखने में भी सहायता मिलेगी। अब तक केवल एकपक्षीय रूप से सरकारी सीमाओं व आवश्यकताओं की बात ही सामने आई है जिससे परंपरागत जुड़ाव थोड़ा असहज हुए हैं। रक्षा सरोकारों को गहराई तक प्रभावित करने वाली चीजें या तो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं या उनके बारे में बात नहीं हो रही है। तथाकथित 'सुधार' खर्च घटाने के प्रयोगों के रूप में भी सामने आ रहे हैं, जैसे, तीन वर्षीय शार्ट-कमीशन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों-सीएपीएफसे सात वर्ष के लिए पार्श्व प्रवेश। हालांकि, इससे आंकड़ों के विचार से सैनिकों की कमी पूरी हो सकती है या सिविल व सीएपीएफ के बहुत से लोगों को 'सैनिक अनुभव' मिल सकता है, पर इससे अधिकारियों में विशेषज्ञता, गुणवत्ता या गंभीरता नहीं समाहित होगी क्योंकि उनका कार्यकाल सीमित होगा। 'प्रशिक्षण स्कूल' के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग गौरव का विषय हो सकता है। इससे कुछ लोगों का संस्था के असाधारण मानकों से 'सीमित' परिचय हो सकता है, पर इससे संस्था की सीमाओं में कोई विस्तार नहीं होगा।

भारतीय सशस्त्र बलों में सैनिक भावना की अपनी विशिष्ट परंपरा व पहचान है। यह नेहरूवादी अनदेखी और बाद वाली राजनीतिक अवस्थापनाओं की लचर व क्षेत्रीयतावादी भावनाओं तथा सैनिक छावनियों की सुरक्षा में सामाजिक अशांति झेलने में सफल रहे हैं। आज छावनियों के लगभग सभी फाटक खोल दिए गए हैं जिससे सामाजिक व राजनीतिक भावनाओं से सैनिकों के प्रभावित होने का कटु यथार्थ सामने है। वास्तव में स्वतंत्रता के फौरन बाद से ही संस्थागत विमर्श में गिरावट आई थी, पर आज सभी सामाजिक वायरसों के संक्रमण का खतरा संस्थान के मनोवैज्ञानिक चरित्र पर मंडरा रहा है। उसकी 'शब्दहीन' प्रकृति जरूरी है, पर विडंबना है कि अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद इसे गलत तरीके से खामोशी समझा जा रहा है और सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

स्पष्ट रूप से सशस्त्र बलों की ऐतिहासिक समानता तथा पेशेवर क्षमता का लाभ उठाने के लिए इसे अनेक अनावश्यक दिशाओं में मोड़ा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही समान रूप से संस्था के सरोकारों को संबोधित करने की भावना का अभाव है। 'वर्दी' पर किसी राजनीतिक पकड़ या झुकाव इसे पुलिस बलों जैसा बना देगा। राष्ट्रीय व संस्थागत नेतृत्व को उसी जोश से 'दूरी' व 'सरोकार' बनाए रखने चाहिए जिससे उसने सरकारी सीमाओं और आवश्यकताओं को स्पष्ट किया है। दशकों से 'स्पिट एंड पालिश' की आवश्यकता को देखते हुए 'ग्लिंट इन द बायोनेट' बनाए रखी गई है। गरिमा व अभिप्रेरणा ने सुनिश्चित किया है कि सशस्त्र बल अनावश्यक नाटकीयता व विकृतियों से बचे रहें। यदि अत्यधिक महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण , समानता तथा वादा की गई गारंटियां पूरी करना संभव न हो तो राजनीतिक आकाओं के सामने झुकना या रचनात्मक दुरुपयोग कोई विकल्प नहीं है।

कराची विमान दुर्घटना के सबक

> **यह तथ्य हवाई अड्डे के निकट ऊंची इमारतों के मूलभूत खतरों को उजागर करता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर रिहायशी इलाके में मकानों पर गिरा।**

अभिजित भट्टाचार्य
(लेखक समसामयिक मामलों पर स्तम्भकार हैं)

उड़ान के दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। विचारणीय तथा अविचारणीय। मनुष्य और मशीन अंतरापृष्ठ विचारणीय कारक का निर्माण करता है जबकि उड़ान पथ पर मौसम और अज्ञात परिदृश्य अविचारणीय कारक हैं। यदि विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है कि उसे अन्वेषकों द्वारा परिहार्य अथवा अपरिहार्य दुर्घटना की श्रेणी में विभक्त किया जाता है। अत:, 22 मई को हुई कराची विमान दुर्घटना को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? परिहार्य अथवा अपरिहार्य? इसके लिए, लाहौर-कराची फ्लाइट 8303 की दुर्घटना की विवेचना करनी होगी।

2004 में निर्मित एवं चायना सदर्न एयरलाइंस को बेचा गया एयरबस- ए 320-214 को पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने 2014 में खरीदा था। अधिकतम 77 टन भार ले जाने की क्षमता के साथ, लाहौर-कराची फ्लाइट में निश्चित रूप से पूरा भार नहीं लदा था क्योंकि आमतौर से 140 यात्रियों के बजाए यह केवल 100 लोगों को लेकर जा रहा था। लगभग 90 मिनट में 1,050 किलोमीटर की दूरी तय करना निश्चित रूप से ऐसे किसी भी विमान के लिए कोई बड़ा काम नहीं होता, खासकर जब दिन साफ हो।

इसके बावजूद, चीजें स्वाभाविक रूप से योजना के अनुरूप नहीं हुईं और विमान कराची रनवे से एक किलोमीटर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अत: गड़बड़ी कहां हुई? मनुष्य या मशीन? चलिए पहले मशीन पर ध्यान देते हैं। जैनेस आल दि वर्ल्ड एयरक्राफ्ट के अनुसार, एयरबस-ए 320-214 समय परीक्षित मजबूत विमान है, जो पहला सबसोनिक वाणिज्यिक विमान है जिसमें प्रमुख प्राथमिक संरचनाओं एवं केंद्रीकृत रखरखाव प्रणाली हेतु संयोजन होते हैं।

यह फ्लाई बाई वायर से सुसज्जित होता है, एक ऐसी प्रणाली जो इस हद तक विमान संरक्षण सुविधाएं समाहित करती है जिसे परम्परागत यांत्रिक नियंत्रण प्रणाली के साथ हासिल नहीं किया जा सकता। इसके कम्प्यूटर विमान की संरचनात्मक एवं एयरोडायनामिक सीमाओं का पायलट द्वारा उल्लंघन किए जाने की अनुमति नहीं देंगे।

यद्यपि थोड़ा जटिल है मगर उपरोक्त विवरण पाठकों को एयरबस-ए 320 के उड़ान नियंत्रण की प्रणाली के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए पायलट के हाथों में मुख्य उपकरण होता है। निस्संदेह फ्लाइट डाटा रिकार्डर एवं काकपिट ध्वनि रिकार्डर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के अंतिम क्षणों के बारे में जानकारी देने में मददगार होते हैं। सर्वप्रथम, विमान उड़ने योग्य था। दूसरे, पायलट उड़ाने में दक्ष था। तीसरे, लाहौर से उड़ान भरने के पश्चात, अपने निचले ढांचे को अंदर खींच लिया था। चौथे, मार्ग पर चलते समय कोई भी आपतकालीन संदेश भेजे जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई है। फिर नीचे आने के दौरान ऐसा क्या हुआ?

पायलट ने अचानक धरातल के निकट अंतिम क्षण में मेडे क्यों किया? (मेडे का अर्थ होता है तत्काल सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय काल)। विमान के निचले हिस्से क्यों खुल गए? दोषपूर्ण मापन अथवा दोषपूर्ण रीडिंग के कारण नीचे उतरने की दर और दृष्टिकोण की गति में तालमेल नहीं हो पाया? क्या काकपिट पर किसी के द्वारा कोई घातक हमला किया गया था? क्या उससे कोई अमेरिका निर्मित हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल, स्टिंगर ने आघात किया था, जिसका इस्तेमाल अफगान तालिबान धीमी गति से चल रहे नीचे उड़ने वाले सोवियत तथा अमेरिकी वायु सेना के विमानों पर किया करते थे?

चिंता का मुख्य कारण है जिस तरह से विमान का अंतिम चंद मिनटों के भीतर नियंत्रण नहीं किया जा सका, जो कम ऊंचाई पर था, और लैंडिंग उपकरण से संबद्ध हो चुका था। खबर मिली है कि कुछ असामान्य सी चीज हुई। दुर्घटनाग्रस्त विमान के पायलट ने कथित रूप से हवाई यातायात नियंत्रक की ओर से लैंडिंग से पूर्व विमान की गति एवं अक्षांश को लेकर दी गई तीन चेतावनियों की अनदेखा किया था और एटीसी को आश्वस्त किया था कि वो संतुष्ट है और स्थिति को संभाल लेगा। बाद में, विमान के पहिए खुल नहीं पाए और इंजन में गड़बड़ी आ गई।

पहला विचारणीय बिंदु यह है कि पायलट ने गति और अक्षांश को लेकर एटीसी की तीन चेतावनियों को अनदेखा क्यों किया? क्या वह विमान अथवा उसके उड़ान कौशल को लेकर अतिविश्वास में था? दूसरे, यदि विमान के पहिए लाहौर से उड़ान भरते समय अंदर चले गए थे लेकिन कराची में उतरने से पहले खुल नहीं पाए, यह जमीनी स्तर पर उचित देखरेख का अभाव हो सकता है। यदि ऐसा है तो मानवीय त्रुटि के कारण यह दुर्घटना हुई।

हालांकि, यदि विमान के इंजन में 90 मिनट की उड़ान के बाद कोई गड़बड़ी आ गई थी, लैंडिंग के ठीक पहले, तो इससे पुन: सवाल उठता है। अब क्यों? पहले क्यों नहीं, जब विमान काफी ऊंचाई पर था, या उड़ान भरने के दौरान, अथवा जब वो नीचे आने से पहले उच्च अक्षांश पर था?

निस्संदेह कराची विमान दुर्घटना की जांच का परिणाम आने में समय लगेगा। निश्चित रूप से दुनिया अध्ययन करने एवं निष्कर्षों को जानने के लिए उत्सुक होगी जिससे भविष्य में ऐसी हवाई दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को टाला जा सके। लेकिन वास्तविकता यह है : एक योग्य पायलट, उड़ने में कुशल एक विमान को एक साफ दिन के दौरान उड़ाते हुए लैंडिंग पट्टी के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 100 से अधिक यात्री मारे गए और कई मकान ध्वस्त हो गए। रनवे के बजाए, विमान मानव बस्तियों की छतों पर गिर गया। एक तरह से, इसे लैंडिंग से बचा जा सकता था। अंतिम क्षण में विमान का बर्ताव हैरान करने वाला है। केवल समय ही बताएगा की दुर्घटना के लिए कौन दोषी है, मनुष्य अथवा मशीन?

हालांकि, यह तथ्य हवाई अड्डे के निकट ऊंची इमारतों के मूलभूत खतरों को उजागर करता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर रिहायशी इलाके में मकानों पर गिरा। भारत के समक्ष भी समय-समय पर ऐसी समस्याएं रही हैं। भारत में ऐसे रियल इस्टेट निर्माणों के खिलाफ कानून मौजूद हैं। लेकिन क्या कानूनों का पालन हो रहा है? अब समय आ गया है कि हमारे उड्डयन संबंधी विकास कानूनों पर नए सिरे से दृष्टि डाली जाए? इस तरफ सोचने का यह अच्छा समय है।

आप की बात

प्रेस की स्वतंत्रता

हम सभी जानते है कि संविधान के अनुच्छेद 19(क) के तहत बोलने की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित रूप से उल्लिखित है। तथापि संविधान के पालक राष्ट्रपति , न्यायलय समेत अन्य प्रेस की स्वतंत्रता के रक्षक के सामान हैं। यद्यपि ज्ञात हो कि प्रेस किसी भी मामलें को बाकायदा प्रमाण के साथ अपने अखबारों में प्रकाशित करता है। और ... देश में हो रहे भ्रष्टाचार , कालाबाजारी , बालात्कार , हत्या ,कानून व्यवस्था लचरता जैसे कई मामलों को लोगों के सामने लाते हैं। कई लोग किसी मामलें पर असंतुष्ट होने से सीधे तौर पर प्राथमिक दृष्टया रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन भी किसी वजह से प्रेस से नाराज होने के कारण असंतुष्ट लोगों का हिमायती बन ,प्रेस को परेशान करने के पीछे पड़ जाते हैं। जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में जरा भी कसर नहीं रह पाता है। ऐसे मामलों में आयोग एफआईआर दर्ज होने के पूर्व इस मामलें की सत्यता जांच लें तदुपरांत दोषी के खिलाफ करवाई का आदेश पारित होना चाहिए। मेरे विचार से लोकतंत्र के ऐसे मजबूत स्तम्भ के लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जो निष्पक्ष , त्वरित निर्णय ले सकें ताकि प्रेस की स्वतंत्रता बनी रहें।

- **मंकेश्वर महाराज**, मधेपुरा

गांवों में दें स्थायी रोजगार

बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने कार्यस्थल से मूल निवास के ग्रामों में लौटे हैं। इनमें से लगभग आधे श्रमिक पुन: काम की तलाश में महानगरों की ओर लौटना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में ही उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। मनरेगा योजना से ही अधिकांश लोगों को रोजगार मूलक कार्यों में संलग्न किया जा सकता है। आगामी वर्षा ऋतु के मद्देनजर बारिश के जल को संचयकरने हेतु उसके संरक्षण और संवर्धन के कार्यों पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को इस तथ्य पर गौर करते हुए बड़ी तादाद में जल संरक्षण के रोजगार मूलक कार्य गांव-गांव में प्रारंभ करना चाहिए ताकि श्रम शक्ति का सदुपयोग हो एवं लोगों की आजीविका भी चल सके। इस कार्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहिए। कुटीर उद्योगों और कृषि से जुड़े कार्यों द्वारा रोजगार की संभावनाएं तलाशना वक्त की जरूरत है। कोरोना त्रासदी के कारण हमारे कामगार शारीरिक मानसिक और आर्थिक रूप से काफी पस्त हो चुके हैं। गांव में ही स्थाई रोजगार उपलब्ध करवाकर सरकार उन्हें बहुत बड़ी राहत और संबल प्रदान कर सकती है।

- **ललित महलकरी**, इंदौर

योगी ने पेश की मिसाल

भारत में आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए, परन्तु यह उन लोगों द्वारा फैलाये गये भ्रम का नतीजा है जिन्होंने, विशाल ज्ञान को समैटे हुए धर्म शब्द को अपने अपने स्तर से मापकर संकुचित कर दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि धर्म की राजनीति नहीं , पर राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को धर्म की परिभाषा कितनी विशाल है यह साबित कर दिया, उन्होंने पिछले दिनों मोहद्दीपुर-जंगल कौड़ियां फोर लेन की निर्माण की जद में पड़ने वाली गोरखनाथ मंदिर की दुकानों को तोड़ने के लिए बिना हिचक सहमति दी बल्कि अधिकारियों को बुलाकर जल्द से जल्द इन दुकानों के अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दे दिये। योगी जी के इस कार्य से समाज में धर्म को विकास कार्यों में रोड़ा बताने वालों को करारा जवाब मिला है। साथ ही साथ योगी जी ने संकेत दिया कि यदि आपकी नीयत ठीक है तो राजनीति में रहकर भी धर्म का पालन किया जा सकता है।

- **अभिनव दीक्षित**, बांगरमऊ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बीमारी मई के अंत से कम होना शुरू हो जाएगी। यह स्पष्ट है कि वायरस का प्रभाव घट नहीं रहा है। अगला कदम क्या होगा?
- **राहुल गांधी**
कांग्रेस नेता

सबसे पहले कांग्रेसशासित राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की थी। राहुल झूठ फैला रहे और वायरस के खिलाफ संघर्ष को कमजोर कर रहे हैं।
- **रवि शंकर प्रसाद**
केंद्रीय मंत्री

चीन जांच के घेरे में है। सारा विश्व उसे कोविड-19 फैलाने का दोषी मान रहा है। कई फर्में चीन छोड़कर जा रही हैं। वह ध्यान बंटाने का प्रयास कर रहा है।
- **वीके सिंह**
केंद्रीय मंत्री

विदेशी कंपनियों के लिए योगी सरकार यूपी में बढ़ाएगी लैंड बैंक

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर एक-एक किमी की दूरी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना महामारी के बीच आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में जुटी योगी सरकार अब प्रदेश में लैंड बैंक बढ़ाने पर जोर देगी। यह लैंड बैंक विदेश से आने वाली बड़ी कंपनियों और अन्य औद्योगिक संस्थानों को आसानी से जमीन मुहैया करवा सकेगा। सरकार ने लैंड बैंक को बढ़ाने के लिए राजस्व संहिता में संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में एक्सप्रेस-वेज के दोनों ओर एक एक किमी की दूरी में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी बेहद सरल बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निकट एक वृहद इलेक्ट्रानिक्स सिटी विकसित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशानिर्देश में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अपने सरकारी आवास पर बैठक की जिसमें कई निर्णय लिए गए। इस बैठक में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के साथ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त समेत 18 विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए प्रदेश में लैंड बैंक बढ़ाने के सभी बिन्दुओं पर चर्चा हुई है। वित्त विभाग ने सुझाव दिया है कि बन्द पड़ी सार्वजनिक उपक्रमों की इकाईयों की जमीनों को नीलाम किया जाए। इस पर सरकार विधिक राय लेगी।

सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में एक्सप्रेस-वेज के दोनों ओर एक एक किलोमीटर की दूरी में भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण बनाने पर फैसला हुआ है। राजस्व ग्रामों के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सम्मिलित होने पर इन ग्राम सभाओं की सार्वजनिक भूमि को सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों में अमेज किये जाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम में एक निर्धारित समय सीमा के उपरान्त भी इकाई स्थापित न किये जाने पर सम्बन्धित भूखण्डों के आवंटन को निरस्त करने पर भी प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। इस प्राविधान को पूर्वगामी प्रभाव से लाने पर भी विचार कर लिया जाये। राजस्व संहिता में संशोधन कर औद्योगिक इकाईयों, औद्योगिक पार्कों के लिए कृषि भूमि का लीज पर देने की अनुमति के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। प्रस्ताव के अनुसार औद्योगिक इकाईयों के लिए अनुमन्य फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत तथा इसके ऊपर पर चेजबिल एफएआर को सम्मिलित करते हुए कुल 3.5 अनुमन्य कर शीघ्र लागू करने की कार्यवाही का फैसला किया गया है। औद्योगिक विकास विभाग के अधीन बन्द पड़ी इकाईयों की भूमि के साथ-साथ अन्य विभागों की बन्द पड़ी इकाईयों जैसे चीनी मिलों तथा प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों को दी गयी भूमि भी लैण्ड बैंक के लिए उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। मिश्रित भू उपयोग के साथ आधुनिक इन्टीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप स्थापित किये जाने के सुझाव को शीघ्र लागू किया जायगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के विकास प्राधिकरणों के उद्योग भू-उपयोग की भूमि सम्मिलित करते हुए प्रदेश में उपलब्ध सभी भूखण्डों को जीआईएस पर उपलब्ध कराने तथा रीयल टाइम अपडेशन करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जायेगी। औद्योगिक इकाईयों के लिए कृषि भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को सुझाव के अनुसार अधिकतम 15 से 20 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव को शीघ्र लागू किया जायेगा। महाना ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि राजस्व विभाग द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में प्रतिनियुक्ति के पदों को शीघ्र भरा जाए।

इसके साथ-साथ प्राधिकरणों द्वारा विशेषज्ञों, प्रोफेशनलों की सेवाएं भी प्राप्त की जायें। जेवर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के निकट एक वृहद इलेक्ट्रानिक्स सिटी विकसित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।

यूपी इन्वेस्ट एजेन्सी की स्थापना होगी

महाना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देश भी दिये गये हैं। इसमें यूपी इन्वैस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित एमओयू तथा जीबीसी-1 और 2 में प्रारम्भ की गयी परियोजनाओं की अगले एक सप्ताह में समीक्षा कर सभी अनिस्तारित प्रकरणों का समाधान कराया जाएगा। प्रस्तावित यूपी इन्वेस्ट एजेन्सी की स्थापना अतिशीघ्र होगी। प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों की स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति युवा हब मॉडल का उपयोग करते हुए कौशल विकास की कार्यवाही अभियान के रूप में करायी जायेगी।

विदेशी निवेश के लिये योगी सरकार ने केन्द्र को भेजी रिपोर्ट

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना संकट के चलते चीन से कारोबार समेटने का मन बना चुकी कम्पनियों के लिये योगी सरकार ने संभावित निवेश पर केन्द्रित योजनाओं का ब्लूप्रिन्ट केन्द्र सरकार को भेजा दिया है। जिसमें यहां उपलब्ध संशोधनों तथा निवेश के अवसरों का जिक्र करते हुये राज्य सरकार की नीतियों का जिक्र किया गया है। केन्द्र सरकार इसका परीक्षण कराने के बाद निवेश के लिये कम्पनियों के आगे रखेगी। करीब सात सौ से ज्यादा विदेशी कम्पनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही है। इनमे अधिकतर कम्पनियां अमेरीका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य देशों की हैं। केन्द्र की मोदी सरकार इन कम्पनियों से सम्पर्क साध कर इन्हे भारत में लाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक करीब दर्जन भर फिनिश्ड उत्पादों के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ग्लोबल सप्लायर बनने की तैयारी कर रही है। जिसमे आटो पार्टस, लेदर, लेदर शूज, फूड प्रोसेसिंग, इलेटानिक्स, एल्मुनियम, लौह अयस्क जैसी वस्तुए तथा रासायनिक उत्पाद हैं। चीनी से कारोबार समेट रही ज्यादा से ज्यादा कम्पनियों को यहां लाने के लिये केन्द्र सरकार ने प्रस्तावित उत्पादों को फोकस में रखकर यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी थी ताकि विदेशी कम्पनियों के सामने रखकर देश में निवेश लाया जा सके। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार विदेशी निवेश लाने की दिशा में पहले से काम कर रही है और इसके लिये गठित टास्क फोर्स ने सम्बंधित कम्पनियों के दूतावासों से भी सम्पर्क किया है। सूत्रों का कहना है कि सीएम योगी द्वारा तैयार करायी गई निवेश की इस रिपोर्ट को केन्द्र सरकार को भेजा गया है ताकि केन्द्र सरकार विदेशी कम्पनियों से सीधे सम्पर्क करे और इन्हें देश के राज्यों में लाया जा सके।

टिड्डी दलों पर लगातार निगरानी बनाए रखी जाए: कृषि मंत्री

● जिला मुख्यालयों पर नोडल अधिकारी, टॉस्क फोर्स व नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल के प्रकोप की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। टिड्डी दलों के नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बृहस्पतिवार को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में टिड्डी दलों के संचलन पर लगातार निगरानी बनाए रखी जाए। विभागीय कर्मचारी अधिकारी जन सामान्य से निरन्तर क्षेत्र में सम्पर्क करते हुए टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए सम्बन्धित संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रभावी कार्रवाई करें। शाही ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष तथा गठित टीमों द्वारा जो टिड्डी दलों के प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आक्रमण एवं उनकी गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण एवं तद्नुसार सम्बन्धित जिलों को आवश्यक सुरक्षात्मक निर्देश प्रेषित करता रहे। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालयों पर इसके लिए नोडल अधिकारी, टॉस्क फोर्स एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश के क्रम में जनपदों में भी गठन की कार्रवाई की गई है। टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव तथा सावधानियों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी विषयक एक फोल्डर तैयार कर प्रदेश के सभी जनपदों के विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है तथा इसे किसानों एवं जन सामान्य को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

टिड्डी दल के प्रकोप की सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित समस्त क्षेत्रीय कार्मिकों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित ढंग से कृषकों तक पहुंचाने के लिए सम्बन्धित जनपदों को निर्देश दिए।

कृषि मंत्री ने बताया कि दौसाए राजस्थान के पास वाला टिड्डी दल एक बड़े और कई छोट-छोटे दलों में विभाजित हो गया है। अधिकांश छोटे दलों को टिड्डी नियंत्रण दल ने दौसा के पास नियंत्रित कर लिया गया है। सिर्फ एक बहुत छोटा सा दल दौसा से 10 किमी दूर अलूदा के पास देखा गया है। इन दलों से आगरा जनपद को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

केंद्र व राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं: मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना वायरस महासंकट के बीच प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। रोजाना प्रवासी मजदूरों को लेकर रोज कोई न कोई अप्रिय खबर आ रही है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने राज्य सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। गुरुवार को अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि जिस प्रकार से लॉकडाउन से पीड़ित व घर वापसी को लेकर मजबूर प्रवासी श्रमिकों की बदहाली व रास्ते में उनकी मौत आदि के कड़वे सच मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने हैं। वह पुन:स्थापित करते हैं कि केन्द्र व राज्य सरकारों को इनकी बिल्कुल भी चिन्ता नहीं है। यह अति दु:खद है। देश में लॉकडाउन के आज 65वें दिन यह थोड़ी राहत की खबर है कि न्यायालयों ने कोरोनावायरस की जाँच व इलाज में सरकारी अस्पतालों की बदहाली, निजी अस्पतालों की उपेक्षा व प्रवासी मजदूरों की बढ़ती दुर्दशा व मौतों के सम्बंध में केन्द्र व राज्य सरकारों से सवाल-जवाब शुरू कर दिया है।

चार जून से होगा मुल्जिमों का बयान दर्ज

अयोध्या के विवादित ढांचे को ढहाए जाने का मामला

विधि संवाददाता। लखनऊ

अयोध्या के विवादित ढांचा को ढ़हाए जाने के आपराधिक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत चार जून से मुल्जिमों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करना शुरु करेगी। इसके तहत मुल्जिमों को यह बताया जाएगा कि उनके खिलाफ क्या गवाह एवं सबूत पेश किए हैं और इस पर उनका क्या कहना है। उन्हें अपनी निर्दोषिता स्पष्ट करने का मौका दिया जाएगा।

विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बचाव पक्ष को यह निर्देश दिया है कि वो हर हाल में तय तारीख पर बयान दर्ज कराने के लिए मुल्जिमों की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को प्रत्येक दशा में 31 अगस्त, 2020 तक निर्णीत करने का आदेश दे रखा है।

गुरुवार को विशेष अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से कहा गया कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना प्रकोप के चलते उम्रदराज लोगों को केंद्र व राज्य की गाइडलाइंस के मुताबिक घर से निकलने की मनाही है। चूंकि इस मामले में ज्यादातर मुल्जिम अधिक उम्र के हैं। लिहाजा ऐसी दशा में वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। यह भी कहा गया कि कुछ मुल्जिम अयोध्या जनपद के आस-पास के जिलों के हैं। उनसे सम्पर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें से कुछेक से बात भी हो गई है। लिहाजा इनका बयान दर्ज कराने के लिए कम से कम एक हफ्ते की मोहलत दी जाए।

विशेष जज ने इसके साथ ही दोनों पक्षों को यह भी आदेश दिया कि वो भविष्य में लिखित बहस दाखिल करने हेतु अपनी तैयारी पूरी करते रहें। ताकि अनावश्यक समय नष्ट न हो। इस दौरान सीबीआई की ओर से वकील ललित सिंह व आरके यादव उपस्थित थे।

वहीं बीते 18 मई से पुन: सुनवाई शुरु होने पर बचाव पक्ष ने अभियोजन के तीन गवाहों से जिरह करने की अर्जी दाखिल कर दी। जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इनमें से दो गवाह फरहत अब्बास व जगत बहादुर अग्रवाल से बचाव पक्ष की जिरह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूरी हो गई है। जबकि एक गवाह मधुरिमा मिश्रा उम्रदराज होने के चलते चलने फिरने में भी असमर्थ है। लिहाजा उनकी गवाही को अदालत ने नहीं पढने का आदेश जारी कर दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल

लखनऊ (विसं)। धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए एमपीएमएलए की विशेष अदालत ने 30 मई की तारीख मुकर्रर की है। विशेष जज पवन कुमार राय ने यह आदेश अभियोजन की गुजारिश पर दिया है। गुरुवार को अदालत के समक्ष लल्लू की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। इस दौरान फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभी इस मामले के कागजात संबधित थाने से प्राप्त नहीं हुए हैं। लिहाजा इस मामले मे कोई दूसरी तारीख तय की जाए। 19 मई, 2020 को धोखाधड़ी के इस मामले की एफआईआर आरपी द्विवेदी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इसके अगले दिन लल्लू को आगरा में अवैध रुप से धरना-प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में उन्हें उसी रोज जमानत मिल गई थी। लेकिन इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी के इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

भाजपा को जनता के सुख-दुख से कोई मतलब नहीं: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि, कहते हैं जब रोम जल रहा था, सम्राट नीरो बंशी बजा रहा था, भाजपा नेतृत्व और उसकी सरकारें इसे ही दुहराने जा रहे हैं। भाजपा 30 मई को केन्द्र सरकार का एक साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर वाहवाही लूटने की तैयारी में जुट गई है। देश-प्रदेश में इसके लिए भव्य आयोजन होंगे। यह असमय जश्न तब मनेगा जब एक ओर कोरोना महामारी से मौतें हो रही हैं और भूखे प्यासे श्रमिक भटक रहे है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का जंगलराज चल रहा है। सत्ता की हनक में निर्दोषों का उत्पीड़न हो रहा है। रोटी रोजगार के धंधे बंद हैं। किसान, नौजवान और व्यापारी सब हताशा में हैं।

उन्होंने सवाल किया कि भाजपा सरकार अपने झूठ और थोथे वादों से जनता को कब तक भटकाएगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन दिया तो केन्द्रीय वित्तमंत्री ने 80 करोड़ परिवारों को मदद का दावा कर दिया। अब ये आंकड़े सच्चे हैं तो झूठा कौन, क्या भूख से बेहाल श्रमिक, नंगे पैर तपती धरती पर दौड़ती महिलाएं और बच्चे। संकट के ऐसे समय में जब सत्ता के शीर्ष से देश को भरोसा दिलाने की जरूरत है तब जिम्मेदार लोग दिशाहीन हो चुके हैं। उन्हें जनता के सुख दुख से मतलब नहीं है। भाजपा को तो बस सत्ता के सिंहासन से ही वास्ता है।

हर जरूरतमंद के खाते में डालें जाएं 10 हजार रुपए: प्रियंका गांधी

● मनरेगा के कार्य दिवस 100 से 200 दिन तक बढ़ाया जाए

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मांग की है कि हर जरूरतमंद के खाते में 10 हजार रुपए डाले जाएं। प्रियंका ने कहा कि आज देशभर में कांग्रेस के कार्यकर्ता-नेता उन लोगों के पक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं जो लोग लॉकडाउन और कोरोना महामारी के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग है कि अगले 6 महीने तक प्रतिमाह 7500 रुपए जरूरतमंद लोगों के खाते में डाले जाएं।

इसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच चुके हैं उनके लिए मनरेगा के कार्य दिवस 100 से 200 दिन तक बढ़ाया जाए। जो लोग लॉक डाउन से जूझ रहे हैं, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, जो छोटे उद्योग वाले हैं छोटे दुकानदार हैं, बुनकर हैं उनकी मदद के लिए सरकार कुछ करें उनको एक आर्थिक पैकेज दे। उनके ऊपर कर्ज ना हो उनके हाथ में पैसा आए ताकि इस मुश्किल वक्त में उनका गुजारा चल सके। प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव पर कहा कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों और विशेषकर भाजपा से यह आग्रह करना चाहती हूं कि यह वक्त राजनीति का नहीं है। यह वक्त पूरे देश को इकट्ठा होने का है। सभी पार्टी के राजनेताओं को वैचारिक मतभेदों को भुलाकर हम सबको सबकी मदद करना है।

टीम भावना के साथ चुनौतियों से निपटने का होगा प्रयास

● नवनियुक्त एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने पदभार ग्रहण किया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

वर्ष 1990 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था पद का कार्यभार बृहस्पतिवार को ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं और पुलिस महानिदेशक के निर्देश हैं, उसका शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाए। प्रशांत कुमार अभी तक एडीजी मेरठ जोन के पद पर तैनात थे। बीते मंगलवार को राज्य सरकार ने उन्हें एडीजी कानून-व्यवस्था पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। एडीजी ने कहा कि जो शासन की नीति शुरू से रही है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम एंड क्रिमिनल और इसके साथ-साथ जो नई चुनौतियां समय-समय पर आती रहती हैं उसको एक टीम भावना जागृत करके और उसका सही अनुपालन फील्ड के अफसरों से कराया जाए यह प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान जो कार्य पुलिस ने किए उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी लेकिन श्सर्विस बिफोर सेल्फ सर्विस को आप स्वयं के पहले रखते हुए हमारे सभी कोरोना वारियर्स ने स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ तथा अन्य विभागों के लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया है और अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें तो हमारे कोरोना वारियर्स यहां बहुत कम संख्या में संक्रमित हैं। इसका कारण है कि शासन और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार ऑफिसर ओरिएंटेड पुलिसिंग फील्ड में की गई। सभी सीनियर ऑफिसर प्रतिदिन उन बैरियर्सए नाकाए क्वॉरेंटाइन सेंटर और कोविड हॉस्पिटल में जाते थे और किसी भी तरीके की जो सहायता है उसकी कमी नहीं होने दी गई। एडीजी ने कहा एक नया चैलेंज जो इस दौरान उभर कर आया वह लाखों की संख्या में लोग अन्य राज्यों से आए हैं और उनके पुनर्वास के लिए उनके एंप्लॉयमेंट के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारा प्रयास होगा कि उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए हमारे विभाग से जो भी सहायता संभव होगी वह हम देंगे।

टिड्डी दल पर हेलीकाप्टर से कीटनाशकों का छिड़काव कराए: रालोद

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने केन्द्र और प्रदेश दोनों ही सरकारों से किसानों की हालत की अनदेखी बन्द करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकारें अपनी कुम्भकर्णी नींद से बाहर निकल कर किसानों के पक्ष में निर्णय करे। कोरोना महामारी के कारण सम्पूर्ण लाक डाउन में फूलों और सब्जियों के किसानों की दशा दयनीय हो गई है। दैवीय आपदा के साथ साथ सरकारों की अनदेखी ने किसानों की नींद पहले ही उड़ा रखी है और अब टिड्डी दलों ने किसानों का चैन हराम कर दिया है। त्रिवेदी ने कहा कि सरकार द्वारा जब हेलीकाप्टरों से योद्धाओं के सम्मान में पुष्प वर्षा हो सकती है तो इन किसानों की फसलों की रक्षा के लिए तत्काल हेलीकाप्टरों द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव करके टिड्डियों के दलों को भी समाप्त किया जा सकता है।

बिजली दरों में फिर बढ़ोत्तरी की तैयारी

● उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से की मुलाकात

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

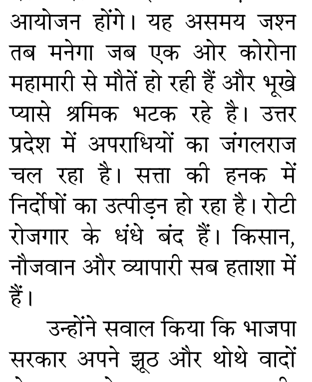

कोरोना महामारी के बीच बिजली विभाग एक बार फिर उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ डालने वाला है। पावर कारपोरेशन इस माह के अंत तक उप्र विद्युत नियामक आयोग में बिजली बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। इधर बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव की भनक लगते ही विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मुलाकात की है और कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाए।

शक्ति भवन में मुलाकात के दौरान उपभोक्ता परिषद ने जनहित का प्रस्ताव सौंपते हुए यह मुदा उठाया कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2019-20 में जब बिजलीदर में बढ़ोतरी की गयी थी। उस समय टैरिफ आर्डर में प्रदेश के उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो के ऊपर लगभग 13337 करोड़ रूपए निकला था। वह अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है अगर यह उपभोक्ताओं को मिल जाए तो अपने आप ही बिजली दरों में 10 प्रतिशत की कमी हो जाएगी। उन्होंने सरकार को चाहिए कि उपभोक्ताओं का रूपए उपभोक्ताओं को जल्द मिल सके इसके लिए नियामक आयोग को निर्देशित किया जाना चाहिए। इस महीने के अंत तक नियामक आयोग में दाखिल करने की जुगत में है। पिछले वित्तीय वर्ष में पावर कारपोरेशन ने 15 प्रतिशत तक बिजली के दामों में वृद्धि की थी। उपभोक्ता परिषद के अनुसार नियामक आयोग द्वारा जारी मेरिट आर्डर का अगर शत-प्रतिशत पालन बिजली कम्पनिया कर ले तो लगभग हर वर्ष 1200 करोड़ का फायदा सभी डिस्कामों को हो सकता है। महत्वपूर्ण बात प्रदेश में एटीएनसी हानिया केवल 2 प्रतिशत कम कर ले तो लगभग 1100 करोड़ का फायदा हो जायेगा। निजी घरानों की मंहगी बिजली खरीद पर यदि अंकुश लगाया जाए तो लगभग 800 करोड़ की बचत हो सकती है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन में उपभोक्तओं की स्थिति को देखते हुए सरकार को विद्युत अधनियम 2003 की धारा 108 के तहत नियामक आयोग में बिजली दर में घटौती का प्रस्ताव देना चाहिए। केंद्र सरकार ने बिजली उत्पादन कम्पनियों के फि क्स्ड कॉस्ट में लॉक डाउन अवधि में कटौती की है। साथ ही अनेकों राहत प्रदान की है ऐसे में उसका लाभ उपभोक्तओं तक पहचाया जाना चाहिए।

डीएम शीघ्र जारी करें बालू मौरंग के अनुज्ञा पत्र

लखनऊ। सचिव एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डॉ. रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि कृषिकीय भूमि पर बाढ़ से एकत्रित उपखनिजों बालू, मौरंग के अनुज्ञा पत्र शीघ्र से शीघ्र जारी किए जाएं। इससे जहां खनन से राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं कृषिकीय भूमिधरों का हितलाभ भी प्रभावित नहीं होगा। डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली-1963 के नियम (52) के अन्तर्गत कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण बालू मोरम आदि को हटाये जाने के लिए रायल्टी के दो गुना के आधार पर अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही यह निर्देश दिये गये हैं कि कृषि भूमि पर प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार जांच कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा प्रतिमाह प्राप्त स्वीकृत अस्वीकृत निर्गत अनुज्ञा पत्र की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक खनन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए।

फूड प्रोसेसिंग के जरिए गांवों को किया जाए गुलजार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेती में पैदा होने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग करके गांवों को गुलजार करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्ययोजना बनायी जाए कि खेती में पैदा होने वाले विभिन्न फलों, सब्जियों, फूलों आदि को किसानों के खेत से सीधे खरीदकर उन्हे कोल्ड चेन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में पहुंचाया जाए। उन्होंने किसानों और युवाओं तथा विभिन्न प्रदेशों से आए कामगारों का आह्वान किया है कि वे इस कोल्ड चेन का हिस्सा बनें, इससे जहां उन्हें काम और रोजगार मिलेगा वहीं कृषि क्षेत्र में एक नयी उर्जा व उत्साह का संचार होगा। मौर्य अपने आवास पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के साथ इस मसौदे को अमलीजामा पहनाने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मौर्य ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक परिवेश में संतुलन के लिए आवश्यक है कि खेती को कुटीर उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि स्किल मैपिंग का कार्य चल रहा है और स्किल्ड व हुनरमन्द तथा विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता व दक्षता रखने वाले लोगों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़कर उन्हे आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इससे ग्रामीण आर्थिक उन्नयन तो होगा ही और शहरीकरण व पलायन की प्रवृत्ति पर भी विराम लगेगा, साथ ही मजदूरों के कार्यकौशल का लाभ उठाने में उप्र कामयाब होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह फूड प्रोसेसिंग के दृष्टिकोण से अनरजिस्टर्ड यूनिटों की सूची मंगायें तथा सूची के आधार पर व जिलों में चल रहीं अनरजिस्टर्ड यूनिटों का अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन करवायें, इस तरह जिलावार अनरजिस्टर्ड इकाइयों की सूची तैयार करायी जाए। हमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है और कोशिश है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को हम गांवों तक लें जायें। इस क्षेत्र में निवेश की बहुत बड़ी सम्भावना है और काफी तादाद में निवेश हुआ भी है।

जनसमस्याओं के निराकरण में सहयोग करें समाजसेवी

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजसेवियों व स्वैच्छिक संगठनों से अपील की है कि वे इस संकट काल में नागरिकों को खासतौर से अन्य प्रदेशों से आ रहे कुशल व अकुशल श्रमिकों को मदद दिलाने में सहयोग प्रदान करें। मौर्य जनपद कौशाम्बी के विभिन्न समाजसेवियों से वेबिनार के जरिए संवाद कर रहे थे। उपमुख्यमंत्री ने कौशाम्बी के विभिन्न लोगों से वार्ता करते हुये वहां की स्थितियों व समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की तथा विभिन्न लोगों के सुझाव भी सुने और उन्हे आश्वस्त किया कि प्रत्येक नागरिक की हर समस्या का हर सम्भव निदान किया जायेगा।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर भाजपा एक महीने तक चलाएगी अभियान

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जून से एक महीने का अभियान शुरू करेगी जिसमें देश के हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल रैली आयोजित करना शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी। भाजपा वर्चुअल रैलियों के जरिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान, 20 लाख करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज, कोविड-19 से जुड़े विषयों सहित जन कल्याण कार्यो के बारे में लोगों को बताएगी।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष फेसबुक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसकी तारीख की घोषणा एक-दो दिन में हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा लिखा पत्र पार्टी के कार्यकर्ता करीब 10 करोड़ घरों तक पहुंचाएंगे। भूपेन्द्र यादव ने कहा, पार्टी ने तय किया है कि वर्चुअल संवाद के माध्म से देशभर के हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल रैली आयोजित की जाएगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ ली थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। बहरहाल, भाजपा महासचिव ने बताया कि डिजिटल सम्पर्क आज के समय में सामाजिक, राजनीतिक सम्पर्क का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ऐसे में पार्टी वर्चुअल संवाद के जरिए जमीनी स्तर पर अपने कार्यो को पहुंचाने पर जोर दे रही है। यादव ने बताया कि पार्टी ने इसके लिए हर मोर्चे को भी जिम्मेदारी सौंपी है जिसमें युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल है। इनके माध्यम से 500 से ज्यादा वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी।

यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरा देश कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट है। संकट की इस घड़ी में देश के लोगों ने एक दूसरे का साथ देते हुए इस लड़ाई को लड़ा है और एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फीड द नीडी अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत 8 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने 19.18 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को भोजन कराया। 4.86 करोड़ से अधिक लोगों को फूड पैकेट्स की आपूर्ति की गई।

भूपेन्द्र यादव ने बताया कि पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक फेस कवर कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को वितरित किए गए तथा कोरोना योद्धाओं को बूथ स्तर पर पार्टी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके साथ ही 12.87 लाख से अधिक बूथों में धन्यवाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। भाजपा नेता ने बताया कि 11 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं द्वारा 588 जिलों के 9 हजार से अधिक मंडलों में 1.18 लाख से अधिक गरीब बस्तियों में 10.30 लाख फूड पैकेट्स घर-घर जाकर वितरित किए गए।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थानीय पर्व 'जमाई सस्थी' पर एक पेड़ की पूजा करती हुई महिलाएं।

पटनायक ने कोरोना के खिलाफ ओडिशा की लड़ाई की सराहना की

भुवनेश्वर। कोरोना वायरस महामारी से मानव जीवन बचाने में ओडिशा को एक मिसाल बताते हुए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 0.46 फीसदी है जो देश और दुनिया में सबसे कम है। पटनायक ने दावा किया कि कई शक्तिशाली राष्ट्र और समृद्ध भारतीय राज्य भी स्थिति का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन ओडिशा ने पिछले दो महीनों में इस बीमारी के प्रसार को सफलतापूर्वक काबू में किया है और सुनिश्चित किया है कि लोग ठीक हों और मृत्यु दर को नण्य रखा है। उन्होंने कोविड योद्धाओं के समर्पण और सेवा की सराहना की, जिन्होंने प्रदेश में मृत्यु दर 0.46 प्रतिशत पर नियंत्रित करने में मदद की और सुनिश्चित किया है कि 50 फीसदी से ज्यादा मरीज सेहतमंद हो जाएं। ओडिशा में कोरोना वायरस के 1,660 मामले आए हैं जिनमें से 887 ठीक हो गए हैं तथा छह अप्रैल से सात लोगों की मौत हो चुकी है।

पटनायक ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमने दो महीने पहले कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, हमारा लक्ष्य राज्य के 4.5 करोड़ लोगों के जीवन को बचाना था और हमने यह सुनिश्चित किया है। यह राज्य के लिए एक अभूतपूर्व सफलता है। कोविड योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पटनायक ने ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले सभी लोगों से 30 मई को शाम साढ़े पांच बजे बंदे उत्कल जननी गीत (जिसे राज्य का गीत माना जाता है) गाने की अपील की। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे संकल्प को मजबूत करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम डॉक्टर, नर्स, जन प्रतिनिधि और गैर सरकारी स्वयंसेवकों समेत उन सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का हौसला बढ़ाएगा जो महामारी से निपटने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

राजस्थान में टिड्डियों के हमले से 20 जिलों में 90,000 हेक्टेयर इलाका प्रभावित

जयपुर। पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान में घुसी टिड्डियों के हमले से राजस्थान के जिलों का लगभग 90,000 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि टिड्डी नियंत्रण दलों द्वारा किए गए कीटनाशक छिड़काव के बाद टिड्डियां श्रीगंगानगर से चलकर नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर और अन्य क्षेत्रों से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर बढ गई। कृषि विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि टिड्डियों के हमले से श्रीगंगानगर में लगभग 4,000 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल को नुकसान हुआ वहीं नागौर में 100 हेक्टेयर भूमि की फसल को चट कर दिया। राज्य में टिड्डियों के हमले से 20 जिलों की कुल 90,000 हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 67,000 हेक्टेयर भूमि पर टिड्डियों को भगाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करवाया है। अधिकारी ने बताया कि टिड्डियां एक दिन में 1520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक दिन में 150 किलोमीटर तक की दूरी तक यात्रा कर सकती है। चूंकि अभी खेतों में खड़ी फसल नहीं है इसलिए टिड्डियां पेड़ों और अन्य भोज्य पदार्थो को अपना लक्ष्य बना रही हैं। उन्होंने बताया कि टिड्डियों द्वारा पाकिस्तान से इतनी दूरी की यात्रा करने का मुख्य कारण खड़ी फसलों की अनुपलब्धता भी है। अधिकारी ने बताया कि टिड्डियों को नियंणित करने के लिए ब्रिटिश निर्मित 800 स्प्रेयरर्स माउंटेंड ट्रैक्टर्स से कीटनाशक छिडकाव किया गया। लगभग 200 दल प्रतिदिन छिड़काव करने वालों में शामिल हैं। उन्हें 120 जीपें उपलब्ध करवाई गई हैं।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राजभवन के खर्चों में कटौती की घोषणा की

भाषा। मुम्बई

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोविड-19 के राहत उपायों के वास्ते अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजभवन के खर्चों में कटौती की बृहस्पतिवार को घोषणा की। आधिकारिक बयान के अनुसार, इन कदमों में इस वित्त वर्ष के दौरान राजभवन के लिए कार खरीदने को टालना, राज्यपाल के आधिकारिक आवास पर आने वाले वीआईपी आगुंतकों का स्वागत करते समय उन्हें गुलदस्ता नहीं देना आदि शामिल है। उसने कहा कि इन उपायों से राजभवन के इस वित्त वर्ष के खर्चों में करीब 10 से 15 प्रतिशत की कमी आएगी।

बयान में कहा कि राज्यपाल ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राजभवन में कोई नया पूंजी कार्य शुरू नहीं करने और किसी भी नए बड़े निर्माण या मरम्मत कार्य को नहीं करने का निर्देश दिया है। बयान में कहा, जो काम अभी किए जा रहे हैं, वे जारी रहेंगे और पूरे किए जाएंगे। उसने कहा, कोश्यारी ने पुणे में राजभवन में 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले रिसेप्शन को भी रद्द करने को कहा है।

बयान में कहा गया है कि अगले आदेश तक राजभवन में नियमित भर्ती भी नहीं की जाएगी। राजभवन के लिए नई कार खरीदने के प्रस्ताव को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

बयान में कहा गया है कि वीवीआईपी को दी जाने वाली भेंट और स्मृति चिन्ह भी अगले आदेश तक नहीं दिए जाएंगे और साथ ही वीआईपी आगुंतकों को गुलदस्ते नहीं दिए जाएंगे। राजभवन में आगुंतकों के कमरों को सजाया भी नहीं जाएगा।

राज्यपाल ने कुलपति और विभिन्न अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करने को भी कहा है, ताकि यात्रा के खर्चे को बचाया जा सके। बयान में कहा गया कि कोश्यारी पहले ही अपने एक महीने का वेतन कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दे चुके हैं और साथ ही एक साल तक अपने वेतन का 30 प्रतिशत भी इस कोष में देने की बात कही है।

टीडीपी की नींव कोई नहीं हिला सकता: चंद्रबाबू नायडू

अमरावती। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ साजिशें रच कर और उन्हें झूठे मामलों में फंसा कर टीडीपी की नींव नहीं हिला सकती। नायडू ने यहां एक राजनीतिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के गरीब लोगों, सिनेमा और देश के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में टीडीपी संस्थापक एन टी रामाराव के उत्कृष्ट और चहुंमुखी योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजने की भी मांग की। सताइस मई को शुरू हुए पार्टी के दो दिवसीय डिजिटल सम्मेलन में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। टीडीपी ने एक बयान में नायडू के हवाले से कहा, टीडीपी की नींव को कोई नहीं हिला सकता क्योंकि पार्टी स्थापना के समय से ही गरीब और पिछड़े वर्गों के दिलों में इसका मजबूत स्थान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टीडीपी कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की साजिशों और उनकी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) द्वारा दर्ज कराए गए झूठे मामलों से नहीं डरेंगे। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करने के लिए तैयार हैं।

अरुणाचल प्रदेश में हथियार और गोला बारूद बरामद

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में सुरक्षा बलों ने हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया है। चांगलांग के पुलिस अधीक्षक मिहीन गैम्बो ने बृहस्पतिवार को बताया कि सेना के 9 राजपूताना राइफल्स के जवानों और राज्य पुलिस कर्मियों के एक दल ने बुधवार को मियाओ बुम इलाके से हथियारों और गोला बारूद का एक जखीरा बरामद किया। उन्होंने बताया कि एक एके-56 राइफल, तीन मैगजीन, 7.62 एमएम की 115 गोलियां, 40 एमएम का एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर , एक हथगोला, करीब 500 ग्राम के चार स्टिक पाउडर जेल विस्फोटक, .22 की एक पिस्तौल और कई अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि 9 राजपूताना राइफल्स ने मियाओ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और मामले की जांच जारी है।

फर्जी ई-यात्रा पास बेचने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई के चेंबूर उपनगरीय इलाके में पुलिस ने बृहस्पतिवार को 28 वर्ष के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर फर्जी ई-यात्रा रैकेट का भंडाफोड़ किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मुम्बई में डोंगरी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए जरूरी ई-यात्रा पास अवैध तरीके से बना रहे हैं और प्रति पास पांच हजार रुपए में बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसके बाद मनोज रामू हुंबे को गिरफ्तार कर लिया गया जो यह रैकेट चलाता था। उससे पूछताछ में यह पता चला कि वह और उसके सहयोगी फर्जी पास बनाते थे और उसे मुंबई और नवी मुंबई पुलिस आयुक्तों तथा मुम्बई उपनगरीय एवं पालघर कलक्टर कार्यालयों द्वारा जारी किया दिखाते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हुंबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465 और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

रांची में बिरसा मुण्डा इंटरनेशनल एअरपोर्ट के स्पेशल विमान से उतरने के बाद बस से अपने गंतव्य स्थान को जाते हुए प्रवासी।

महाराष्ट्र में अभी तक कोविड-19 से 22 पुलिसकर्मियों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने अभी तक कम से कम 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली है। यह बात एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कही। अधिकारी ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 130 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या बढ़कर 2,095 हो गई है।

कुल संक्रमित पुलिसकर्मियों में से 236 अधिकारी हैं जबकि 1,859 अन्य कांस्टेबुलरी रैंक के कर्मचारी हैं। सभी का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अभी तक 75 अधिकारी और 822 कांस्टेबुलरी रैंक के कर्मी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अधिकारी के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले की 254 घटनाएं हुईं और इन मामलों के संबंध में अभी तक 833 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा 40 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों पर भी हमले किए गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने लॉकडाउन आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कम से कम 1,16,670 मामले दर्ज किए हैं जिसमें 23,314 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कम से कम 705 लोगों का पता लगाया है जिन्होंने घर पर पृथक रहने के नियम का उल्लंघन किया। इस आंकड़े में मुम्बई शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में पुलिस नियंत्रण कक्षों को कोरोना वायरस महामारी के संबंध में करीब 96,700 कॉल आईं। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अवैध परिवहन के 1,323 अपराध दर्ज किए और 75,813 वाहन जब्त किए हैं। विभिन्न अपराधों के लिए पुलिस द्वारा 5.75 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है।

घर में पृथक-वास के नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना वायरस के संदिग्ध या हल्के लक्षणों वाले लोगों के घर में क्वारंटाइन रहने के दौरान पृथक-वास (क्वारंटाइन) नियम तोड़ने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। दूसरी बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को घर से हटा कर संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा। केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के हल्के और पूर्व लक्षणों वाले मामलों में लोगों को घर में पृथक-वास रहना चाहिए। कोविड-19 के संदिग्ध लोगों से घर में पृथक-वास मानदंडों के पालन की सहमति लिखित में लिया जाना है। कोई व्यक्ति घर में पृथक-वास मानदंडों का पहली बार उल्लंघन करता हैं तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और यदि व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता हैं तो उसे कोविड-19 देखभाल केन्द्र में भेजा जाएगा। मध्यप्रदेश में बुधवार रात तक कुल 7261 कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। 313 लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो चुकी है तथा अब तक 3927 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 50 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण पहुंच चुका है।

फर्जी संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई को दी चुनौती

भाषा। मुंबई

भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्वाई करने के लिए मुंबई पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मुंबई भाजपा इकाई के अध्यक्ष लोढा ने मंगलवार को दायर अपनी याचिका में कहा कि पुलिस द्वारा 23 मई को जारी किया गया आदेश दुर्भावनापूर्ण है और इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी की स्थिति में सरकार की निष्क्रियता की आलोचना पर प्रतिबंध लगाना है।

याचिका में कहा गया है कि यह आदेश मनमाना, अनुचित और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर गलत, फर्जी सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्वाई की जाएगी। यह आदेश आठ जून तक लागू रहेगा। यह भी कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया समूह के एडमिन को समूह में प्रसारित किसी भी गलत सामग्री या गलत संदेशों के प्रसार के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाई माना जाएगा।

याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ हफ्तों में महाराष्ट्र में महामारी स्थिति को सही ढंग से नियंत्रित करने में राज्य सरकार की अक्षमता को उजागर किया गया है। सरकार को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस आदेश को खारिज करने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि नागरिकों ने अब सोशल मीडिया पर अपनी राय और विचार रखना शुरू कर दिया है।

चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए, एक घायल

चाईबासा। झारखंड के चाईबासा जिले में आज तड़के मनमादुबेड़ा और केन्तई गांवों के बीच टेबो पुलिस थानांतर्गत पहाड़ी इलाके में हुई मुठभेड़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं स्थानीय पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट आफ इंडिया (पीएलएफआई) के तीन क्सलियों को मार गिराया जबकि एक घायल नक्सली समेत दो को गिरफ्तार कर लिया। चाईबासा के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता ने घटना की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त इलाके में पीएलएफआई संगठन के नक्सली एकत्रित होकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद आज तड़के घेराबंदी कर उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया लेकिन उन्होंने गोलीबारी प्रारंभ कर दी जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कार्वाई कर भीषण मुठभेड़ में इस नक्सली संगठन के तीन नक्सलियों को मार गिराया।

लड़के और लड़कियों दोनों को सिखाया जाए कि रजस्वला होना शर्म की बात नहीं : ईरानी

नई दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर लोगों से लड़कियों के साथ ही लड़कों को भी इस तथ्य को लेकर शिक्षित करने की अपील की कि रजस्वला (मासिक धर्म) होना कोई शर्म की बात नहीं है। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर वर्ष 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह इससे जुड़ी दकियानूसी बातों और रजस्वला के दौरान लड़कियों और महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ भी आवाज उठाता है। मंत्री ने कहा कि जन औषधि केन्द्रों के जरिए भारत की लाखों महिलाओं को सैनेटरी नैपकीन किफायती दामों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ईरानी ने ट्वीट किया, जन औषधि केन्द्रों के जरिए लाखों भारतीय महिलाओं को किफायती दामों में सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 पर ना केवल लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी इस तथ्य को लेकर शिक्षित करने का संकल्प करें कि रजस्वला कोई शर्म की बात नहीं है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं का जैविक चक्र (बायोलॉजिकल सर्कल) उसकी तरक्की की राह में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सिलसिलेवार किए ट्वीट में कहा, ऐसे समय में जब देश एक महाशक्ति बनना चाहता है तब लैंगिक भेदभाव से जुड़ी रूढ़िवादी बातों से ऊपर उठाना और अपनी बेटियों की मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता सुनिश्चित करना एक जिम्मेदारी बन जाता है। शर्मा ने कहा, एक महिला का जैविक चक्र उसकी तरक्की की राह में कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। सभी महिलाएं सुरक्षित रजस्वला की हकदार हैं। स्वच्छ मासिक धर्म उनका अधिकार है।

असम के नालबारी जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाता हुआ आदमी।

देश ने वीर सावरकर को किया याद

भाषा। नई दिल्ली

● महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धासुमन

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने बृहस्पतिवार को स्वतंत्रता सेनानी एवं हिन्दुत्व विचारक वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावरकर ने दूसरों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, मैं साहसी वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। हम उन्हें उनकी बहादुरी और दूसरों को स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने की प्रेरणा देने तथा सामाजिक सुधारों पर जोर देने के लिए याद रखेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ मई 2018 के मन की बात कार्यक्रम का एक क्लिप भी जारी किया जिसमें उन्होंने सावरकर का उल्लेख किया था। मोदी ने कहा था कि यह दुख की बात है कि हम लंबे समय तक 1857 की घटनाओं को केवल विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहते रहे। वास्तव में उस घटना को कम करके आंका गया। उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए भारतीय वीरों के संघर्ष को देश की आजादी की पहली लड़ाई कहने की हिम्मत की।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, समाज सुधारक, लेखक, कवि वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर स्वातंत्र्य वीर के अनुकरणीय कृतित्व और व्यक्तित्व को विनम्र नमन करते हैं। नायडू ने

अपने ट्वीट में कहा, वीर सावरकर ने दलित और दुर्बल वर्गों के भाई-बहनों के लिए एक न्यायपूर्ण समावेशी संवेदनशील समाज की स्थापना हेतु सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया।

उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए लंबा संघर्ष किया ... छुआछूत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि वह अपेक्षा करते हैं कि देश के युवा, स्वातंत्र्य वीर सावरकर के जीवन और कृतित्व का गंभीर अध्ययन करेंगे और राष्ट्र एवं समाज निर्माण में उनसे प्रेरणा लेंगे। समाज से कुरीतियों को दूर करेंगे तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक यातनाएं सहीं और देश के लिए इतने कष्ट सहने वाला विश्व में सावरकर जैसा शायद ही कोई हो।

शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि सावरकर ने अस्पृश्यता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और मंदिरों में दलित समाज के प्रवेश के लिए संघर्ष किया। ऐसे महान राष्ट्रभक्त के चरणों में कोटि-कोटि नमन। उन्होंने कहा कि भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर वीर सावरकर का महामंत्र था एक राष्ट्र-एक संस्कृति भाव। देश की स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष व राष्ट्रप्रेम हर भारतीय के लिए प्रेरणास्रोत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर भारत माता के ऐसे सपूत थे, जिन्होंने अदभुत जीवट और राष्ट्रप्रेम का परिचय देते हुए इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई।

जबलपुर में गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने खेत की जुताई करता हुआ एक किसान

90 वर्षीय पुरुष ने कोरोना को हराया

इंदौर (मध्य प्रदेश)। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में 90 वर्षीय एक पुरुष इस महामारी को परास्त करते हुए घर लौट आए हैं। इसके साथ ही, वह देश के उन सबसे उम्रदराज मरीजों में शामिल हो गए हैं जो उपचार के बाद इस महामारी से उबर चुके हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद 90 वर्षीय पुरुष को शहर के एक निजी अस्पताल में 22 मई को भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद संक्रमणमुक्त होने पर उन्हें बुधवार शाम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उम्रदराज व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें मेडिकल स्टाफ इस शख्स पर फूल बरसाने के बाद दो उंगलियों से 'विक्टरी साइन' बनाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान एक लड़की बुजुर्ग के हाथ में श्रीफल (नारियल) थमाकर उनकी आरती उतारती नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की समीक्षा की

भाषा। नई दिल्ली

● कहा- राज्य विशिष्ट समाधान तैयार करना जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में सभी राज्यों के लिए एक जैसा ही समाधान की तलाश करने के बजाय प्रत्एक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-विशिष्ट समाधान तैयार करना चाहिए। मोदी ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्थायित्व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

मोदी ने कहा, विद्युत सेक्टर, विशेष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वे सभी क्षेत्रों और राज्यों में एक जैसी नहीं हैं। मंत्रालय को सभी राज्यों के लिए ठीक एक जैसे ही समाधान की तलाश करने के बजाय प्रत्एक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-विशिष्ट समाधानों को प्रस्तुत करना चाहिए। विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करते हुए बुधवार को मोदी ने बिजली क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया और खास तौर पर विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों में बिजली वितरण एवं पारेषण खंड की समस्याओं को रेखांकित किया।

बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने बैठक में बिजली क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु की गई विभिन्न नीतिगत पहलों पर चर्चा की जिनमें संशोधित शुल्क नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्थायित्व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए

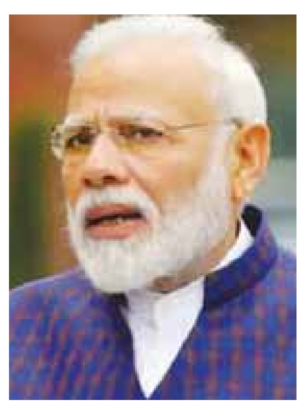

उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनका प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है। उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि बिजली क्षेत्र में उपयोग में आने वाले उपकरण मेक इन इंडिया के अनुरूप होना चाहिए।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सोलर वाटर पंपों से लेकर विकेन्द्रीकृत सौर शीत भंडारणों तक की कृषि क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रूफटॉप सोलर के लिए भी अभिनव मॉडल पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही यह इच्छा जताई कि प्रत्एक राज्य में कम-से-कम एक शहर (या तो राजधानी शहर या कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल) ऐसा हो, जो रूफटॉप सौर ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से पूरी तरह से सौर शहर हो। प्रधानमंत्री ने कार्बन मुक्त लद्दाख की योजना में तेजी लाने की इच्छा जताई और इसके साथ ही सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग करके तटीय इलाकों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष बल दिया।

चक्रवात प्रभावित पश्चिम बंगाल में भारी बारिश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रात भर हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण दो लोगों की मौत हो गई। इस वजह से शहर और बंगाल के दक्षिणी जिलों को बृहस्पतिवार को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। हफ्ते भर पहले ही चक्रवात अम्फान ने राज्य में काफी तबाही मचाई थी। पुलिस ने बताया कि उत्तर 24 परगना में दीवार गिरने से 40 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच अन्य जख्मी हो गए। आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी बर्धमान जिले के दुर्गापुर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोलकाता यातायात पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बुधवार शाम से बारिश होना शुरू हुई। कुछ ही घंटों में शहर के कई इलाकों में पानी भर गया जिससे चक्रवात के मद्देनजर राहत काम में लगे कर्मचारियों को परेशानी हुई। राज्य में 20 मई को चक्रवात आया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संवेदनशील समूहों को भी शामिल करने का अनुरोध किया

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मादक पदार्थों के आदी लोगों, समलैंगिकों और एचआईवीएड्स पीड़ित व्यक्तियों सहित संवेदनशील समूहों को भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने का अनुरोध किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वे कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते अपनी आजीविका और आश्रय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय को नागरिक समाज से संबंधित संगठनों और मादक पदार्थों के आदी लोगों, समलैंगिक समुदाय, महिला यौनकर्मियों और एचआईवीएड्स पीड़ित लोगों की ओर से प्रतिवेदन मिले हैं कि वे वे आजीविका, पोषण, आश्रय और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के मामले में बहुत प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) की उप महानिदेशक डॉ शोभिनी राजन ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय गहनता से कोविड-19 से निपटने में जुटा है। उसने उन लोगों के लिए सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित को लेकर कदम उठाए हैं, जिन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। पत्र में कहा गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय एचआईवी और अन्य प्रभावित लोगों को उपचार के संदर्भ में दवाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए आजीविका, पोषण और आश्रय आदि से संबंधित कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को संबोधित करते हुए लिखे गए इस पत्र में कहा गया है, अनुरोध किया जाता है कि आप इस मामले पर विचार करें।

बीकानेर में सरदार मेडिकल कॉलेज के बाहर अपने वजीफे में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते मेडिकल छात्र

कोविड-19 के अनसुलझे रहस्यों में संभावित उत्परिवर्तन, असामान्य लक्षण शामिल

भाषा। नई दिल्ली

नोवेल कोरोना वायरस के विभिन्न रूपों में परिवर्तित होने, सूंघ नहीं पाने जैसे असामान्य लक्षणों के अज्ञात कारणों और डेंगू की जांच में रोगियों के नमूनों की गलत रिपोर्ट जैसे कोविड-19 से जुड़े कुछ रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं।

वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआत से ही कोविड-19 को लेकर विभिन्न अध्ययनों में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को सुलझाने से बीमारी के प्रभावी उपचारात्मक तरीके मिल सकते है। इस महामारी ने अभी तक पूरी दुनिया में 56 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया है और 3,55,000 लोगों की अब तक इससे जान जा चुकी है।

विषाणु विज्ञानी उपासना रे ने पीटीआई-भाषा से कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से जुड़ा एक बड़ा रहस्य स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन की दर को लेकर है। कोलकाता स्थित सीएसआईआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल

बायोलॉजी की वरिष्ठ वैज्ञानिक उपासना ने कहा कि स्पाइक प्रोटीन वायरस को होस्ट सैल से जुड़ने और उसमें प्रवेश करने में मदद करता है।

उपासना रे और उनकी टीम ने अपने अध्ययन में भारतीय रोगियों से लिए गए सार्स-सीओवी-2 के नमूनों में उत्परिवर्तन को देखा। अध्ययन की अभी विशेषज्ञ समीक्षा नहीं हुई है। अनुसंधानकर्ताओं ने स्पाइक प्रोटीन के विशेष क्षेत्रों में मुड़ी हुई संरचनाएं देखीं जो उनके मुताबिक वायरस के होस्ट सैल से जुड़ाव को प्रभावित कर सकती हैं।

उपासना ने कहा कि टीके संबंधी इंजीनियरिंग के लिए नोवेल कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के अंदर हो रहे उत्परिवर्तन पर सावधानी से विचार होना चाहिए। सार्स-सीओवी-2 से संबंधित एक और गुत्थी है कि वायरस संक्रमित रोगी की अन्य एंटीबॉडी के लिए की गई जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है।

त्रिपुरा में बनेगा अखिल भारतीय वाक-श्रवण संस्थान का पूर्वोत्तर केंद्र

अगरतला। केंद्र ने अखिल भारतीय वाक- श्रवण संस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र पश्चिम त्रिपुरा जिले में बनाने का फैसला किया है। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। नाथ ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के छात्रों को संस्थान में पढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संस्थान में मूक-बाधिर बच्चों को पढ़ाने और उनके उलाज से संबंधित डिप्लोमा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में संस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का निर्णय है।

पेज एक का शेष

नहीं ले...

भी कहा कि सारे कामगार अपने पैतृक राज्य नहीं जाना चाहते हैं और इनमें से कुछ काम करना चाहते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने इन कामगारों की दयनीय स्थिति के संबंध में केन्द्र से अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायालय ने जानना चाहा कि आखिर इन कामगारों को अपने पैतृक शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा और उनकी यात्रा के किराये का भुगतान कौन करेगा। न्यायालय ने इन कामगारों के लिये भोजन और पानी की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। पीठ ने मेहता से जानना चाहा कि आखिर इन श्रमिकों की यात्रा के भाड़े के भुगतान को लेकर किस तरह का भ्रम है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन कामगारों को अपने घर लौटने के लिये यात्रा के भाड़े का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं किया जाये। पीठ ने कामगारों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुये मेहता से सवाल किया, 'सामान्य समय क्या है? यदि एक प्रवासी की पहचान होती है तो यह तो निश्चित होना चाहिए कि उसे एक सप्ताह के भीतर या दस दिन के अंदर पहुंचा दिया जायेगा? वह समय क्या है? ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक राज्य प्रवासियों को भेजती है लेकिन दूसरे राज्य की सीमा पर उनसे कहा जाता है कि हम प्रवासियों को नहीं लेंगे, हमें इस बारे में एक नीति की आवश्यकता है।'

चीन से...

निर्माण किया है और सैनिकों को ढोने वाले हथियारों से लैस भारी वाहनों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा उसने हेलीकॉप्टर से भी हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। एलएसी पर बढ़ती गर्मी के बीच नई दिल्ली में चीन के राजदूत सुन वेईडांग ने बुधवार को कहा था कि सीमा पर तनाव को दूर करने के लिए संवाद जारी है। उसी दिन बीजिंग में उनकी सरकार ने कहा था कि सीमा पर हालात ' हालात स्थिर और नियंत्रण योग्य' है। चीन ने यह भी कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच उचित व्यवस्था और संवाद के लिए चैनल हैं।

केंद्रीय कर्मचारी...

अधिसूचित मेमोरेंडम में कहा गया है कि मास्क लगाना जहां अनिवार्य होगा वहीं थोड़े से अंतराल पर साबुन एवं सैनिटाइजर का प्रयोग भी जरूरी है। फाइलों के आदान प्रदान को जितना हो सके उतना कम करें ताकि कागजातों के अनेक हाथों से गुजरने के चलते बढ़े संक्रमण की आशंका नकारी जा सके। इतना ही नहीं कर्मचारियों एक दूसरे का फोन, ऑफिस के अन्य सामानों मसलन डेस्क, उपकरणों के प्रयोग से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। गाइडलाइन में सामूहिक रूप से दोपहर का भोजन करने से भी मना करते हुएसलाह दी गई है कि अलग-अलग समय पर लंच करें और कार्यालय के कॉरीडोरों और परिसरों में बेवजह की मटरगश्ती भी न करें। इसके अलावा इस बात पर जोर भी दिया गया है कि पहले से लागू कई मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का पूर्ववत पालन करते रहना होगा। सरकारी कार्यालयों को डेस्क और कुर्सियां जिग-जैग तरीके से व्यवस्थित करनी होगी ताकि कर्मचारी एक दूसरे की तरफ मुंह करके न बैठ पाएं। यदि कार्यालय में किसी को सर्दी जुकाम की शिकायत होती है तो उसे कम से कम 20 सेकेंड तक अपने हाथों को कोहनी तक धोकर सैनिटाइज कर लेना चाहिए। साथ ही मास्क लगाए रखना चाहिए।

केंद्र पर...

साथ ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य माध्यमों पर लांच किया गया। सोनिया के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, पी चिदंबरम एवं अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने सोशल मीडिया मंचों पर अपने मैसेज पोस्ट किए हैं। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिना विचारे थोप दिए गए लॉकडाउन के चलते हजारों लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं, कल कारखाने- दफ्तरआदि बंद पड़े हैं, किसान अपनी फसल बेचने के लिए संघर्षरत हैं, ऐसे समय केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों, कामगारों और किसानों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को प्रवासी मजदूरों, गरीब परिवारों को सीधे नकदी देनी चाहिए और एमएसएमई को वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में लाखों प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरन अपने गृह राज्यों के लिए रवाना होना पड़ा। सोनिया ने केंद्र से मांग की है कि अगले छह महीनों तक प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में प्रति माह 7,500 रुपये डाले जाएं और 10-10 हजार रुपये की तत्काल सहायता प्रदान की जाए। उनकी सुरक्षित और निशुल्क घर वापसी सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसर एवं राशन का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके अलावा मनरेगा के तहत काम के घंटे बढ़ाकर 200 दिन किया जाए जिससे गांवों में रोजगार की सुविधा मिल सके। माइक्रो, लघु, मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को लोन के बजाय वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि करोड़ों लोगों का रोजगार सुरक्षित रहे और देश प्रगति कर सके। गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अपनी पार्टी की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा देती सोनिया ने बताया कि देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार राहत गतिविधियों में जुटे हुए हैं और प्रदेश पार्टी इकाइयां मजदूरों की घर वापसी के हर संभव उपाय कर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरा देश लॉकडाउन के चलते बेहाल है लेकिन मोदी नीत सरकार को अभी तक इस बात का अहसास नहीं हो सका है। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लॉकडाउन को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। कोविड 19 के चलते देश में तूफान सा आया हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ है। लाखों परिवार पैदल घर लौटने पर मजबूर हैं, छोटे कारोबार जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं-ठप पड़े हैं। देशवासियों को पैसा चाहिए। सरकार को उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा ने अपने संदेश में बताया कि कांग्रेस ने अपने दम पर पिछले डेढ़ महीने में कम से कम 90 लाख लोगों की मदद की है। उन्होंने देशवासियों से सोशल मीडिया पर शुरू की गई स्पीक अप इंडिया मुहिम से जुड़ने की अपील भी की है। अभी तक यूपी कांग्रेस के लगभग 52 हजार कार्यकर्ता प्रियंका के साथ फेसबुक पर जुड़ चुके हैं।

कांग्रेस देश...

पर निशाना साधने के बाद विपक्षी दल पर तीखा हमला बोला। सोनिया के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश को कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, तब कुछ राजनीतिक दल देश के सामने मौजूद चुनौतियों से फायदा उठाने की कोशिश में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पराजित करने वाली ईरानी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों समेत सभी प्रदेशों की सरकारें 1.76 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की साक्षी हैं और उन्होंने इससे लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से हमारे समाज के कुछ सबसे कमजोर वर्गों को मदद मिली है। ईरानी ने कहा, संकट की इस घड़ी में, केंद्र और राज्यों के साथ ही जिलों के अधिकारियों ने भी अपने प्रयासों को एक दिशा में सम्मिलित कर दिया है। और ऐसे समय में कांग्रेस का राजनीतिक दोषारोपण में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन उससे यही अपेक्षित भी है।

दिलेर जवानों...

सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। गुरुवार को श्रीनगर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्थानीय टीमों और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी घटना स्थल का दौरा किया। जम्मू और कश्मीर पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने भी मामले में जांच करने के लिए अलग-अलग नमूने एकत्रित किए हैं। श्रीनगर में कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि हिज्बुल मुजाहिदीन (एचएम) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आईईडी विशेषज्ञों के साथ मिलकर पिछले साल 14 फरवरी को हुए पुलवामा जैसे हमले की साजिश रच रहे थे। उस हमले में सीआरपीएफके 40 जवान शहीद हुए थे। कुमार ने कहा कि पुलिस को एक सप्ताह से इनपुट मिल रहे थे कि एचएम और जेईएम आतंकवादी कार बम का उपयोग कर सुरक्षा बलों के खिलाफ एक बड़े आत्मघाती हमले की साजिष रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार देर रात जब संदिग्ध कार एक सुरक्षा जांच बिंदु पर पहुंची तो सुरक्षाबलों ने कुछ चेतावनी शॉट लगाए, लेकिन आतंकवादी कार को छोड़कर भाग गए। दूर से रोषनी कर जांच करने में मामला कुछ संदिग्ध लगा तो सुरक्षा बलों आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी और दिन निकलने का इंतजार करने लगे। गुरुवार सुबह बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और देखा कि वाहन विस्फोटक से भरा हुआ था। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ द्वारा तकनीक के सहारे आईईडी को निश्क्रिय किया गया। इस तरह बड़ी घटना टल गई।

दिल्ली में...

स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में अब तक संक्रमण के मामलों की संख्या 1,58,333 बताई है। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि 4,531 लोगों की मौत हुई है और उपचार के बाद 67,692 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं।

संबित पात्रा...

अलावा अब तक कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अशोक चव्हाण में भी इसी हफ्ते सोमवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले एनसीपी कोटे से मंत्री जितेंद्र अहवाद संक्रमित हुए थे। कांग्रेस के एक अन्य नेता संजय झा भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने खुद 22 मार्च को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।

सात राज्यों...

तीन बार 80-90 अंडे देती है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन टिड्डियों का झुंड तेजी से बढ़ सकता है। टिड्डियां मानसून शुरू होने के बाद अंडे देना शुरू कर देंगी और अगले दो महीनों तक प्रजनन जारी रखेंगी, जिससे खरीफ फसल के विकास के चरण के दौरान नई पीढ़ियां आ जाएंगी। पिछले साल दिसंबर में पहली बार भारत-पाकिस्तान सीमा पर टिड्डी दल को देखा गया था। अब इनके लगातार फैलने से किसान चिंतित हैं क्योंकि सीजन जुलाई-अगस्त-सितंबर के दौरान कीट ग्रीष्मकालीन खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसानों को कीड़ों को दूर भगाने और फसलों को बचाने के लिए तेज संगीत बजाने की सलाह दी गई है। टिड्डे जानवरों या मनुष्यों पर हमला नहीं करते हैं लेकिन फसलों और हरियाली के अन्य क्षेत्रों को तबाह कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि खतरे से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों में टिड्डी नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। अब तक, कीटनाशक स्प्रे के लिए 89 फायर ब्रिगेड, 120 सर्वेक्षण वाहन, स्प्रे नियंत्रण उपकरणों के साथ 47 नियंत्रण वाहनों और 810 ट्रैक्टर स्प्रेयर तैनात किए गए हैं। इस काम के लिए ड्रोन की भी मदद ली जाएगी। केंद्र सरकार यूनाइटेड किंगडम से 60 स्प्रेयर आयात करेगा। उनमें से 15 स्प्रेयर 11 जून तक और बीस उसके बाद 25 जून तक आने की उम्मीद है। बाकी नौ स्प्रेयर 25 जुलाई तक आ जाएंगे। इन स्प्रेयरों को राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा।

लिपजिग ने हर्था बर्लिन से 2–2 से ड्रा खेला

बर्लिन। आरबी लिपजिग ने आखिरी आधे घंटे का खेल दस खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद बुंदेसलीगा फुटबाल टूर्नामेंट में बुधवार को यहां हर्था बर्लिन को 2-2 से बराबरी पर रोका। लिपजिग की टीम एक समय जीत की तरफ बढ़ रही थी लेकिन हर्था के फारवर्ड क्रिस्टोफ पियाटेक ने 82वें मिनट में पेनल्टी पर गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलाई। इससे लिपजिग की दूसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा। मध्यांतर तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थीं।

वायरस के प्रभावों पर आईओसी सदस्यों से बात की ओलंपिक प्रमुख ने

लुसाने। ओलंपिक प्रमुख थामस बाक ने कोरोना वायरस महामारी के संभावित दुष्परिणामों को लेकर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) सदस्यों के साथ बातचीत की। इस महामारी के कारण तोक्यो ओलंपिक को 2021 तक स्थगित करना पड़ा है। बाक ने भाषा और स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार तीन अलग अलग सत्रों में आईओसी के 100 सदस्यों से बात की। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज आईओसी सदस्यों के साथ कई दौर की बातचीत की जिसमें आईसीसी सत्र की तैयारियों के बारे में उनके सुझावों को सुना गया।

अब रोम में ही होगी रोम डायमंड लीग

रोम। यूरोपीय फुटबाल चैंपियनशिप के कारण नेपल्स स्थानान्तरित कर दी गई रोम डायमंड लीग अब इटली की राजधानी में ही आयोजित की जाएगी। इटालियन एथलेटिक्स महासंघ ने बुधवार को बैठक में कहा कि यूरो 2020 के कोरोना वायरस के कारण स्थगित हो जाने के बाद अब यह यह लीग 17 सितंबर को रोम में ही आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन हालांकि ओलंपिक स्टेडियम में नहीं बल्कि स्टेडियम डि मरामी में किया जाएगा।

ट्रेनिंग शिविर से शीर्ष खिलाड़ियों का फिर इनकार

नई दिल्ली। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) जून के अंत में फिर एक ट्रेनिंग शिविर आयोजित करने का प्रयास करेगा लेकिन शरत कमल और जी साथियान सहित शीर्ष खिलाड़ी यात्रा करने को तैयार नहीं है क्योंकि हालात अब भी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने इस महीने के शुरू में खेल परिसर को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी। टीटीएफआई ने खिलाड़ियों को पत्र लिखकर जून के पहले हफ्ते में शिविर के लिए इकट्ठा होने को कहा। लेकिन कोई भी शीर्ष खिलाड़ी यात्रा करने का इच्छुक नहीं था और अब दूसरी बार जब महासंघ का पत्र उन्हें मिलेगा तो इसमें भी उनका जवाब वैसा ही होगा। भारत के शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी शरत ने पीटीआई-भाषा से कहा, हमें जुलाई में यह करना चाहिए। यात्रा करने के लिए यह अब भी काफी जल्दी है और चीजें अभी तक व्यवस्थित नहीं हुई है। मामलों का बढ़ना जारी है। इनमें कुछ स्थिरता तो होनी चाहिए, तब तक हम घर पर जैसे ट्रेनिंग कर रहे है, करते रहेंगे।

भारत अक्टूबर में करेगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा

● क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कार्यक्रम घोषित किया, भारत के खिलाफ पूर्ण श्रृंखला शामिल

कार्यक्रम इस प्रकार है : पुरूष टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला - पहला टी20 : 11 अक्टूबर, ब्रिसबेन, दूसरा टी20 : 14 अक्टूबर, कैनबरा, तीसरा टी20 : 17 अक्टूबर, एडीलेड, **पुरूष टेस्ट श्रृंखला** - पहला टेस्ट : तीन से सात दिसंबर, ब्रिसबेन, दूसरा टेस्ट : 11 से 15 दिसंबर, एडीलेड (दिन-रात्रि), तीसरा टेस्ट : 26 से 30 दिसंबर, एमसीजी, चौथा टेस्ट : तीन से सात जनवरी, एससीजी, **पुरूष वनडे श्रृंखला** - पहला वनडे : 12 जनवरी, पर्थ,दूसरा वनडे : 15 जनवरी, एमसीजी, तीसरा वनडे : 17 जनवरी, एससीजी,**महिला वनडे श्रृंखला** - पहला वनडे : 22 जनवरी, कैनबरा, दूसरा वनडे : 25 जनवरी, मेलबर्न,तीसरा वनडे : 28 जनवरी, होबार्ट

भाषा। मेलबर्न

क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने अटकलों का दौर खत्म करते हुए गुरूवार को पुष्टि की कि भारतीय टीम वित्तीय रूप से अहम चार टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए इस साल अक्टूबर में उसके देश का दौरा करेगी। सीए ने कोविड–19 महामारी का प्रभाव कम होने के बाद अपना गर्मियों का छह महीने का घरेलू कार्यक्रम घोषित किया जो नौ अगस्त से तीन मैचों की श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे के दौरे से शुरू होगा। सीए ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया कि भारत टी20 श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा करेगा जिसकी शुरूआत 11 अक्टूबर को ब्रिसबेन से होगी जिसके बाद 14 अक्टूबर (कैनबरा) और 17 अक्टूबर (एडीलेड) को मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टी20 विश्व कप होगा और महामारी के चले इसके आयोजन होने की संभावना काफी कम है। सीए ने हालांकि गुरूवार को जारी अपने अधिकारिक जारी कार्यक्रम में टी20 विश्व कप का जिक्र नहीं किया। विराट कोहली की टीम फिर चार टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए वहां जाएगी जिसकी शुरूआत तीन दिसंबर से ब्रिसबेन में होगी। भारत इसमें एडीलेड में 11 से 15 दिसंबर तक एक दिन–रात्रि टेस्ट खेलेगा जैसा कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने वादा किया था। तीसरा और चौथा टेस्ट क्रमश: मेलबर्न (26 से 30 दिसंबर) और सिडनी (तीन से सात जनवरी) को खेला जाएगा। सीए के वित्तीय हालात के लिए यह श्रृंखला काफी अहम है जिसे महामारी के चलते अपने परिचालन को संभालने के लिए स्टाफ को कम करना पड़ा। सीए को भारत के इस दौरे से 30 करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर की कमाई होगी। इसके बाद तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 12 जनवरी को पर्थ में मैच से शुरू होगी और इसके बाद 15 जनवरी को मेलबर्न और 17 जनवरी को सिडनी को खेला जाएगा। सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन रोबर्ट्स ने बयान में कहा, हम बीसीसीआई के साथ मिलकर पुरूष और महिला दौरों पर काम कर रहे हैं और हम न्यूजीलैंड की पुरूष और महिला टीमों के खिलाफ भी महत्वपूर्ण श्रृंखला का आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम भी वनडे श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा करेगी जिसमें मैच कैनबरा (22 जनवरी), सेंट किल्डा (25 जनवरी) और होबार्ट (28 जनवरी) में खेले जाएंगे। उन्होंने साथ ही संकेत दिया कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो इस कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है जिसमें न्यूजीलैंड (पुरूष और महिला), वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट (21 से 25 नवंबर) की श्रृंखलाएं शामिल हैं।

आईसीसी बोर्ड ने टी20 विश्व कप पर फैसला 10 जून तक टाला

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड ने गुरुवार को आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप सहित अपने एजेंडे में शामिल सभी मामलों पर फैसले को 10 जून तक टाल दिया। विश्व कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित किए जाने और इस विंडो का इस्तेमाल फिलहाल स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए किए जाने की अटकलें लगाई जा रही है।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया क्रिकेट प्रमुख ने मेजबानी नहीं मिलने पर सीए पर निशाना साधा

पर्थ। पश्चिम आस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ (वाका) की प्रमुख क्रिस्टीना मैथ्यूज ने भारत के खिलाफ होने वाली हाई प्रोफाइल टेस्ट श्रृंखला के लिए पर्थ पर ब्रिसबेन को तरजीह देने के लिए क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) पर निशाना साधा है। क्रिस्टीना का कहना है कि नवनिर्मित आप्टस स्टेडियम हर तरह से गाबा से बेहतर है। इसके बावजूद पर्थ को नवंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ कम महत्वपूर्ण एकमात्र टेस्ट की मेजबानी सौंपी गई।भारतीय टीम चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा करेगी जिसकी शुरूआत तीन दिसंबर से ब्रिसबेन में होगी।

आईओए में वाकयुद्ध जारी

● बतौर अध्यक्ष वह समितियां गठित कर सकते हैं : बत्रा

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच वाकयुद्ध जारी रहा जिसमें अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने दावा किया कि संस्था का संविधान उन्हें समिति या आयोग गठित करने का अधिकार देता है जो कार्यकारी परिषद या आम सभा की मंजूरी के अधीन है। मंगलवार को आईओए महासचिव राजीव मेहता ने बत्रा के 19 मई के नैतिक आयोग को भंग करने के फैसले को अवैध करार दिया था जो 2017 में गठित किया गया था। मेहता ने कहा था कि नैतिकता नियमों के अंतर्गत आयोग का कार्यकाल 2018 में आम सभा की बैठक ने तय किया था जिस पर बत्रा ने हस्ताक्षर किए थे और यह चार वर्ष का था और अध्यक्ष दो साल पहले ही इसे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन बत्रा ने कहा कि आईओए संविधान के अनुसार उनके पास एक आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार है। बत्रा ने कहा, मुझे 18.3 नियम में कोई जिक्र नहीं मिला कि अध्यक्ष को किसी समितिआयोग को गठित करने में महासचिव से सलाह लेनी ही पड़ेगी या उसका इसमें शामिल होना जरूरी होगा। आम सालाना बैठक (एजीएम) या आम सभा को संविधान की सीमाओं के अंदर काम करना होता है और यह संविधान के अंतर्गत बाध्य है और अगर किसी भी समय एजीएम या कार्यकारी समिति संविधान का उल्लंघन करती है तो संविधान निश्चित रूप से प्रभावी होगा। बत्रा ने साथ ही कहा कि उन्होंने समितियों ओर आयोंगों को गठित करने का फैसला आईओए संविधान के 18.3 नियम के अनुसार लिया इसलिए ए अध्यक्ष के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यह अच्छी तरह पता है जिसके पास नियुक्ति का अधिकार है, उसके बाद हटाने का भी अधिकार है। इस मौजूदा मामले में आईओए के कार्यकारी बोर्ड ने 27 मार्च 2019 को आईओए अध्यक्ष की सिफारिशों पर नैतिक आयोग के कार्यकाल को मजूंरी दी जो 2019 के अंत तक का था।

तोक्यो ओलंपिक की होटल बुकिंग में नुकसान के लिए खन्ना से स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने तोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए होटल बुकिंग में देरी के कारण हुए नुकसान के लिए गुरुवार को वित्त समिति के अध्यक्ष अनिल खन्ना से स्पष्टीकरण मांगा। इस विलंब के कारण बजट में लगभग 73 लाख रुपए का इजाफा हुआ। आईओए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खन्ना को लिखे पत्र में बत्रा ने बताया कि किस तरह उनकी ओर से 15 दोहरे कमरों की बुकिंग में स्वीकृति में विलंब के कारण देश में खेल की सर्वोच्च संस्था के खर्चों पर असर पड़ा। बत्रा ने 750 डॉलर के पुराने किराए का जिक्र करते हुए कहा, आपने वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में, अपनी समझ से जून 2019 में इसे स्वीकृति नहीं देने का फैसला किया और इसे लंबित रखा, अंततः फरवरी 2020 में इसे स्वीकृति दी जब प्रति दोहरे कमरे का किराया 1080I1090 डॉलर था। यह बुकिंग 18 रात के लिए थी। वित्तीय समिति के अध्यक्ष के रूप में आपकी या पूरी वित्त समिति की ओर से विलंब के कारण आईओए को अब 72,84,600 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं उपरोक्त पर जल्द से जल्द तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने का अाग्रह करता हूं।

विराज व आरपी सिंह बने आईओए प्रीप्रेशन कमेटी में सदस्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन (यूपीओए) के अध्यक्ष विराज सागर दास को आगामी बीच गेम्स 2020–21 के लिए गठित भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की प्रीप्रेशन कमेटी में सदस्य चुना गया है। इस 16 सदस्यीय कमेटी में डा. आरपी सिंह (महासचिव यूपी हाकी व आईओए एथलीट कमेटी सदस्य) को भी सदस्य चुना गया है। यह कमेटी आगामी प्रस्तावित बीच गेम्स 2020–21 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के चयन व तैयारी संबधी सुविधाओं को देखेगी और इस बारे में आईओए अध्यक्ष व महासचिव के समन्वय से काम करेगी। इस बारे में उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन (यूपीओए) के समस्त पदाधिकारियों ने बधाई दी और उम्मीद जताई कि विराज सागर दास व डा. आरपी सिंह के अनुभव का लाभ इस कमेटी को जरूर मिलेगा।

कोषाध्यक्ष ने बत्रा के कदम को संविधान का उल्लंघन करार दिया

नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे ने हाल में उठाए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के कदमों को आईओए संविधान का उल्लंघन करार दिया और देश में खेल की सर्वोच्च संस्था की कार्यकारी परिषद की जून में बैठक बुलाने की मांग की।

कुंबले और लक्ष्मण को आईपीएल के आयोजन की उम्मीद

भाषा। नई दिल्ली

पूर्व भारतीय कप्तान और किंग्स इलेवन पंजाब के मुख्य कोच अनिल कुंबले को उम्मीद है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आयोजन होगा और उन्होंने कोविड–19 महामारी के चलते दर्शकों के बिना इस धनाढ्य लीग के आयोजन का भी समर्थन किया। यह अभी आधिकारिक नहीं है लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर में करना चाहता है। कोविड–19 महामारी के कारण टूर्नामेंट अभी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट कनेक्टेड में कहा, हां हम इस साल आईपीएल के आयोजन के प्रति आशान्वित हैं लेकिन इसके लिए हमें कार्यक्रम को काफी व्यस्त करना होगा। अगर हम दर्शकों के बिना मैचों का आयोजन करते हैं तो फिर इन्हें तीन या चार स्थलों पर आयोजित किया जा सकता है। इसके आयोजन की अब भी संभावना है। हम सभी आशावादी हैं।

लॉकडाउन में गैर अनुबंधित और अंडर–19 खिलाड़ियों को मिली मानसिक स्वास्थ्य की सीख : द्रविड़

कोलकाता। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख और पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने खुलासा किया कि कोविड-19 लॉकडाउन के बीच गैर अनुबंधित और अंडर-19 खिलाड़ियो के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओ पर पेशेवरों की मदद से गौर किया गया। द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आयोजित वेबीनार में स्वीकार किया कि क्रिकेटरों के लिए यह अनिश्चितता भरा दौर है जिससे वे मानसिक तौर पर प्रभावित हो सकते है। लॉकडाउन में हमने इस मुद्दे (पेशेवरों के जरिए खिलाड़ियो के मानसिक स्वास्थ्य पर काम) पर गौर करने की कोशिश की। हमने अनुबंध सूची से बाहर और अंडर-19 खिलाड़ियों की पहचान की। हमने उन्हे पेशेवरों की मदद लेने का मौका दिया। पूर्व क्रिकेटर होने के नाते मेरा मानना है कि पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट कोच के पास इस तरह के मसलो से निबटने की विशेषज्ञता नही है जिनसे की इन दिनों कुछ युवा गुजर रहे है। हमारे लिए यही अच्छा था कि हम इसके लिए पेशेवरों की मदद ले। उन्होने स्वीकार किया कि क्रिकेट मे मानसिक स्वास्थ्य एक मुद्दा है लेकिन साथ ही खुशी भी व्यक्त की कि अब इस पर लगातार चर्चा हो रही है।

राष्ट्रीय खेल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली। पहले से ही कई बार टल चुके 36वें राष्ट्रीय खेल कोरोना वायरस महामारी के कारण अब अनिश्चितकाल के लिए टाल दिए गए हैं। ए खेल अक्टूबर नवंबर में गोवा में होने थे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने हाल ही में गोवा सरकार से कहा था कि वह इस साल 20 अक्टूबर से चार नवंबर के बीच राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करे। कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के कारण इन्हें स्थगित करने का फैसला किया गया। आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा द्वारा भेजे गए एक बयान में गोवा के उप मुख्यमंत्री और खेल का भी प्रभार देख रहे मनोहर अजगांवकर ने कहा , राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति ने कोरोना महामारी के कारण खेलों को स्थगित करने का फैसला किया है। समिति सितंबर के आखिरी में बैठक करेगी और राष्ट्रीय खेलों की तारीख तय की जाएगी। गोवा सरकार केंद्रीय खेल मंत्रालय से सलाह लेगी। खेलों के आयोजन के लिए चार महीने की अग्रिम सूचना चाहिए होगी। पिछले राष्ट्रीय खेल केरल में 2015 में हुए थे। आगामी राष्ट्रीय खेल पहले नवंबर 2018 में होने थे लेकिन फिर अप्रैल 2019 तक के लिए स्थगित कर दिए गए।

लार के इस्तेमाल की आदत को छोड़ना मुश्किल : अरुण

● सभी टीमों को समान मौका मिलता है तो कृत्रिम पदार्थ के इस्तेमाल का प्रयास होना चाहिए

भाषा। नई दिल्ली

भारत के गेंदबाजी कोच भरत अरूण का मानना है कि गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल की आदत को छोड़ना मुश्किल होगा लेकिन इस इसकी जगह कृत्रिम पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं जब तक कि सभी टीमों को इसके उपयोग का समान अवसर मिले। कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए अनिल कुंबले की अगुआई वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की क्रिकेट समिति ने स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के तहत लार के इस्तेमाल को प्रतिबंध करने का प्रस्ताव रखा है। कई शीर्ष खिलाड़ियों और कोचों का मानना है कि गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गेंद को चमकाने के लिए कृत्रिम पदार्थ के इस्तेमाल की स्वीकृति मिलनी चाहिए। अरूण ने हाल में बातचीत के दौरान कहा, जहां तक बाहरी पदार्थ के उपयोग का सवाल है तो जब तक यह सभी टीमों के लिए समान हैं तो इसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। लार का इस्तेमाल करने की आदत को छोड़ना काफी मुश्किल होगा लेकिन हमारे ट्रेनिंग और अभ्यास सत्र के दौरान हमें इस आदत को छोड़ने का प्रयास करना होगा। दुनिया के शीर्ष तेज गेंदबाज और इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पैट कमिंस भी लार पर प्रतिबंध लगने के कारण बाहरी पदार्थ के इस्तेमाल का पक्ष ले चुके हैं। आईसीसी ने गेंद पर पसीने के इस्तेमाल को प्रतिबंधित नहीं किया है जिससे कोरोना वायरस नहीं फैलता लेकिन कमिंस चाहते हैं कि खेल की वैश्विक संस्था गेंदबाजों के लिए कुछ और पहल करे। क्रिकेट.काम.एयू ने कमिंस के हवाले से कहा , पसीना बुरा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि हमने इससे कुछ अधिक की जरूर है। यह कुछ भी हो, वेक्स या कुछ और जो कुझे नहीं पता। पूर्व महान स्पिनर शेन वार्न ने हाल में सुझाव दिया था कि गेंद को एक तरफ से भारी किया जाए जिससे कि स्विंग कराने में मदद मिले।

वित्त मंत्री ने एफएसडीसी बैठक की अध्यक्षता की, अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने यह समीक्षा ऐसे समय की है जब कोविड–19 संकट के कारण आर्थिक गतिविधिंा बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कोरोना वायरस महामारी के बाद एफएसडीसी की यह पहली बैठक थी। इसमें अरबीआई गवर्नर तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रों के नियामक शामिल हैं। फिच रेटिंग्स, क्रिसिल समेत कई एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है। ऐसी स्थिति में वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए हुई एफएसडीसी की यह 22वीं बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद एक अधिकारी ने कहा कि कोविड–19 के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई है। बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एफएसडीसीउप–समिति और वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न नियामकों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया गया। क्षेत्रीय नियामकों के लिए एफएसडीसी शीर्ष निकाय है जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। आरबीआई गवर्नर के अलावा सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) प्रमुख अजय त्यागी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के चेरमैन सुभाष चंद्र खुंतिया, ऋण शोधन एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) के चेयरमैन एम एस साहू और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय भी बैठक में मौजूद थे। आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे, वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा समेत वित्त ममंत्रा अन्य शीर्ष अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

दबाव में कर्ज देने से और दुर्बल हो जाएंगे बैंक, दो साल में छह प्रतिशत बढ़ जाएगा एनपीए: फिच

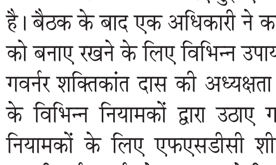

मुंबई। फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दीफिच रेटिंग्स ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी कि सरकार के करीब 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के तहत पहले से स्वीकृत उधार देने से उन्हें कर्ज की किस्ते वसूल करने में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रपट में कहा गया है कि इससे अगले दो वर्षों के दौरान उनके बकाया ऋण अनुपात में छह प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि जबरन कर्ज देने के दबाव के चलते बैंकों का बकाया ऋण अनुपात दो प्रतिशत से छह प्रतिशत के बीच हो सकता है। यह बैंकों के हालात की गंभीरता और बैंकों के जोखिम लेने की क्षमता और उच्च नियामक प्रावधानों पर निर्भर करेगा। एजेंसी ने हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए के बारे में अलग–अलग जानकारी नहीं दी। सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज में बैंक ऋण में कई तरह की राहत और कर्ज अदायगी में दी गई मोहलत में 90 दिनों की वृद्धि शामिल है। फिच की रिपोर्ट में कहा गया है कि ए उपाय विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भारी बोझ डालेंगे, जिनकी बैलेंस शीट पहले ही बहुत कमजोर है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के काबू में आने तक उपभोक्ता मांग और विनिर्माण, दोनों ही खराब स्थिति में रहने वाले हैं।

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी

● सेंसेक्स 595 अंक की बढ़त से 32,000 अंक के पार

भाषा। नई दिल्ली

सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहा और सेंसेक्स 595 अंक और चढ़ गया। मई के डेरिवेटिव्स अनुबंधों के निपटान के बीच बाजार में व्यापक लिवाली देखने को मिली। सेंसेक्स की बड़ी कंपनियों एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलएंडटी तथा आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में बढ़त से भी बाजार धारणा को बल मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 595.37 अंक यानी 1.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 32,200.59 अंक पर बंद हुआ। दिन में यह 32,267.23 अंक के स्तर तक भी गया। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 175.15 अंक या 1.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,490.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एलएंडटी का शेयर सबसे अधिक 6.17 प्रतिशत चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर आईटीसी, एसबीआई और भारती एयरटेल के शेयर 0.83 प्रतिशत तक टूट गए। विश्लेषकों ने कहा कि मई के डेरिवेटिव्स अनुबंधों के निपटान के मद्देनजर भागीदारों की शॉर्ट कवरिंग से बाजार में व्यापक तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा वैश्विक बाजारों के मजबूत रुख से भी यहां धारणा को बल मिला। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, यूरोपीय संघ की एक बड़ा पैकेज देने की योजना से यूरोपीय शेयरों में तेजी आई। अमेरिका–चीन राजनयिक मुद्दों की वजह से एशियाई बाजारों के शेयर प्रभावित हुए। भारत में हालांकि कोविड–19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से बाजार ने राहत की सांस ली है। प्रोत्साहन उपायों से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को मदद मिलेगी। जमीनी वास्तविकताओं में मामूली बदलाव ही आया है लेकिन उम्मीदों के बीच बाजार में तेजी आ रही है। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 1.42 प्रतिशत तक का लाभ रहा। अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीदों के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी रहीं। अमेरिका का डाउ जोंस मार्च के बाद पहली बार 25,000 के ऊपर बंद हुआ। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट और जापान का निक्की लाभ में रहे। वहीं हांगकांग के हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार एक प्रतिशत तक के लाभ में थे। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 34.92 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी पांच प्रतिशत की कमी

भाषा। नई दिल्ली

एसएंडपी का अनुमान

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने गुरुवार को कहा कि कोविड–19 महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में पांच प्रतिशत घट सकती है। एसएंडपी ने एक बयान में कहा, हमने मार्च 2021 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर नकारात्मक पांच प्रतिशत कर दिया है... इस समय हमारा मानना है कि (महामारी का) प्रकोप तीसरी तिमाही में चरम पर होगा। इससे पहले इस सप्ताह रेटिंग एजेंसी फिच और क्रिसिल ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत संकुचन का अनुमान जताया था। एसएंडपी ने एक बयान में कहा, भारत में कोविड–19 के प्रकोप और दो महीने के लॉकडाउन – कुछ क्षेत्रों में इससे भी लंबे समय तक – ने अर्थव्यवस्था में अचानक रुकावट पैदा कर दी है। इसका मतलब है कि इस वित्त वर्ष में वृद्धि तेजी से संकुचित होगी। आर्थिक गतिविधियां अगले एक साल तक व्यवधान का सामना करेंगी। भारत में अभी तक कोविड–19 पर काबू नहीं पाया जा सका है। पिछले एक सप्ताह में नए मामले नए मामले प्रतिदिन 6,000 से अधिक रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में कमी की है, जिससे संक्रमण के मामले बढ़े हैं।

देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019–20 में 13 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 49.98 अरब डॉलर पर पहुंचा

नई दिल्ली। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2019-20 में 13 प्रतिशत बढ़कर 49.97 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में देश को कुल 44.36 अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक समीक्षावधि में देश के सेवा क्षेत्र ने 7.85 अरब डॉलर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र ने 7.67 अरब डॉलर, दूरसंचार क्षेत्र ने 4.44 अरब डॉलर, व्यापार क्षेत्र ने 4.57 अरब डॉलर, वाहन क्षेत्र ने 2.82 अरब डॉलर, निर्माण क्षेत्र ने दो अरब डॉलर और रसायन क्षेत्र ने एक अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे की गिरावट के साथ 75.76 पर बंद

मुंबई। अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पांच पैसे की गिरावट के साथ 75.76 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार कारोबार के दौरान रुपया सीमित दायरे में रहा। घरेलू शेयर बाजार में तेजी से जहां रुपए पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा वही अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ने से यह लाभ जाता रहा। अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया गिरावट के साथ 75.90 पर खुला लेकिन बाद में चीजें बेहतर हुई और अंत में यह डॉलर के मुकाबले बुधवार को बंद भाव के मुकाबले 5 पैसे की गिरावट के साथ 75.76 पर बंद हुआ।

ट्रेंट लिमिटेड की आय बढ़ी

मुंबई। ट्रेंट लिमिटेड कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त चौथी तिमाही और वित्त वर्ष के वित्तीय परिणामों स्टैंडअलोन और समेकित की घोषणा की। तिमाही में संचालन से मिलने वाली आय 8 फीसद बढ़कर 723 करोड़ रुपये दर्ज की गयी है। संचालन से प्राप्त होने वाला मुनाफा। 2गुणा12 करोड़ रुपये है जोकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 90 फिसद कम है।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल कैलाश प्रसाद पुत्र श्री मुनेश्वर प्रसाद निवासी मकान न0 A-495, Block-A, कैंप न0 4, ज्वाला पुरी, दिल्ली–110087, ने अपनी बेटी सीता देवी पति श्री चन्दर पाल नाती लव और बेटा रोशन कुमार पिता श्री कैलाश प्रसाद और बहु सोनी देवी पत्नी श्री रोशन कुमार को उनके दुर्व्यवहार के कारण अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सभी सम्बंध विच्छेद कर लिये हैं इस पर हुए लेनदेन पुलिस केस की जवाबदेई मेरे मुवक्किल की नहीं होगी।

(एडवोकेट)
महेन्द्र कुमार

ADITYA BIRLA CAPITAL
संरक्षण निवेश वित्त सलाह
आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयन कम्पाउण्ड, वेरावाल, गुजरात – 362 266
सीआईएन : U65990GJ1991PLC064603

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अधीन]

जबकि,
अधोहस्ताक्षरी ने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, द्वितीय तल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 15–01–2020 जारी की थी, जिसमें कर्जदारों/सह–कर्जदारों मैसर्स साकेत इंडस्ट्रीज से इसके सह–कर्जदार नामत: श्री जावेद मोहम्मद, श्री फिरोज मोहम्मद, श्रीमी नूर जहां, श्रीमती फरजाना हसन, मैसर्स जे.के. एंटरप्राइजेज से सूचना में वर्णित बकाया राशि रू. 1,19,61,990 (रूपए एक करोड़ उन्नीस लाख इकसठ हजार नौ सौ नब्बे मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 27 मई, वर्ष दो हजार बीस को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, द्वितीय तल, यूको बैंक बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 की बकाया राशि रू. 1,19,61,990 (रूपए एक करोड़ उन्नीस लाख इकसठ हजार नौ सौ नब्बे मात्र) तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन :–

अचल सम्पत्ति सम्पत्ति/प्लॉट नंबर 57, भू तल, ब्लॉक–ई, विपुल वर्ल्ड, गुड़गांव, हरियाणा–122001 तथा सम्पत्ति/प्लॉट नंबर 50, द्वितीय तल, ब्लॉक–ई, सेक्टर–48, गुड़गांव, हरियाणा–122001 का साम्यिक बंधक।

आदित्य बिड़ला फाइनैंस लिमिटेड
हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : गुड़गांव
तिथि : 28–05–2020

ईरान परमाणु समझौते के तहत मिल रही रियायतों को समाप्त करेगा अमेरिका

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नीत प्रशासन 2015 के ईरान परमाणु समझौते के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों से अब भी मिल रही लगभग सभी रियायतों को समाप्त करने जा रहा है। अमेरिका के मौजदा और पूर्व अधिकारियों समेत संसद के सलाहकारों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बुधवार को बताया कि विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ इस समझौते से जुड़ी केवल एक रियायत को छोड़कर बाकी सभी रियायतें समाप्त करेंगे। इन रियायतों के तहत रूस, यूरोपीय और चीनी कंपनियों को ईरान के नागरिक परमाणु प्रतिष्ठानों में बिना अमेरिकी जुर्माने के काम जारी रखने की छूट थी। इन रियायतों का मार्च में नवीनीकरण किया गया था और यह इस सप्ताह के अंत में समाप्त होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार इस रियायत को समाप्त किए जाने के बाद कंपनियों को अपना कामकाज समेटने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा। ए

● कंपनियों को अपना कामकाज समेटने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा

अधिकारी सार्वजनिक तौर पर इस मामले पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और इन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। इस संबंध में औपचारिक घोषणा बृहस्पतिवार को हो सकती है।पोम्पिओ ने रियायत को आगे बढ़ाने का विरोध मार्च में किया था। परमाणु समझौते से जुड़ी हुई यह कुछ वैसी रियायतें हैं जिसे ट्रंप प्रशासन ने रद्द नहीं किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस परमाणु समझौते से अलग कर लिया था और ईरान पर वे प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए थे जिसमें इस समझौते के तहत उसे थोड़ी रियायत दी गई थी या प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिए गए थे। नागरिक परमाणु सहयोग रियायत विदेशी कंपनियों को ईरान के कुछ घोषित परमाणु प्रतिष्ठानों में बिना अमेरिकी प्रतिबंध का सामना किए हुए काम करने की मंजूरी देता है। ईरान परमाणु समझौते के समर्थकों का कहना है कि इस रियायत से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को ईरान की परमाणु नीति के बारे में जरूरी जानकारी मिलती है और इसके बिना ऐसा नहीं हो पाएगा। उनका कहना है कि ईरान में इस संबंध में हो रहे कुछ कार्य जैसे कि तेहरान परमाणु भट्ठी में परमाणु समस्थानिकों से जुड़े कार्य का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में हो सकता है और यह मानवीय कार्य से जुड़ा है। वहीं संसद में ईरान की आलोचना करने वालों ने पोम्पिओ पर दबाव डाला है कि वह सभी तरह की छूटों को समाप्त करें क्योंकि इससे ईरान को वैसे तकनीक हासिल होती हैं जिसका इस्तेमाल वह हथियार के लिए कर सकता है। इन आलोचकों ने उस छूट पर कड़ी आपत्ति जताई थी जो ईरान के किसी समय गोपनीय माने जाने वाले फोरदो प्रतिष्ठान में काम जारी रखने की अनुमति देती है।

केप कैनावेरल के कैनेडी स्पेस सेंटर में स्पेसएक्स डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन-2 लॉन्च को देखने से पहले नासा के एक दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

'चीन की बाहुबल की नई नीति का भारत एवं अन्य देशों के साथ संबंधों का असर पड़ेगा'

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक ने कहा है कि चीन की बाहुबल की नई नीति का भारत एवं अन्य देशों के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया अब अंततः इस बात को समझ रही है कि चीन समस्याग्रस्त शासन के प्रारूप को आगे बढ़ा रहा है।

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के स्रोत, व्यापार, हांगकांग में चीनी कार्वाई और विवादित दक्षिण चीन सागर में आक्रामक सैन्य कदमों के कारण अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। पूर्वी एशियाई एंव प्रशांत मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री डेविड स्टिलवेल ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन जो कदम उठा रहा है उसका केवल जलडमरूमध्य में ही नहीं, बल्कि उसके पार भी असर होगा। उन्होंने कहा, इससे दक्षिणपूर्वी एशिया में असर पड़ेगा, इसका असर उसके पड़ोसी भारत एवं अन्य देशों पर पड़ेगा। यह नई बाहुबल प्रदर्शन की और आक्रामक नीति रक्षा मंत्री के काम को और मुश्किल बना देगी। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे ने सप्ताहांत में कहा था कि अमेरिका और चीन की सामरिक तनातनी अत्यधिक जोखिम वाले दौर में प्रवेश कर गई है और हमें संघर्ष करते रहने की अपनी भावना को मजबूत करना होगा... स्थिरता के लिए इसका उपयोग करना होगा। स्टिवेल से इसी बयान के संबंध में सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने यह टिप्पणी की। स्टिवेल ने कहा कि दुनिया अंततः इस बात को पहचान रही है कि चीन सरकार के ऐसे प्रारूप को आगे बढ़ा रहा है जिसे कई लोग समस्याग्रस्त समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस का हांगकांग के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का कदम इस बात को और स्पष्ट तरीके से दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित विधेयक का मसौदा गत शुक्रवार को अपनी संसद में पेश किया। इसका मकसद पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग पर नियंत्रण को और मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि एक जुलाई को 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को एक देश, दो विधान के समझौते के साथ चीन को सौंपा था। समझौते की वजह से चीन की मुख्य भूमि के मुकाबले हांगकांग के लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

हांगकांग में नए सुरक्षा कानूनों को लेकर अमेरिका, चीन के बीच बढ़ी तनातनी

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

हांगकांग पर अपना नियंत्रण कड़ा करने के लिए पेश किए गए चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाए जाने के बीच अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर तीखे प्रहार किए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उन कदमों से बेहद चिंतित है जो 1984 के चीनी-ब्रितानी संयुक्त घोषणा पत्र के तहत हांगकांग को प्रदत्त अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को आधारभूत रूप से कमजोर करते हैं। यह घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र में कानूनी रूप से बाध्य संधि के रूप में दर्ज है।

अमेरिका मिशन ने कहा, यह वैश्विक चिंता का विषय है जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस मामले पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अमेरिकी मिशन ने कहा, इस प्रकार के कदम चीन द्वारा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की अवमानना और पूरी अवहेलना को दर्शाते हैं। उसने बताया कि अमेरिका ने हांगकांग की लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं नागरिक स्वतंत्रता को खतरा पैदा करने वाले चीन के प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर चर्चा के लिए बधुवार को सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक बुलाई। अमेरिकी मिशन ने बुधवार को कहा कि अपेक्षा के अनुसार चीन ने सुरक्षा परिषद की इस वर्चुअल बैठक की प्रक्रिया को आने बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि यह इस बात का एक और उदाहरण है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पारदर्शिता और अपने कार्यों को लेकर अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही से डरती है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत झांग जुन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन के निराधार अनुरोध को सिरे से खारिज करता है। उन्होंने ट्वीट किया, हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विधेयक चीन का पूरी तरह आंतरिक मामला है। इसका सुरक्षा परिषद के जनादेश से कोई लेना-देना नहीं है। चीनी दूत ने कहा, तथ्य बार-बार यह साबित करते हैं कि अमेरिका दुनिया के लिए संकट पैदा करता है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। चीन अमेरिका से अपील करता है कि वह ताकत दिखाने की राजनीति और धमकाने की आदत से तत्काल बाज आए। उल्लेखनीय है कि चीन ने हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित विधेयक का मसौदा गत शुक्रवार को अपनी संसद में पेश किया था। इसका मकसद पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हांगकांग पर नियंत्रण और मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि एक जुलाई को 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को एक देश, दो विधान के समझौते के साथ चीन को सौंपा था। समझौते की वजह से चीन की मुख्य भूमि के मुकाबले हांगकांग के लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इस बीच, रूस ने चीन के समर्थन में बात की। संयुक्त राष्ट्र में रूप से प्रथम उप स्थाई प्रतिनिधि दमित्रि पोलियांस्की ने ट्वीट किया, हांगकांग पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने का अमेरिका अनुरोध परिषद के जनादेश का दुरुपयोग और महज उकसावे की कार्वाई को दर्शाता है। उन्होंने कहा, हम सदस्य देशों के आंतरिक मामलों पर कभी चर्चा नहीं करते।

हांगकांग में नए कानून के तहत आरोपियों को मुकदमे के लिए चीन नहीं भेजा जाएगा: रिपोर्ट

भाषा। बीजिंग

चीन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हांगकांग में किए अपराधों के आरोपियों को नए सुरक्षा कानून के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए चीन नहीं भेजा जाएगा। हांगकांग स्थित अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को हांगकांग की कानून व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इस कानून में मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपियों को सीमा पार कर चीनी मुख्य भूभाग नहीं भेजा जाएगा। इस नए कानून से चीन की सुरक्षा एजेंसियों को पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति मिल जाएगी।बहरहाल हांगकांग बार एसोसिएशन ने कहा कि चीन का प्रस्तावित नया सुरक्षा कानून अदालतों में दिक्कतों में फंस सकता है क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी के लिए लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस कानून को लेकर हांगकांग में जबरदस्त विरोध हो रहा है। रविवार को हजारों लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शनों में भाग लिया।इससे पहले आरोपियों को मुकदमे के सामने के लिए चीन भेजने वाले हांगकांग सरकार के नियोजित कानून के खिलाफ व्यापक पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे और प्रदर्शनकारियों ने लगभग एक साल तक इस शहर के जनजीवन को अस्त-व्यस्त रखा था।अखबार की खबर में कहा गया है, नए कानून के तहत आरोपियों को हांगकांग में मुकदमे का सामना करना होगा। उन्हें मुकदमे के लिए सीमा पार मुख्य भूभाग नहीं भेजा जाएगा।

हांगकांग में विवादित बिल को लेकर दूसरे दिन सेंट्रल में जारी तनाव के बीच दंगा पुलिस के सामने चलती दिखी एक महिला

बांग्लादेश में फंसे 200 भारतीयों को सड़क मार्ग के जरिए सुरक्षित लाया गया

ढाका। बांग्लादेश में लॉकडाउन के कारण फंसे करीब 200 भारतीयों को सड़क मार्ग के जरिए भारत भेजा गया। बांग्लादेश में फंसे इन भारतीयों में ज्यादातर उत्तर पूर्वी राज्यों के निवासी हैं, जिन्हें तीन सीमा चौंकियों के जरिए भेजा गया। भारतीय उच्चायोग ने यहां बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने अखौरा-अगरतला एकीकृत जांच चौकी का दौरा किया और त्रिपुरा जाने वाले भारतीयों से बातचीत की। उच्चायोग ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की। ट्वीट में कहा गया कि, इसके अलावा, मेघालय से सटी दौकी-तमाबिल सीमा चौकी और असम की सीमा से सटी सुतरकांडी-शिओला चौकी से भी भारतीयों को भेजा गया। भारतीय उच्चायोग ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें घर वापस जाने वाले छात्र बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। उच्चायोग ने वतन वापसी के इच्छुक भारतीयों के लिए अपनी वेबसाइट पर एक लिंक साझा किया था, जहां वह लौटने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

चीन के प्रयासों को रोकने के लिए भारत-अमेरिका को बनानी चाहिए योजना: थिंक टैंक

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पाकिस्तान और श्रीलंका की चरमराती आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उनके साथ संबंध मजबूत कर हिन्द महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे चीन को रोकने के लिए अमेरिका तथा भारत को कोई योजना बनानी चाहिए।

हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत में चिंता है। भारत मुख्यतः चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के उद्देश्य से श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यामां और सिंगापुर सहित क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। थिंक टैंक हडसन इंस्टिट्यूट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से न सिर्फ दक्षिण एशिया में जीवन और आजीविका को खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि यह क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामरिक बदलाव का भी कारण बन सकती है।

● हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से भारत में चिंता है

संस्थान की भारतीय मूल की शोधार्थी अपर्णा पांडे और अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई रिपोर्ट में थिंक टैंक ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाएं तबाही से बच जाएंगी, लेकिन उनकी सरकारों को निवेश को संरक्षण और बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना होगा।

इसमें कहा गया, पाकिस्तान और श्रीलंका संभवतः नकारात्मक वृद्धि की दिशा में चले जाएंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कर्जदाताओं से कर्ज राहत की आवश्यकता होगी। इसके बिना, श्रीलंका के सामने बड़े कर्ज डिफॉल्ट की संभावना है। दोनों देशों के अपने हितकारी के रूप में चीन की ओर देखने की संभावना है जैसा कि उनके नेता कुछ समय से करते प्रतीत हो रहे हैं। रिपोर्ट कोलकाता से लेकर काबुल तक संकट: दक्षिण एशिया में कोविड-19 का प्रभाव के अनुसार चीन दक्षिण एशिया की कर्ज से दबी सरकारों पर अपने लाभ के लिए आदान-प्रदान के तहत दबाव बना सकता है। हडसन इंस्टिट्यूट की इस सप्ताह जारी रिपोर्ट में कहा गया है, यह क्षेत्र में भारत की सुरक्षा और अमेरिका के प्रभाव की कीमत पर होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंध मजबूत कर हिन्द महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे चीन को रोकने के लिए भारत और अमेरिका को कोई योजना बनानी चाहिए।

चीन अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड योजना के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद लेने में लगा है और उसकी इस बात के लिए आलोचना होती रही है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर देशों को अपने फायदे के लिए कर्ज के जाल में फंसा रहा है।रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न खतरे से क्षेत्र के मिलकर काम करने की भारत की पहल को पाकिस्तान तवज्जो नहीं दे रहा है और वह इस चुनौतीपूर्ण समय में भी कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। इसमें उल्लेख किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि पाकिस्तान के पास अपनी सेना को भारत के खिलाफ मजबूत करने के लिए संसाधनों की कमी है, फिर भी वह काफी बड़े देश भारत के खिलाफ अपने को ऊपर दर्शाने के प्रयास के तहत उप-पारंपरिक युद्ध (आतंकवाद) के इस्तेमाल को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के असैन्य और सैन्य नेताओं में भारत विरोधी भावना को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव, खासकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसमें कहा गया है कि विगत में पाकिस्तान ने प्राकृतिक आपदाओं का इस्तेमाल भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए किया है। भारतीय अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पाकिस्तान पागलपन के रूप में कोविड-19 का इस्तेमाल भी ऐसा करने के लिए कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, यद्यपि उपमहाद्वीप में पूर्ण युद्ध होने की संभावना नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास लगातार बाधित रहने की संभावना है।

रूस में कोरोनो वायरस संक्रमण के मामलों में तेज वृद्धि

● संक्रमितों की संख्या के लिहाज से तीसरे नंबर पर देश

भाषा। मास्को

रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के बृहस्पतिवार को आठ हजार 371 नए मामले सामने आए जिससे देश में वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ कर तीन लाख 79 हजार पर पहुंच गई। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में रूस अमेरिकी और ब्राजील के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। रूस सरकार के कोरोना वायरस निरोधक कार्यबल ने बताया कि बृहस्पतिवार को कोरोना संक्रमण के देश भर में आठ हजार 371 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा कल के बराबर है और इस महीने की शुरूआत में एक दिन में आए सर्वाधिक ग्यारह हजार मामलों से कम है। अधिकारियों ने बताया कि ताजा मामलों के साथ ही देश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 379,000 पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस के आंकड़ों के लिहाज से रूस अब दुनिया भर में अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि देश भर में कोरोना के कारण 174 और लोगों की मौत हुई।

पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 61 हजार के पार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,076 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61 हजार का आंकड़ा पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस खतरनाक वायरस से 36 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,260 तक पहुंच गई है। संक्रमण के 2,076 नए मामलों के साथ ही देश भर में संक्रमण के कुल मामले 61,227 पहुंच गए हैं। सिंध प्रांत में सबसे ज्यादा 24,206 मामले हैं। इसके बाद पंजाब में 22,037, खैबर पख्तूनख्वा में 8,483, बलूचिस्तान में 3,616, इस्लामाबाद में 2,015, गिलगित-बाल्टिस्तान में 651 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 219 मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 20,231 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या एक लाख के पार

भाषा। वाशिंगटन

पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस ने अमेरिका में सबसे भयंकर तबाही मचाई है जहां इस वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों की संख्या एक लाख को पार कर गई है। दुनिया में किसी भी अन्य देश में कोविड-19 के कारण इतने अधिक लोगों की मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचा रखी है, जनजीवन ठहर सा गया है और आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं।

अमेरिका में एक तिहाई लोगों की मौत दुनिया की वित्तीय राजधानी माने जाने वाले न्यूयॉर्क, उसके नजदीकी इलाके न्यूजर्सी और कनेक्टिकट में हुई हैं। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, यहां मंदी आ गई है और बीते तीन महीने में 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि मृत्यु दर और नए मामलों की संख्या में अब कमी आने लगी है। इसे देखते हुए लगभग सभी 50 राज्यों ने

अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने की हिम्मत जुटाई है। सदन में बहुमत के नेता स्टेनी होयर ने कहा, कोविड-19 के कारण 1,00,000 वें अमेरिकी व्यक्ति की मौत हो गई। ऐसे में हमारा देश एक दुखद मुकाम पर है। पूरे देश में, इतने परिवार इस बीमारी के कारण अपने प्रियजनों को खोने के दुख में डूबे हैं। जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के मुताबिक बुधवार को अमेरिका में मृतकों की संख्या एक लाख को पार कर गई है। होयर ने कहा, इस त्रासदी का असर कितना होगा यह अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जान गंवाने वाले इन एक लाख लोगों में कोई माता-पिता होगा, कोई दादा-दादी या नाना-नानी, भाई या बहन, बच्चा और हमारे मूल्यवान समुदाय का सदस्य होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मृतक संख्या कोरियाई युद्ध के बाद से हर संघर्ष में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या से भी ज्यादा है। यह 1968 में अमेरिका में फ्लू महामारी में मारे गए लोगों की संख्या के बराबर है और उससे भी एक दशक पहले एक अन्य फ्लू महामारी से मरने वालों के 1,16,000 के आंकड़ों के करीब पहुंच रहा है। अब तक 17 लाख अमेरिकी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम संबंधी अमेरिकी केंद्र (सीडीसी) के मुताबिक देश में इस संक्रमण ने हर आयुवर्ग और हर समुदाय को अपनी चपेट में लिया है। संक्रमण के कुल मामलों में से 4.7 एशियाई अमेरिकियों के और 26.3 फीसदी अश्वेत अमेरिकियों के हैं। संक्रमण के कारण यहां कितने भारतीय-अमेरिकी लोगों की मौत हुई इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछ अनाधिकारिक अनुमानों की मानें तो न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में ऐसे 500 से अधिक लोगों की मौत हुई तथा इस समुदाय के संक्रमित लोगों की संख्या हजारों में है। बीते दो महीनों में कई जाने माने भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक एवं प्रभावशाली सामुदायिक नेताओं की संक्रमण के कारण मौत हुई। अमेरिका ने जांच बढ़ा दी है। सीडीसी ने कहा कि अब तक अमेरिका में 1.57 करोड़ लोगों की जांच की गई है जिनमें से 18 लाख संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण के सर्वाधिक 5,00,000 से अधिक मामले 18-44 आयु वर्ग में है जिसके बाद 4,50,000 से अधिक मामले 45-64 आयु वर्ग में हैं।

अमेरिकी कांग्रेस ने जातीय अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई को लेकर चीन पर प्रतिबंधों को दी मंजूरी

वाशिंगटन। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर पहले से ही चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी संसद ने जातीय अल्पसंख्यकों पर नृशंस चीनी कार्वाई को लेकर अपना रुख कड़ा करने के समर्थन में मतदान किया है। सदन में बुधवार को द्विदलीय विधेयक पारित किया गया जिसके तहत पश्चिमी शिंजियांग क्षेत्र में उइगर एवं अन्य जातीय समूहों की व्यापक निगरानी और उन्हें नजरबंद रखने में शामिल चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात की गई है। इस विधेयक को सीनेट में पहले की पारित किया जा चुका है और अब इसे कानून में बदलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। ट्रम्प ने इस सप्ताह कहा था कि वह इस विधेयक पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों पाटियों के सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान करते हुए इसे एक के मुकाबले 413 मतों से पारित कर दिया। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने और हांगकांग में नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की चीनी योजनाओं के खिलाफ पहले से ही तनाव चल रहा है। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने विधेयक के समर्थन में संसद में कहा, उइगर लोगों के खिलाफ बीजिंग की बर्बरतापूर्ण कार्वाई दुनिया की अंतरात्मा तक को हिला देने वाली है।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 मई 2020

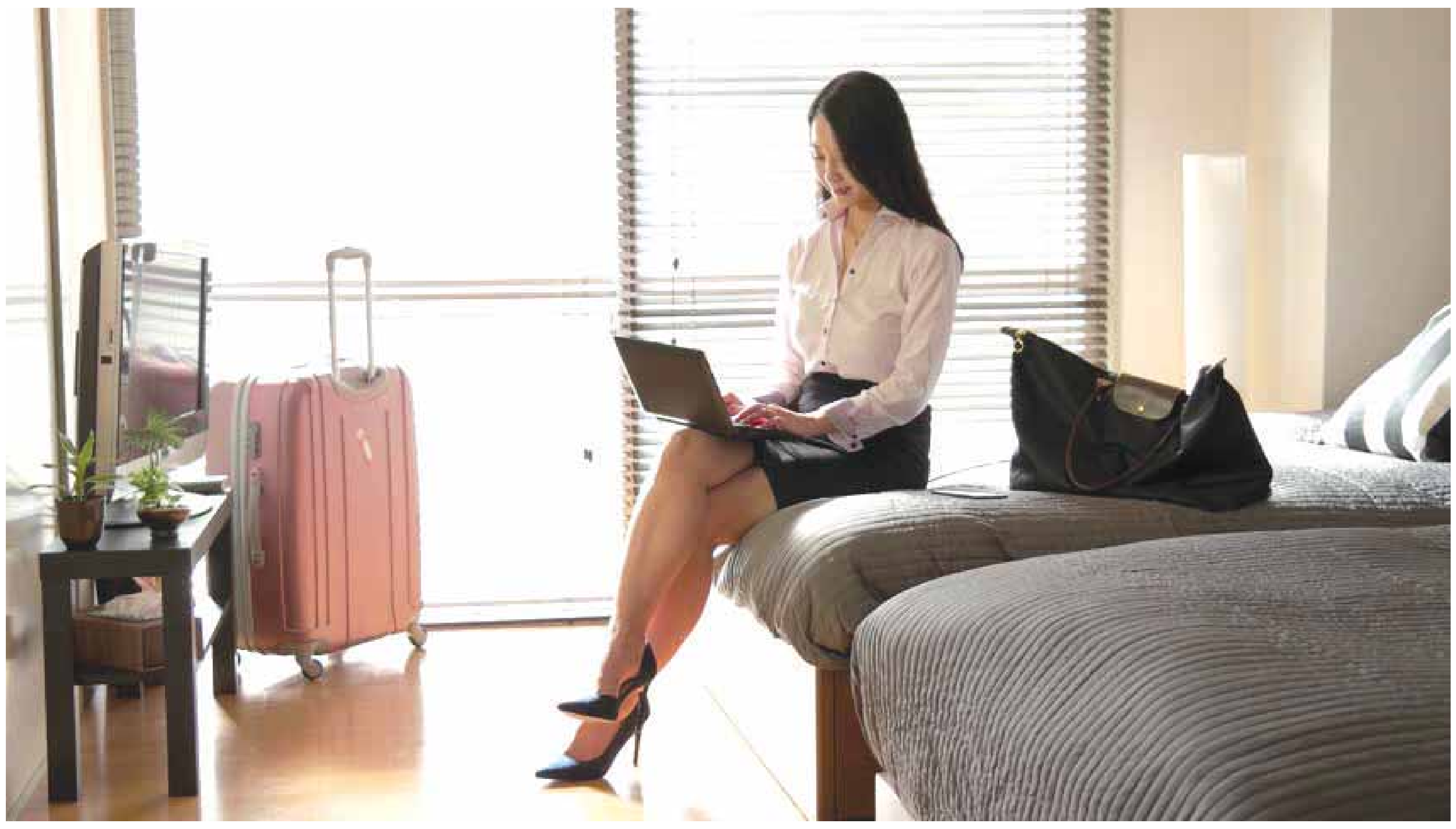

विमान यात्रा परिदृश्य में होंगे व्यापक परिवर्तन

क्या एअरलाइन्स द्वारा स्वचालित तंत्र बनाने, यात्रियों की संख्या कम करने और विमान परिचारिकाओं तथा क्रू सदस्यों की यूनिफॉर्म में व्यापक परिवर्तन करने मात्र से ही एक बंद स्थान पर बैठने और 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होने संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सकता है, प्रश्न कर रही हैं पायनियर संवाददाता साक्षी शर्मा...

महीनों घरों में बंद रहने, छुट्टियों में बाहर घूमने की पुरानी एलबम के पन्ने पलटते हुए हम सभी उड़ने के लिए बेचैन थे और सोचा करते थे कि कब ऐसा हो सकता है? ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुन ली गईं और अब सुनने में आया है कि उड़ाने प्रारंभ की जा रही हैं। जैसा कि दूसरे विषयों में होता है इस बार उड़ानों और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं में भी कोरोना वायरस से बचने के उपायों से जुड़े व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं।

अब पूर्व से भिन्न व्यवस्था बनाते हुए चेक-इन तथा विमान पर चढ़ने और बैठने की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना होगा।

अत: ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एअरपोर्ट के रास्ते में ही हों और आपके फोन पर एक संदेष आ जाए कि आपका वेब चेक-इन पूरा किया जा चुका है और आपके लिए बोर्डिंग पास भी प्रिंट कर दिया गया है। आपके एअरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको एक थर्मल स्कैनिंग करानी होगी और आपके मोबाइल पर आरोग्य सेतु एम में भी यह दिखना चाहिये कि आप 'कोविड 19' से मुक्त हैं। आपके लिए एअरपोर्ट के द्वार खुल जाएंगे और आप एअरपोर्ट के भीतर आ जाएंगे। आप द्वारा बोर्डिंग पास को स्कैन कराने के बाद अपनी आईडी को डिजिटली वेरिफाई कराना होगा। आप अपने बैगेज़ टैग को भी ऑनलाइन प्रिंट करके अपने बैगेज के साथ नत्थी कर सकते हैं। जी नहीं, हम सुदूर भविष्य की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा ही अब आपको वर्तमान में देखने को मिलने वाला है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था की योजना बना ली गई है।

लेकिन इतनी सावधानियां रखने के बाद भी आपकी चिंताएं कम नहीं हो रहीं क्योंकि चारों ओर अनिश्चितता फैली हुई है। हम सभी के मन में कई प्रश्न उठते रहते हैं और हम सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चिंतित अनुभव करने से लेकर बंद स्थान में बैठने और 14 दिन के क्वारंटीन या एकांतवास से लेकिन यात्रियों को अपनी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं दिखाई देता।

मनोचिकित्सक अरुनीत सभरवाल 'द हैप्पी ट्री' नाम से एक क्लिनिक चलाते हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के विषय में अनिष्चितता होने के कारण लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। इससे लोगों के मन में एक प्रकार का भय व्याप्त हो गया है क्योंकि व्यक्ति को किसी भी काम से सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर वायरस संक्रमण का जोखिम रहता है। उनके अनुसार, 'इससे यात्रियों की चिंता बढ़ती है क्योंकि चाहे ऑन-लाइन चेक-इन आ जाए, लेकिन विमान पर साथ बैठने और यात्रियों से संक्रमण होने से एक दूसरे में चिंता का होना स्वाभाविक है।'

कोरोना संक्रमितों की संख्या में होने वाली वृद्धि से लोग अपने घरों से बाहर जाने से ही हिचक रहे हैं, उनके लंबी यात्रा पर जाने को तो भूल ही जाइये। ईज़ माई ट्रिप, के मुख्य कार्यकारी तथा संस्थापक निशांत पट्टी का कहना है, 'यात्रा के समय यात्रियों का घबराना स्वाभाविक है। लेकिन उनकी इसी घबराहट के कारण सभी यात्री अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।' सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सभी आवष्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। हम उनका सहयोग करने के लिए सभी प्रकार के नवीनतम निर्देशों को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जेटसेटगो एवियेशन, कंपनी की मुख्य कार्यकारी तथा संस्थापक कणिका टेकरीवाल ने बताया कि यात्रा विकल्पों के चुनाव के समय अब लोग अधिक भिज्ञ और सावधान हो गए हैं।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दिये गए निर्देशों में कई मानक निर्देश दिये गए हैं जिन्हें यात्री की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है और उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिये।

वर्तमान में केबिन क्रू और सुरक्षा कर्मचारियों को ही पीपीई किट पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन भविष्य में सभी लोगों के लिए इसे पहनना अनिवार्य किया जा सकता है क्योंकि यात्रियों के आपसी संकर्प की अनदेखी नहीं की जा सकती, विशेषकर जब स्थान चारों ओर से बंद हो। क्या सभी के लिए इसे पहनना जरूरी करना कुछ अधिक की अपेक्षा करना माना जा सकता है। ये व्यावहारिक नहीं लगता क्योंकि विमान में यात्री को चाहे केवल 2 घंटे ही बैठना पड़े लेकिन उसे इस पीपीई किट को लगभग 6 घंटे पहने रहना होगा। इन्हें पहनना असुविधाजनक होने के साथ ही इसे पहनने से पसीना आता है और खुली हवा नहीं मिलती। ऐसे में सभी यात्रियों द्वारा इस किट को छ: घंटे धारण करना और वो भी तब जब हवाई यात्रा में उस बंद स्थान में जहां हवा के दबाव में निरंतर परिवर्तन होते रहते हों, सभी को एक दूसरे से सट कर बैठना होगा, ये विकल्प व्यावहारिक नहीं लगता।'

लेकिन कनिका का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में यात्रियों तथा क्रू सदस्यों की सुरक्षा हेतु पीपीई किट एक व्यावहारिक विकल्प है। एअरपोर्ट तथा विमान के भीतर पीपीई सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है और इससे सभी चेकप्वाइंट पर एक दूसरे से संक्रमण होने को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया, 'हम ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित कर रहे हैं जिनके माध्यम से यात्री तथा क्रू सदस्यों की यात्रा सुरक्षा के साथ सुनिश्चित की जा सकेगी। लेकिन अभी तक हवाई यात्रियों को किट उपलब्ध कराने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका है। हम विमान पर सीटों की संख्या में कमी, क्रू सदस्यों की यूनिफॉर्म में संशोधन, यात्रियों द्वारा संपर्क के स्थानों कमी के साथ ही एफएंडबी मानकों में भी परिवर्तन कर रहे हैं।'

निशांत ने बताया, 'यदि हम सरकार द्वारा दिये गए सभी निर्देशों का अनुपालन भी करें तो हम वायरस के प्रसार में कमी ही ला सकते हैं, इसे समाप्त नहीं कर सकते।'

हवाई यात्री के साथ एक और चुनौती गंतव्य नगर में अनिवार्य एकांतवास पर रहना है। इसके बाद जब वो लौटेंगे तब भी उन्हें अपने गृहनगर में क्वारंटीन रहना होगा। परम आवश्यक न हो तो कोई भी यात्रा नहीं करेगा क्योंकि 28 दिन का समय अत्यंत लंबा होता है। वैसे ये व्यवस्था कितने दिन रह सकती है? निशांत का कहना है कि हर राज्य आज अपने अनुसार क्वारंटीन संबंधी निर्देश निर्गत कर रहा है। इसके कारण हवाई यात्रा अव्यावहारिक बनती जा रही है। उन्होंने कहा, 'वे अब हवाई यात्रा पर निकट दृष्टि रख रहे हैं। ये निर्देश लंबे समय तक बने नहीं रह सकते। इन्हें पूरे देश को ध्यान में रखते हुए ढीला तथा तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये।'

इस महामारी ने हमारे जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन किये हैं। कनिका ने बताया, 'यात्रा के समय की चुनौतियों को देखते हुए सभी की सुरक्षा परम आवश्यक है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक नई सामान्य परिस्थिति का सृजन करना होगा। ये हमारे और समस्त समुदाय के लाभ के लिए तथा कोरोना ग्राफ को सही स्थान पर रखने के लिए आवश्यक है।'

उड़ान के तकनीकी पक्ष तथा सुनहरे पक्ष की ओर इंगित करते हुए निशांत ने बताया, 'यदि हम वायरस के प्रसार के तकनीकी पक्ष को देखें तो ये वायरस या तो संपर्क या वायु में उपस्थित एअरोसोल के माध्यम से फैलता है। संपर्क के माध्यम से प्रसार को रोकने के लिए एअरलाइन हर उड़ान के बाद विमान यात्री द्वारा छुए सभी स्थानों को सैनिटाइज़ करेगी। इससे वायरस को संपर्क के माध्यम से फैलने से रोका जा सकेगा। वायुयानों में स्थापित एअर क्लीनसिंग सिस्टम हवा द्वारा वायरस के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। विमान के भीतर की वायु तीन कारणों से अत्यंत स्वच्छ होती है। प्रथमत: हर सीट को नीचे की ओर एक मीटर प्रति सेकेंड की गति पर धोया जाता है, हवा को ऊपर से नीचे की ओर करके सफाई की जाती है और धूल को फर्श से ही एकत्र कर लिया जाता है। इसमें साइड से कोई हवा नहीं होती। दूसरी बात ये है कि वायुयान में हर तीन मिनट पर वायु को रिसाइकल किया जाता है। भीतर की हवा में फिल्टर हवा के साथ ही बाहरी वातावरण की हवा होती है। बाहर से खींची गई हवा ठंडी, प्रदूषित तथा सूखी होती है और इसका रिसाइकल होता रहता है। अंतत: वायु को हीपा फिल्टरों द्वारा छाना जाता है जिसके बाद वायु अत्यंत शुद्ध हो जाती है। इससे 99.90 से अधिक कण बाहर हो जाते हैं और इससे ही कोरोना के बड़े आकार के वायरस के कण भी छन जाते हैं। इन कारकों के चलते विमान के भीतर की वायु अत्यंत स्वच्छ हो जाती है और एअरोसोल के माध्यम से संक्रमण की संभावना को कम से कम किया जा सकता है।'

वो बताते हैं कि ग्राहकों की चिंता और भय का भी समाधान किया जाता है। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि यात्रियों की चिंताओं को दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। डा. अनुनीत ने इस चिंता को कम करने के लिए कुछ टिप्स दी हैं। उन्होंने बताया, 'हम उन कदमों को उठाते हैं जो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा संस्तुत किये जाते हैं जैसे कि आप बार बार हाथ धोंए, अपने चेहरे, आंख और नाक को गंदे हाथों से छूने से बचें तथा सदैव मास्क पहने तथा खांसते समय मुंह पर कपड़ा रखें। यदि हम बचाव के सभी जतन करें और सावधानी रखें तो हम चिंता को कम कर सकते हैं। चिंतित होने पर अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों से रोग, इसकी संख्या तथा मृत्यु की संख्या के बारे में न बात करके रोचक विषयों पर बात करें। एक स्वास्थ्यकारी दिनचर्या का पालन करें। शोधों से निकले निष्कर्ष के अनुसार कलुषित जीवन प्रणाली के कारण चिंता में वृद्धि होती है जबकि पर्याप्त नींद लेने, स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करने से इसे कम करने में सहायता मिलती है। चिंतित होने पर हम सभी को विमान में सवार होने से पहले गहरी श्वांस लेने जैसे प्राणायाम तथा तनावमुक्त करने वाली तकनीकों को अपनाना चाहिये।'

कोविड के बाद के मॉडलों पर चलते हुए सभी एअरलाइनों को परिस्थितियों के अनुसार ऐसे त्वरित परिवर्तन करने होंगे जो यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से सुसंगत हों। उन्होंने बताया, 'डिलिवरी प्रक्रिया के हर बिंदु का हर बिंदु का संज्ञान ले लिया गया है। एसओपीज़ की उपयोगिता को परखने के लिए विभिन्न मॉकड्रिल की गई हैं तथा उनसे मिली सीखों को एसओपीज़ में समायोजित भी किया गया है। हमनें यात्रियों, उनके बैगेज, कैटरिंग तथा विमानों के भीतर की व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से हम यात्रियों से बात करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से हमारे साथ यात्रा करना चाहेंगे। यात्रियों तथा देश के कुछ चिकित्सकों से मिले सुझावों को अपनाया जाता है। इसके अलावा हम एअरपोर्ट द्वारा विकसित किये गए सुरक्षा प्रक्रियाओं का भी संज्ञान ले रहे हैं।' कनिका ने बताया कि हम इस समय का सदुपयोग जीने और उड़ने के नए तरीकों को जानने में कर रहे हैं।

हर प्रकार के सुरक्षा प्रयासों को अपनाने के बाद भी हमारे समक्ष कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर ढूंढने होंगे जैसे-हम किस प्रकार से अवकाशों के संबंध में योजना बना सकते है? हम किस प्रकार की बैठकें कर सकते हैं, क्या केवल आभासी बैठकें? अब यात्रा किस प्रकार की रहने वाली है? इसके अलावा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या हम संक्रमित होने की जोखिम पर यात्रा करना चाहेंगे?

कोविड 18 का टीका आ जाने के बाद भी यात्रियों के लिए आवश्यक तथा अवकाष यात्रा की सामान्य योजना बनाकर निकलने में अभी काफी समय लगने वाला है।

मुश्किल वक्त में लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूं : माधुरी दीक्षित

भाषा। मुंबई

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने ने कैंडल गीत के साथ हाल ही में गायिकी में हाथ आजमाया है और उन्होंने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौर में लोगों को अच्छा महसूस कराना चाहती हैं। अभिनेत्री-प्रोड्यूसर ने कहा कि यह गीत उम्मीद और सकारात्मकता के बारे में है। माधुरी ने एक साक्षात्कार में पीटीआई-भाषा से कहा, कई लोग हैं जो घर पर बैठ नहीं सकते और वे कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जब मैं उनकी तरफ देखती हूं तो मुझे लगता है कि उनके सामने मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं है। मुझे दुख होता है। मैं जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करती हूं। उन्होंने कहा, एक कलाकार के तौर पर यह लोगों की मदद करने का तरीका है। मैं इस गीत से प्रेरित करके उनकी मदद करने की कोशिश कर सकती हूं। अगर एक कलाकार के तौर पर मैं उन्हें जिंदगी को लेकर अच्छा महसूस करा सकती हूं तो मैं यह करना चाहूंगी। नृत्य और संगीत हमेशा से माधुरी की जिंदगी का हिस्सा रहा है लेकिन अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें फिल्मों में अपने करियर और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कभी अपने गायन के कौशल को बेहतर करने का वक्त नहीं मिला। अभिनेत्री ने कहा, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम उम्र में कदम रखा था और फिर मैं व्यस्त हो गई। उस समय सारा ध्यान अभिनय और नृत्य पर था और गायिकी कहीं पीछे छूट गई। मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। उन्होंने कहा, जब मुझे अपने लिए वक्त मिला तो मुझे लगा कि शायद यह समय है जब मैं वास्तव में गा सकती हूं। यह अपने आप को व्यक्त करने का एक अन्य तरीका है। मैं भविष्य में और गाना चाहूंगी। अभिनय के क्षेत्र में माधुरी (53) नेटफ्लिक्स पर ड्रामा-थ्रिलर सीरीज से डिजिटल मंच पर पदार्पण करने जा रही हैं। करण जौहर के प्रोडक्शन तले बनने वाले इस कार्यक्रम की शूटिंग हाल ही में लॉकडाउन के कारण रोक दी गई थी। अभिनेत्री आखिरी बार 2019 में आई करण जौहर की फिल्म कलंक में दिखाई दी थीं।

कियारा आडवाणी ने हेलो पर किया डेब्यू

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी ने क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हेलो पर डेब्यू कर लिया है। कियारा ने कहा, क्षेत्रीय सोशल मीडिया की ताकत के चलते, हमें अपने प्रशंसकों से मिलने, उनके करीब आने और व्यक्तिगत रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। हम बड़े पर्दे पर जो प्रदर्शित करते हैं, यहां हमें उससे अलग अपने जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं को उनकी मनपसंद भाषा में प्रदर्शित करने में मदद मिलती है। मैं हेलो में शामिल होने और समान विचारधारा वाले लोगों से भरे प्लेटफॉर्म पर असाधारण कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हूं। मुझे यकीन है कि यह सफर मजेदार और मनोरंजक होने वाला है। हेलो प्लेटफॉर्म पर श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, कृति सेनन, सारा अली खान, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, शिल्पा शेट्टी, विजय देवरकोंडा, मिमी चक्रवर्ती, बादशाह, तमन्ना, गुरु रंधावा, एआर रहमान, रकुल प्रीत भसह, योयो हनी भसह जैसी मशहूर हस्तियों शामिल हैं।

जोया मोरानी ने दूसरी बार किया प्लाज्मा डोनेट

बॉलीवुड फिल्मकार करीम मोरानी की पुत्री जोया मोरानी ने कोरोना संक्रमित लोगों की मदद के लिये दूसरी बार प्लाजमा डोनेट किया है। निर्माता करीम और उनकी दोनों बेटियां शजा मोरानी और जोया मोरानी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। हालांकि, इस बीमारी को मात देने के बाद तीनों स्वस्थ होकर बाहर आ चुके हैं। इस बीमारी के दौरान का अनुभव जोया ने साझा किया था और आज वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर नेक काम कर रही हैं। कोरोना से जंग लड़कर बाहर निकले लोगों का प्लाज्मा इस महामारी के खिलाफ मददगार साबित हो रहा है। ऐसे में कोरोना को मात दे चुकी एक्ट्रेस जोया मोरानी प्लाज्मा डोनेशन के लिए दूसरी बार आगे आई हैं। जोया ने प्याज्मा डोनेट करते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा कि प्लाज्मा डोनेशन का राउंड दो। पिछली बार जब डोनेट किया था तो एक मरीज आईसीयू से बाहर आ गया था। मेरे डॉक्टर ने कहा था कोरोना को मात दे चुका यदि व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करेगा तो किसी ना किसी को मदद मिलेगी।

बांग्लादेशी गायक के खिलाफ मामला दर्ज

प्रधानमंत्री को अपमानित करने का मामला

भाषा। अगरतला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानित करने के सिलसिले में संगीत रियलिटी शो सा रे गा मा पा से प्रसिद्धि पाए बांग्लादेशी गायक मैनुल अहसान नोबेल के खिलाफ त्रिपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह शिकायत दक्षिण त्रिपुरा जिले के बेलोनिया शहर के रहने वाले एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। वह गुजरात के गांधी नगर में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का छात्र है। यह शिकायत सुमन पॉल नामक व्यक्ति ने 25 मई को दर्ज कराई। पॉल ने संवाददादताओं को बताया कि नोबेल बांग्लादेश में भी कोई लोकप्रिय गायक नहीं है। उन्हें उस देश के श्रोताओं ने हमेशा खारिज किया है। उन्होंने टीवी संगीत रियलिटी शो सा रे गा मा पा में कोलकाता में हिस्सा लिया, पैसे कमाए, नाम कमाया और वापस बांग्लादेश चले गए। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो यह कत्तई स्वीकार्य नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेलोनिया के पुलिस अधीक्षक जल सिंह मीणा ने इस बात की पुष्टि की कि शिकायत दर्ज की गई है और इसे त्रिपुरा पुलिस के साइबर अपराध प्रकोष्ठ को भेजा दिया गया है। यह मामला भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं एवं अन्य कानून के तहत दर्ज किया गया है। बेलोनिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी राजीव दत्ता ने बताया कि शिकायत के अनुसार, बांग्लादेशी गायक ने फेसबुक पोस्ट में मोदी को मामूली चायवाला बताकर उनका अपमान किया है।

पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी भूमि पेडनेकर

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहती हैं। भूमि पेडनेकर अब पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहती हैं। इस काम को पूरा करने के लिए भूमि पेडनेकर ने भामला फाउंडेशन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए सभी से पर्यावरण को बचाने की अपील की है। भूमि ने वीडियो में बताया है कि हर विलुप्त हो रहीं प्रजातियों को बचाना होगा, हमें उनके अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। भूमि ने कहा कि इस धरती पर 80 लाख से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। इंसान, पेड़, जानवर, वायरस, समुद्री जीव सब इस धरती पर निवास करते हैं। इन जीव जंतुओं को धरती पर जीने का उतना ही अधिकार है जितना किसी इंसान को है। भूमि ने वीडियो के जरिए सभी से अपील की है कि पर्यावरण दिवस पर हर कोई धरती की रक्षा करने की ठाने।